असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

13 मार्च, 2018

षोडश विधान सभा 13 मार्च, 2018 ई0

---------- मंगलवार, तिथि ----------

नवम् सत्र 22 फाल्गुन, 1939(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । प्रश्नोत्तर काल ।

(इस अवसर पर राजद के सभी माननीय सदस्यगण अपने अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने लगे)

समय पर उठाइयेगा । समय पर कहियेगा ।

(व्यवधान)

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, मुख्य सचिव के उपर बहुत ही गंभीर आरोप हैं । महोदय, मुख्य सचिव पर गंभीर आरोप हैं और उस पद पर वे अभी तक बने हुए हैं और सरकार उनको संरक्षण दे रही है ।

(व्यवधान)

महोदय, मुख्य सचिव पर बहुत ही गंभीर आरोप हैं और अभी तक वे इस पद पर बने हुए हैं और सरकारी खजाना को लूट रहे हैं और सरकार उनको संरक्षण दे रही है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप समय पर उठायेगा, अभी प्रश्नकाल है....

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, मुख्य सचिव पर बहुत ही गंभीर आरोप है और माननीय मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचारियों को एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दे रहे हैं । वे बिहार की गाढ़ी कमाई को लूट रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जाय और उनके नेतृत्व में बिहार नहीं चलना चाहिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अभी तो आपका समय है, माननीय सदस्यों का समय है, अभी तो प्रश्नकाल चलने दीजिए ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, जो मामले आ रहे हैं, उसको आपके संज्ञान में देना चाहते हैं और वह मैंने संज्ञान में दे दिया । बिहार के मुख्यमंत्री ऐसे भ्रष्टाचारियों से बिहार की गाढ़ी कमाई को लुटवा रहे हैं ।

अध्यक्ष : ठीक है, बैठिए । अब प्रश्नकाल चलने दीजिए । माननीय सदस्यगण, कोई पदाधिकारी कितना भी उंचा हो, यह सदन तो माननीय सदस्यों का है और इस सदन के लिए माननीय सदस्य ज्यादा महत्वपूर्ण हैं । अभी का काल माननीय सदस्यों का होता है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि अभी प्रश्नकाल चलने दीजिए । अल्पसूचित प्रश्न संख्या-18, श्री श्याम रजक ।

(व्यवधान)

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी के साथ अन्याय होने जा रहा है ।

अध्यक्ष : भाई वीरेन्द्र जी, इनके साथ अन्याय जो भविष्य में होने वाला है, उसकी चर्चा कर अभी क्यों उनपर अन्याय कर रहे हैं ।

प्रश्नोत्तर-काल

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-18(श्री श्याम रजक)

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पटना जिला के फुलवारी प्रखंड के सकरैचा पंचायत के प्राथमिक विद्यालय, चुनौती कुआँ में सात सेट डेस्क एवं बेंच उपलब्ध है तथा प्राथमिक विद्यालय, सलारपुर के बच्चे टाट पट्टी, दरी पर बैठकर पढ़ते हैं । वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में बेंच, डेस्क के क्रय हेतु कुल राशि 2 अरब 6 करोड़ 70 लाख रूपये की स्वीकृति दी गयी थी । राज्य के वैसे प्रारंभिक विद्यालय जहां बेंच, डेस्क की समस्या है, के समाधान हेतु कार्य योजना बनाने का निदेश बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को दिया गया है ।

श्री श्याम रजक : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 2 अरब रूपया दिया गया है, हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि दो अरब रूपया किन-किन स्कूलों में या कितने जिला में गया और उससे बेंच और टेबुल खरीदा गया कि नहीं खरीदा गया, यह बतायें ?

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : महोदय, यह राशि वर्ष 2014-15 में निर्गत की गयी थी और उससे अधिकांश विद्यालय में डेस्क और बेंच की खरीद हुई लेकिन काफी समय हो गया, बेंच और डेस्क की जरूरत कई विद्यालयों में अभी भी है और हमलोगों ने उसके लिए एक कार्य योजना बनायी है, निश्चित रूप से समय-सीमा के अन्दर जो आपने बताया है, जिन विद्यालयों की चर्चा की गयी है, वहां उसको उपलब्ध करा देंगे ।

श्री श्याम रजक : नहीं-नहीं महोदय । मैंने उस विद्यालय के साथ-साथ कहा है पूरे बिहार के संबंध में । फुलवारी में ही 220 प्राथमिक विद्यालय है, मध्य विद्यालय 85 है,

उच्च विद्यालय 17 है, उच्च विद्यालय में तो व्यवस्था हो जाती है, मध्य विद्यालय में ये देते हैं 12 हजार रूपया टेबुल, कुर्सी के लिए प्रति साल और प्राथमिक विद्यालय में सात हजार रूपया चटाई खरीदने के लिए देते हैं तो माननीय मंत्री जी कैसे कह रहे हैं कि हम टेबुल, कुर्सी व्यवस्था करा देंगे । माननीय मंत्री जी बतायें कि कार्य योाजना जब बनाये हैं तो कार्य योजना क संबंध में विस्तृत रूप से बताने का काम करें कि कबतक बेंच, टेबुल बिहार के सभी स्कूलों में व्यवस्था हो जायेगी?

टर्न-2/शंभु/13.03.18

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : महोदय, यह वित्तीय वर्ष तो समाप्त हो रहा है, अगले वित्तीय वर्ष में हमारी कोशिश होगी कि हम सभी विद्यालयों में बहुत समय रहते इसको उपलब्ध करा देंगे ।

श्री सदानन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने हेतु-हेतु मद्भूत का उत्तर दे दिया ।

अध्यक्ष : अगले वित्तीय वर्ष की बात कहे हैं ।

श्री सदानन्द सिंह : नहीं-नहीं, हम यह पूछना चाहते हैं कि क्या माननीय मंत्री जी ने राज्य स्तर पर इसकी समीक्षा करवायी है कि कितने बेंच, डेस्क प्राइमरी से लेकर उच्च विद्यालय तक में आवश्यकता है और उसके लिए कितनी राशि की आवश्यकता होगी ?

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : महोदय, मैंने कहा कि इसके लिए एक कार्य योजना विस्तृत...

अध्यक्ष : आप माननीय मंत्री जी, माइक पर सीधे बोलिये, बोलते समय उधर नहीं घूमिये नहीं तो आवाज घूम जाती है ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : इसके लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा रही है और माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है उसके आलोक में हमारी कोशिश होगी कि हम जितना जल्दी सभी विद्यालयों में बेंच और डेस्क की व्यवस्था कर दें ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो 2018-19 का बजट है उसमें 32 हजार करोड़ रूपया शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया है । जो 2017-18 की तुलना में 7 हजार करोड़ रूपया ज्यादा है । यह 2017-18 में 25 हजार करोड़ के करीब था और 2018-19 में 32 हजार करोड़ रूपया है । यह जो.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बोलने क्यों नहीं देते हैं ?

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसीलिए जो माननीय मंत्री ने कहा उसकी कार्य योजना बनायी जा रही है और सर्वशिक्षा अभियान से जो पैसा मिलता है, उसका एनुवल एक्शन प्लान बनता है । उस एक्शन प्लान के अन्तर्गत उसमें सारे प्रावधान किये जाते हैं तो 2018-19 की जो पूरी योजना है उसकी तैयारी हो रही है और वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के बाद केन्द्र सरकार की जो एक कमिटी है सर्वशिक्षा अभियान और बाकी का बैठकर उसके अनुसार उसकी कार्य योजना बनायी जायेगी । सदन को हम इतना ही आश्वस्त करना चाहेंगे कि एक वित्तीय वर्ष में संभव नहीं है । इसमें समय लगता है बारी-बारी से क्रमबद्ध तरीके से होगा, लेकिन राज्य सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है और समस्या का समाधान करने के लिए हमलोग कार्रवाई करेंगे ।

श्री सदानन्द सिंह : माननीय उप मुख्यमंत्री जी के उत्तर से ही एक प्रश्न उठता है । ठीक कहा माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कि एक वर्ष में यह संभव नहीं है । हम माननीय उप मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि क्या इसके लिए दो वर्ष या तीन वर्ष की समय सीमा निर्धारित की गयी है, कब तक ?

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : कार्य योजना बनने पर मालूम पड़ेगा कि दो साल या तीन साल लगेगा, लेकिन राज्य सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है कि सभी स्कूलों में बेंच डेस्क की व्यवस्था की जाय ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-19(श्री (मो0)आफाक आलम)

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत 1128 मदरसा एवं 531 संस्कृत विद्यालयों का विभागीय संकल्प संख्या-970, दिनांक-31.08.13 द्वारा छठा पुनरीक्षित वेतनमान संरचना के अनुरूप अनुदान का लाभ दिया जा रहा है एवं राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत 1128 मदरसा एवं 531 संस्कृत विद्यालय में कार्यरत कर्मियों को सातवां वेतनमान संरचना के अनुरूप अनुदान का लाभ दिये जाने हेतु अपेक्षित कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

श्री मो0आफाक आलम : महोदय, हम पूछना चाहते हैं कि यह जो प्रक्रियाधीन है फिर उसके साथ और शिक्षक को मिल रहा है तो इनको क्यों नहीं मिलेगा सर ?

अध्यक्ष : आप पूरक पूछ लीजिए न ।

श्री मो0आफाक आलम : पूरक ये है कि उनको मिलना चाहिए ।

अध्यक्ष : नहीं तो सदानन्द बाबू तैयार हैं पूछने दीजिए ।

श्री सदानन्द सिंह : क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि संस्कृत और मदरसा के शिक्षकों के साथ जो वेतन की विसंगति है उसको एक समय सीमा के अंदर कब तक आप वेतन उस विसंगति को दूर करना चाहते हैं ?

अध्यक्ष : माननीय सदानन्द बाबू, यह तो छठे और सातवें वेतनमान की बात है आप वेतन विसंगति कहां से ले आये । वेतनमान तो लागू होता है....

श्री सदानन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह वेतन विसंगतियां भी हैं इसमें संस्कृत और मदरसे को अन्य शिक्षकों की तुलना में कम वेतन दिये जाते हैं ।

अध्यक्ष : वही तो कह रहे हैं और इसमें विसंगति की बात नहीं की गयी है, वही बात तो हम कह रहे हैं । कम और अधिक की बात अलग है अभी छठा वेतनमान और सातवां वेतनमान की बात है । इसलिए माननीय मंत्री बताइये सातवें वेतनमान की बात ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : सातवां वेतनमान का लाभ देने की प्रक्रिया चल रही है निश्चित रूप से इसको समय सीमा के अंदर - छठा का लाभ तो हमने दे दिया है।

अध्यक्ष : वह सीमा माननीय मंत्री जी तय कर देंगे, आप भरोसा रखिये ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : आप भरोसा रखिये वह भी हो जायेगा ।

अध्यक्ष : अब आप नहीं पूछिए ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न स्पष्ट है और उत्तर अस्पष्ट है । छठा वेतनमान मिल रहा है मदरसा कर्मियों को और संस्कृत कर्मियों को सातवां वेतनमान नहीं मिल रहा है । माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि जब अन्य कर्मियों को मिल रहा है तो मदरसा और संस्कृत के कर्मियों को क्यों नहीं मिल रहा है ? माननीय मंत्री ने कहा कि प्रक्रियाधीन है । मैं स्पष्ट रूप से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि तीन माह के अंदर सारी प्रक्रिया को पूरा करके मदरसा और संस्कृत के शिक्षकों को भी अन्य कर्मियों की तरह सातवां वेतन का लाभ दिलाना चाहते हैं या नहीं ?

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : महोदय, हमने पहले कह दिया कि छठा का लाभ दे चुके हैं और सातवां की हमारी तैयारी है । हम यकीन के साथ और भरोसे के साथ आपको कह सकते हैं कि हमारी इन्तहाई कोशिश होगी कि बहुत कम समय सीमा के अंदर उसका लाभ दे दें ।

अध्यक्ष : आपसे भी कम कह रहे हैं ।

तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न सं0-1038(श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव)

श्री कृष्ण कुमार ऋषि,मंत्री : उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अन्तर्गत प्रत्येक प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम

बनाने का लक्ष्य है । पूर्वी चम्पारण जिला के चकिया प्रखंड में के गांधी मैदान चकिया में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-79, दिनांक 17.02.2009 द्वारा स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है । अतएव एक ही प्रखंड में दो स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति पर विचार नहीं किया जा सकता है । पूर्व में स्वीकृत उक्त स्टेडियम के निर्माण की अद्यतन स्थिति जानकारी की मांग विभागीय पत्रांक-15.05. 2017, पत्रांक-1317, दिनांक 18.12.17 द्वारा की गयी है ।

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव : महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ हमने ग्रामीण की बात की है प्रखंड का, हमने नगर पंचायत नगर निगम का बात नहीं किया है । हम कह रहे हैं कि 18 पंचायत का प्रखंड चकिया है । जो 18 पंचायत है और हमलोग बल दे रहे हैं कि जो ग्रामीण युवा हो उसको खेल के प्रति जागरूक करें, लेकिन 40 कि0मी0, 35 कि0मी0 पड़ता है जहां नगर पंचातय में एक स्टेडियम है । जो नगर पंचायत के अधीन है । अब 40 कि0मी0 से जो ग्रामीण बच्चे वहां तो नहीं आयेंगे, इसलिए मैं आग्रह करता हूँ कि प्रखंड का हमने बात किया है, ग्रामीण इलाका का हमने बात किया है । हम आग्रह करेंगे कि ग्रामीण इलाका जो है प्रखंड उसमें बनाया जाय, आप नगर पंचायत की बात कर रहे हैं । हम प्रखंड की बात कर रहे हैं ।

टर्न-3 /अशोक/ 13.03.2018

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-1039(श्री ललित कुमार यादव)</u>

श्रीमती कुमारी मंजु वर्मा, मंत्री : खंड-1 : अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि केन्द्र सरकार द्वारा नहीं बल्कि विभागीय स्तर पर प्रधानमंत्री मातृत्ववंदना योजना एवं किशोरी बालिका योजना की समीक्षा के दौरान प्रगति खेदजनक रहने के कारण विभागीय पत्रांक- 333 दिनांक 24.01.2018 से सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों का वेतन अगले आदेश तक अवरूद्ध कर दिया गया ।

खंड-2 : अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय स्तर से आवश्यक अनुश्रवण एवं अग्रेतर कार्रवाई करने से सम्प्रति प्रधानमंत्री मातृत्ववंदना योजना लागू होने से अबतक 131452(एक लाख इकत्तीस हजार चार सौ बावन) परियोजना स्तर पर लाभान्वितों का आवेदन प्राप्त कर लिया गया है, जिसमें से 97417 (सन्तानवे हजार चार सौ सतरह) लाभुकों का पंजीकरण की जा चुकी है । पंजीकृत लाभुकों में से 20985(बीस हजार नौ सौ पचासी) लाभुकों को राशि 2,52,35,000/-(दो करोड़ बावन लाख पैंतीस हजार) रू0 का भुगतान करा दिया गया है ।

किशोरी बालिकाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार हेतु केन्द्र सरकार द्वारा सबला योजना बिहार राज्य के 12 जिलों में लागू है एवं वर्त्तमन वित्तीय वर्ष में किशोरियों को लाभ दिया जा रहा है । इस वित्तीय वर्ष में 2017-18 में इसका नाम बदलकर किशोरी बालिकाओं के लिए योजना किया गया है एवं इस के लाभार्थी वर्ग में बदलाव करते हुए केवल 11 से 14 वर्ष की स्कूल नहीं जानेवाली किशोरियों के लिए निर्धारित किया गया है । महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 08.12.2017 से इसका विस्तार राज्य के अन्य 26 जिलों में करने का निर्णय लिया गया है, जिसके प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दिनांक 23.01.2018 को प्राप्त कर ली गयी है एवं विभागीय संकल्प संख्या-531 दिनांक 08.02.2018 से इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है ।

वर्त्तमान में बदले हुए प्रावधान के आलोक में परियोजनाओं से बेस लाईन सर्वे प्राप्त कर कार्रवाई की जा रही है । चूंकि यह योजना स्कूल नहीं जानेवाली 11-14 वर्ष की कन्याओं के लिए ही सीमित है अतः ऐसी कन्याओं/लाभार्थियों की संख्या कम होना स्वभाविक है जिसे इस योजना की असफलता के रूप में देखना समीचीन नहीं होगा ।

खंड-3 : उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, माननीय मंत्री जी का इतना फास्ट एक्सप्रेस जवाब था, बहुत कम समझ पाये, पूरी बात समझ नहीं पाये माननीय मंत्री का (व्यवधान) यह बुलेट ट्रेन थी । महोदय माननीय मंत्री जी से हम यह जानना चाहते हैं कि 534 सी.डी.पी.ओ. का वेतन रोका था या नहीं ?

अध्यक्ष : वे तो कही हैं कि रोका था ।

श्रीमती कुमारी मंजु वर्मा, मंत्री : महोदय, अगर काम में शिथिलता होगी तो नियमानुकूल है, वेतन रूका, काम करेगी तो वेतन मिलेगा और अगर काम नहीं होता है तो यही लोग हंगामा खड़ा करते हैं । वह तो विभागीय समीक्षा हुई थी काम नहीं करेगी सी.डी.पी.ओ. तो क्यों नहीं रूकेगा ?

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि 534 सी.डी. पी.ओ. का वेतन हमने रोका, इसका मतलब कार्य में शिथिलता हुई, महोदय, सी.डी. पी.ओ. की ही जवाबदेही थी, उसके ऊपर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी होते हैं वे दोषी नहीं है ? विभागीय प्रधान सचिव दोषी नहीं है ? अब तो डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन फैलियोर हैं, हम कहते हैं इसमें यदि आप लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपने कोई कारगर कदम नहीं उठा रहे हैं दूसरा इसमें जिला प्रोग्राम पदाधिकारी

और विभागीय सचिव या प्रधान सचिव भी दोषी है या नहीं ? उनके विरूद्ध कौन सी कार्रवाई होगी महोदय ।

श्रीमती कुमारी मंजु वर्मा, मंत्री : महोदय, कोई भी योजना चलती है तो विभाग से निदेश दिया जाता है, प्रखण्ड स्तर पर हमारे पदाधिकारी सी.डी.पी.ओ. हैं, तो काम का जवाबदेह कौन होगा माननीय सदस्य इसका जवाब दें ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, आसन सर्वोपरि होता है और बड़ा मुश्किल से प्रश्न आता है महोदय, राज्य हित का प्रश्न है महोदय, और इस तरह के जवाब से हमलोग संतुष्ट नहीं है, हम कह रहे हैं कि सी.डी.पी.ओ. के अलावा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी या विभागीय सचिव की कोई जिम्मेवारी बनती है कि नहीं ? उसके विरूद्ध कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी ? महोदय और पूरा जवाब स्पष्ट नहीं है, इसकी एक जांच होनी चाहिए, उच्चस्तरयी जांच होनी चाहिए, यह मेरा कहना है ।

श्रीमती कुमारी मंजु वर्मा, मंत्री : महोदय, विभाग से तो हमारे प्रखण्ड स्तर के जो पदाधिकारी रहेंगे, निदेशित तो उन्हें ही किया जायेगा और वे नहीं काम करेंगे तो विभागीय स्तर पर समीक्षा होती है तो कुछ न कुछ आदेश उनके प्रतिकूल तो होगा ही ।

अध्यक्ष : तारांकित प्रश्न संख्या-1040 ।

श्री भाई वीरेन्द्र : बार बार सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से आवाज आती है डबल इंजन, डबल इंजन लेकिन हमारा कहना है हुजूर, डबल इंजन तो लगा है लेकिन एक पूरब की तरफ खींचता है और एक पश्चिम की तरफ खींचता है, विकास सब खत्म है हुजूर, इसलिय डबल इंजन की चर्चा न करे लोग ।

अध्यक्ष : भाई वीरेन्द्र जी, यहां सरकार की बात नहीं है । यहां सदन की और माननीय सदस्यों की बात होती है, जो सभी एक ही इंजन से एक ही दिशा में चलते हैं ।

श्री शक्ति सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक पूरक है . . . . .

अध्यक्ष : अरे आपका तो किसी प्रश्न पर पूरक हो जायेगा ।

श्री शक्ति सिंह यादव :(व्यवधान) बालिका योजना में लक्ष्य क्या था सरकार का, उस लक्ष्य के एगेन्स्ट में . . .

अध्यक्ष : अरे लक्ष्य प्राप्ति नहीं हुई इसलिये तो सी.डी.पी.ओ. पर कार्रवाई हुई तो इसमें आप क्या पूछ रहे हैं । श्रीमती सावित्री देवी ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-1040(श्रीमती सावित्री देवी)</u>

श्री रमेश ऋषिदेव, मंत्री : अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि जमुई जिलान्तर्गत अनुसूचित जनजाति के लिए राजकीय अनुसूचित जनजाति बालक उच्च विद्यालय बामदह, जमुई में संचालित है, जिसमें जमुई जिला के छात्र नामांकन कराकर पठन-पाठन करते हैं ।

विभागीय पत्रांक-82 दिनांक 03.11.2017 द्वारा एकलव्य अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय(720 आसन) मौजा- आस्ता, अंचल- झाझा, जिला-जमुई में निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिसकी प्राक्कलित राशि 34.83 करोड़ (चौतीस करोड़ तिरासी लाख रू0) मात्र है । बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है ।

अनुसूचित जनजाति के लिए विभागीय पत्रांक-66 दिनांक 10.10.17 द्वारा 720 आसन वाले अनुसूचित जनजाति सह-शिक्षा(Co-ed) आवासीय +2 उच्च विद्यालय, मौजा-कटौना, अंचल- बरहट, जिला -जमुई में स्वीकृत है, जिसकी प्राक्कलित राशि 34.83 करोड़ (चौतीस करोड़ तिरासी लाख रू0) मात्र है ।

जमुई जिलान्तर्गत प्रखण्ड सोनो और चकाई में नये आवासीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अध्यक्ष : ठीक । तारांकित प्रश्न संख्या-1041 । प्रश्नकर्त्ता सदस्या पूरक पूछ रही हैं ।

श्रीमती सावित्री देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रहपूर्वक कहना चाहती हूँ कि मेरे क्षेत्र में खैरा (माज पहाड़िया) आदिम जन जाति से जिसे वर्त्तमान में अनुसूचित जनजाति के सूची में रखा गया है प्रारम्भ से ही इन जाति के लोग मिट्टी काटने का काम करते हैं, जिनके बच्चे की शिक्षा के लिए आवासीय विद्यालय की स्थापना अति आवश्यक है ।

अध्यक्ष : ठीक ।

श्री विजय प्रकाश : महोदय, यह हमारे जिला से संबंधित है, महोदय, कल्याण विभाग के जितने भी विद्यालय जमुई जिला में है, एक भी नहीं चल रहा है, एक भी नहीं चल रहा है हमारे गांव के बगल में तमकुलिया एक गांव पड़ता हैं वहां पर कल्याण विभाग का विद्यालय है, आज कई वर्षो से बंद है ।

अध्यक्ष : ठीक है । श्री मनोहर प्रसाद सिंह ।

टर्न-4/ज्योति/13-03-2018

<u>तारांकित प्रश्न संख्या 1041(श्री मनोहर प्रसाद सिंह)</u>

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा, मंत्री : महोदय, उत्तर अस्वीकारात्मक है । जिला पदाधिकारी, कटिहार के प्रतिवेदन के आधार पर वस्तुस्थिति यह है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड के अंतर्गत शीला देवी पति स्व0 बबुआ मुर्मु, सैनी सोरेन पति-स्व0 श्री भोगेन मुर्मु सा0-मियाँपुर, थाना-मनिहारी का स्थलीय जाँच के क्रम में पाया गया कि उक्त स्थल संबंधित नाम का कोई व्यक्ति ट्रेस नहीं हुआ है और न ही आर.टी.पी.एस. काउंटर पर कोई आवेदन पेंशन स्वीकृति हेतु दिया गया है । इनकी खोज दूसरे

पंचायत में की जा रही है । पहचान के बाद आर.टी.पी.एस. काउंटर प्राप्ति पर विधवा पेंशन स्वीकृति से संबंधित कार्रवाई की जायेगी ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : ट्रेस तो हो चुका है, ट्रेस नहीं हुआ था जब मुझसे सम्पर्क किया गया, ट्रेस हो चुका है, जिनका नाम दिया गया है, उनके लिए भी तो कोई कार्रवाई नहीं की गयी है, तो क्या मंत्री महोदय कार्रवाई करने का .....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ने बताया है कि न इस नाम से आवेदन आया है, न इस नाम के किसी का पता चल पाया है । आप सूचना दे दीजिये माननीय मंत्री उसपर कार्रवाई करवा देंगे ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : मैंने कहा न कि पता चल गया है, उसके बाद उसकी सूचना गलत है कि पता नहीं चल रहा है ।

अध्यक्ष : आप सारी सूचना माननीय मंत्री जी को दे दीजियेगा ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह: ठीक है ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या 1042 (श्री मुजाहिद आलम)</u>

श्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : महोदय, 1- आंशिक रुप से स्वीकारात्मक है ।

2- उत्तर स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि श्री राजेन्द्र मिश्र, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी योजना एवं लेखा, समस्तीपुर सम्प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुवनी को विभागीय अधिसूचना संख्या-134 दिनॉक 19-02-2018 द्वारा निलंबित कर विभागीय कार्यवाही के अधीन कर दिया गया है ।

3- उपर्युक्त खंड 1 एवं 2 में उत्तर सन्निहित है ।

श्री मुजाहिद आलम : अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ बोलने दिया जाय, गबन का मामला है और मंत्री जी सस्पेंड किए है, तो विभागीय कार्रवाई का मंत्री जी विचार रखते हैं क्या ?

श्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : कार्रवाई हो गयी है, वे सस्पेंड हो गए हैं ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या 1043(श्री राम बालक सिंह)</u>

श्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री: महोदय, 1- आंशिक रुप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प 1021 दिनॉक 5-7-2013 द्वारा माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों को एक एक उच्च माध्यमिक विद्यालय से आच्छादित करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है ।

2- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

3- विभागीय आदेश ज्ञापॉक संख्या 1648 दिनॉक 27-8-2015 द्वारा समस्तीपुर जिले के सरायरंजन प्रखंड अन्तर्गत धर्मपुर पंचायत में

अवस्थित मध्य विद्यालय मणिका को उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित कर दिया गया है ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1044 (श्री सीताराम यादव)

श्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री: महोदय, 1- उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुवनी के पत्रांक 509 दिनॉक 9-3-2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत विद्यालय में हिन्दी-2, संस्कृत-1, गणित-1, विज्ञान-1, अंग्रेजी-1 एवं सामाजिक विज्ञान के 3 शिक्षक कार्यरत हैं । माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 21199/13 में दिनांक 13-10-2017 को पारित न्यायादेश के तहत जिला परिषद्, नगर निकाय परिषद् उच्च माध्यमिक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली समय समय पर यथा संशोधित 206 नियमावली के नियम 6 एवं 8 को रेड डाउन कर दिया गया है । उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में विशेष अनुमति याचिका संख्या 20/2018 एवं अन्य संलग्न वाद दायर किया गया है, जिसमें दिनांक 29-1-2018 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सुनवायी करते हुए कतिपय निर्देश दिए गए हैं और उक्त वाद में अगली सुनवायी दिनॉक 15-03-2018 को निर्धारित किया गया है । इस अवधि में यथास्थिति स्टेटस-को बनाए रखने का आदेश दिया गया है । परिणामस्वरुप नियोजन करने में विधिक कठिनाई है ।

श्री सीताराम यादव : महोदय, 2500 छात्रा इस स्कूल में है, जहॉ एक शिक्षक 2500 छात्रा के लिए सफिसियेंट हैं । 2500 छात्रा एडमिटेड उक्त विद्यालय में तो सफिसियेंट कैसे हैं ?

अध्यक्ष : वह कह रहे हैं कि कोई कोर्ट में मामला है उसमें स्टेटस-को को मेंनटेन करने के लिए कहा गया है ।

श्री सीताराम यादव : समय सीमा दे सकते हैं ।

श्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : कोर्ट का मामला है, कोर्ट से आ जायेगा तब हम करेंगे ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि इस राज्य में 6 हजार विद्यार्थी पर गणित के एक शिक्षक है, 22000 पर फिजिक्स के शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं, तो आखिर इन विद्यालयों में जहॉ जहॉ सिर्फ एक सवाल पर प्रश्नगत जो करने वाले प्रश्नकर्ता हैं, सवाल वह नहीं है, पूरे बिहार का सवाल यह है कि जिस राज्य के अंदर में 22000 पर फिजिक्स के शिक्षक नहीं हों, 6 हजार पर गणित के शिक्षक नहीं हो और जहॉ 2500 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, एक के अलावे और शिक्षक नहीं हैं तो कैसे होगा, क्या सरकार इसपर आगे कोई कार्रवाई करेगी ?

तारांकित प्रश्न संख्या 1045 (श्रीमती गुलजार देवी)

श्री बृजकिशोर बिंद, मंत्री : महोदय, 1- स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि मधुवनी जिलान्तर्गत राजकीयकृत प्लस 2 मेवा लाल राजावती सार्वजनिक उच्च विद्यालय सरौती के वर्ग 9 एवं 10 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए वर्ष 2015-16 में अति पिछड़ी जाति के लिए 8 लाख 11 हजार 800 मात्र एवं पिछड़ी जाति के लिए रुपया 3 लाख, 30 हजार, 3 सौ मात्र की राशि विद्यालय के खाता में भेजी गयी जिसमें पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के 345 छात्र छात्राओं के बीच छात्रवृति वितरण हेतु 3 लाख, 10 हजार, 5 सौ रुपये मात्र की राशि का बैंक एडवाईस दिनाँक 12-03-2018 को भेजा गया है । शेष छात्र छात्राओं की खाता संख्या प्राप्त कर वितरण की कार्रवाई की जा रही है । विभागीय पत्र संख्या 526 दिनाँक 12-03-2018 द्वारा विलम्ब के लिए दोषी पदाधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर उनपर कार्रवाई की जायेगी ।

श्रीमती गुलजार देवी : अध्यक्ष महोदय, कब तक उसपर कार्रवाई करेंगे ?

अध्यक्ष : स्पष्टीकरण पूछे हैं, उसके बाद ।

श्री बृजकिशोर विन्द, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, स्पष्टीकरण पूछा गया है, मांगा गया है । जैसे ही आ जाता है, उनपर कार्रवाई होगी ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1046 (सुश्री पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान)

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा , मंत्री : महोदय, 1- उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि बाल विकास परियोजना अन्तर्गत नियमित एवं संविदा के आधार पर नियुक्त महिला पर्यवेक्षिकाएं कार्यरत हैं । कटिहार जिला अन्तर्गत नियमित रुप से 5 महिला पर्यवेक्षिका पदस्थापित हैं, जिनका स्थापना आयुक्त कार्यालय, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया में संधाारित हैं एवं उनके स्तर से ही अपने प्रमंडल अतर्गत स्थानान्तरण किया जाता है । नियमित रुप से पदस्थापित महिला पर्यवेक्षिका का स्थानान्तरण वर्ष 2015 में किया गया है । कटिहार जिलान्तर्गत संविदा पर 75 महिला पर्यवेक्षिका पदरस्थापित हैं, जिनमें से प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिला प्रोग्राम पदाधिकारी कार्यालय, कटिहार के आदेश ज्ञापाँक 1062 प्रो0 दिनाँक 28-06-2016 एवं ज्ञापांक 96 प्रो0 दिनांक 31-01-2017 द्वारा कुल 11 महिला पर्यवेक्षिकाओं का स्थानान्तरण किया गया था । जिला पदाधिकारी, कटिहार के पत्रांक 224 दिनाँक 7-3-2018 से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों द्वारा संविदा के आधार पर कार्यरत महिला पर्यवेक्षिकाओं के स्थानान्तरण हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है, जिसकी प्रकिया अंतिम चरण में है । स्थानान्तरण की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर ली जायेगी ।

सुश्री पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से इतना ही आश्वासन चाहिए कि कब तक यह प्रक्रिया पूरी कर दी जायेगी ?

अध्यक्ष : वह तो बतायीं कि वह लगातार चल रही है । एक 28-6-16 का भी उन्होंने हवाला दिया कि किया गया है । मंत्री जी ने कहा है कि आयुक्त कार्यालय में उनका स्थापना होता है, वहॉ से स्थानान्तरण होता है और पिछले समय में हुआ भी है । किसी खास पर्यवेक्षिका के बारे में आपका कोई होगा, तो मंत्री जी को दे दीजियेगा, वह कार्रवाई करेंगी ।

सुश्री पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान : नहीं, अध्यक्ष महोदय, कोई खास नहीं पूरे डिस्ट्रीक्ट का मामला है । कोई खास का मामला नहीं है, यह पूरे जिला का मामला है ।

अध्यक्ष: वह बतला दीजिये ।

टर्न-5/13.3.2018/बिपिन

<u>तारांकित प्रश्न संख्या: 1047 (श्री महेश्वर प्रसाद यादव)</u>

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, 1. उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत गायघाट प्रखंड के शिवदाहा पंचायत के प्राथमिक विद्यालय शिवदाहा पंचायत में प्राथमिक विद्यालय शिवदाहा, बरैल, ततमा टोला स्वीकृत नहीं है ।

2. उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

3. उत्तर उपर्युक्त कंडिका में सन्निहित है ।

श्री महेश्वर प्रसाद यादव: महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब सही नहीं है । वहां विद्यालय स्वीकृत है । विद्यालय के लिए जमीन लिखा हुआ है और उसको दूसरे व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है । इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि इसकी पुन: उच्चस्तरीय जांच कराना चाहते हैं ?

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा,मंत्री: महोदय, कल मैंने पूरे विषय पर, प्रश्नों पर चर्चा कर रहा था, समीक्षा कर रहा था और उस दौरान मुझे जानकारी दी गई कि यह विद्यालय स्वीकृत है ही नहीं । भवन किसी ने रजिस्ट्री कर दी है लेकिन स्वीकृति नहीं है उसकी ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप कह रहे हैं कि विद्यालय स्वीकृत नहीं है, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि विद्यालय स्वीकृत है और जमीन भी उसके नाम से रजिस्ट्री है, स्कूल के लिए रजिस्ट्री है तो यह बात अलग है । इसको देखवा लीजिए कि स्कूल स्वीकृत है कि नहीं । दूसरी बात कि अगर स्कूल स्वीकृत नहीं

भी है और भूमि विद्यालय के लिए सरकार के नाम से पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है, तब अतिक्रमण तो उसपर भी नहीं होना चाहिए, उसको भी देखवा लीजिए ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा,मंत्री: जी, मैं इसकी जांच करवा लूंगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या: 1048 (श्री वशिष्ठ सिंह)

श्री संतोष कुमार निराला,मंत्री: महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है । उक्त मार्ग पर नए परमिट हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर परमिट निर्गमन की कार्रवाई की जाएगी ।

श्री वशिष्ठ सिंह: मंत्री महोदय जी, सब स्वीकारात्मक है तब आपसे यही आग्रह है कि आश्वासन दे दीजिए कि उसको भविष्य में हम शुरू करा देंगे ।

अध्यक्ष: ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या: 1049 (श्री अमित कुमार)

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा,मंत्री: महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार के वर्त्तमान नीति के तहत सिर्फ उन्हीं अनुमंडलों में डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने की योजना है जहां पूर्व से अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय संचालित नहीं है । सीतामढ़ी जिला का रीगा प्रखंड सीतामढ़ी सदर अनुमंडल के क्षेत्रान्तर्गत आता है जहां पूर्व से एस.आर.के.जी. महाविद्यालय, सीतामढ़ी, एस.एल.के. कॉलेज, सीतामढ़ी, आर.एस.एस.साइंस कॉलेज, सीतामढ़ी तथा आर.एस.महिला कॉलेज, सीतामढ़ी पूर्व से ही संचालित है । अत: रीगा प्रखंड में संप्रति डिग्री महाविद्यालय खोलने की कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन नहीं है ।

श्री अमित कुमार: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सीतामढ़ी जिला के अनुमंडल में खोला जाए क्योंकि करीब-करीब हमारी सुप्पी और रीगा ब्लॉक कहीं भी डिग्री कॉलेज है, वहां से डिस्टेंस उसका 20 कि0मी0 है । अब बच्ची लोग कैसे जाएगी वहां उस कॉलेज में, यह भी तो सोचने की बात है । अत: उसपर विचार करना चाहिए । यह मैं रिक्वेस्ट करूंगा ।

अध्यक्ष: ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या: 1050 (श्री अशोक कुमार सिंह(224))

अध्यक्ष : श्री विनोद जी प्राधिकृत हैं ।

श्री विनोद प्रसाद यादव: पूछता हूं ।

श्री विनोद कुमार सिंह,मंत्री:महोदय, खंड-1. उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि सहायक निदेशक, जिला खनन कार्यालय, गया के पत्रांक 692 दिनांक 08 मार्च,

2018 द्वारा सूचित किया गया है कि गया जिलान्तर्गत कुल 42 बालू घाट संचालित है जिसमें शेरघाटी प्रखंड में तीन एवं डोभी प्रखंड में दो बालू घाट संचालित हैं । वैसे बालू घाट जहां के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं है एवं अवैध खनन का मामला प्रकाश में आने पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाती है जिसके तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 में शेरघाटी एवं डोभी प्रखंड में अवैध उत्खनन परिवहन के मामले में कुल 41 प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, 86 वाहन जप्त किए गए हैं एवं 25 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है । बालू के अवैध उत्खनन एवं परिवहन में संलिप्त जिला स्तर, अनुमंडल स्तर, अंचल और थाना स्तर पर लगातार छापेमारी की जाती है । गया जिलान्तर्गत अवैध खनन एवं परिवहन के विरूद्ध की गई कार्रवाई के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 1832 छापेमारी 345 प्राथमिकी, 190 व्यक्तियों की गिरफ्तारी एवं 949 वाहन की जप्ती की गई है ।

श्री विनोद प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय मूल प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके । मैंने कहा कि अवैध उत्खनन नहीं, वैध उत्खनन में पहले जो लिमिट, जो गहराई है, उससे ज्यादा गहराई तक बालू निकाला जा रहा है जिससे भूगर्भीय जल प्रभावित हो रहा है और उसमें पेयजल संकट और सिंचाई सुविधा का अभाव हो रहा है तो इसपर माननीय मंत्रीजी ने तो कोई उत्तर ही नहीं दिया कि ऐसा है कि नहीं ?

दूसरी बात जो इन्होंने कहा कि कई ट्रकों को जप्त किया गया है और ट्रैक्टर को जप्त किया गया है, लोगों को जेल भेजा गया है तो क्या इनके विभाग के अधिकारी उन जगहों पर उत्खनन रोकने में असक्षम हैं, तभी इतना अवैध उत्खनन हो रहा है ? तो माननीय मंत्रीजी, जो वहां पर कई जगहों पर...

अध्यक्ष: आप पूरक पूछिये ।

श्री विनोद प्रसाद यादव: पूरक मेरा है कि उत्खनन के कारण तीन मीटर से ज्यादा गहराई तक जो बालू निकाला गया है जिसके कारण भूगर्भ जल नीचे चला गया है । आसपास के गांव में पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है । तो क्या माननीय मंत्रीजी को विभाग ने जो जवाब दिया है, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं । मगध के आयुक्त से इन संपूर्ण मामले की जांच कराने का विचार रखते हैं ?

श्री विनोद कुमार सिंह,मंत्री: महोदय, तीन मीटर गहराई की चर्चा माननीय सदस्य ने की है और उसका जो जांच हमने कराया है, उसमें कहीं पर प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है । इसके बाद भी माननीय सदस्य की चिंता गंभीर है तो वो अगर स्थान बताएंगे तो जांच कराएंगे ।

अध्यक्ष : स्थान दिया हुआ है, किसी वरीय अधिकारी से जांच करा दीजिए ।

श्री विनोद कुमार सिंह,मंत्री: जिस स्थान की चर्चा इसमें इन्होंने की है, उस स्थान पर तीन मीटर की गहराई पर कहीं पर ...

अध्यक्ष: दोनों जगह दिया हुआ है न - शेरघाटी के चिताब एवं डोभी के पिड़ासीन, तो दिया हुआ है दोनों ।

श्री बिनोद कुमार सिंह,मंत्री: दोनों जगहों का जांच पदाधिकारियों ने किया है महोदय....

अध्यक्ष: आप किसी वरीय अधिकारी से जांच करा लीजिए ।

श्री बिनोद कुमार सिंह,मंत्री: ठीक है । करा लेंगे ।

श्री विनोद प्रसाद यादव: मेरा एक पूरक है महोदय कि माननीय मंत्रीजी कह रहे हैं कि गहराई अधिक नहीं है, कम-से-कम एक दर्जन बच्चों की मौत गहराई में डूबने से हो चुकी है ..

अध्यक्ष: गहराई की भी जांच कराएंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या: 1051 (डॉ0 शमीम अहमद)

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा,मंत्री: महोदय, 1. उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चंपारण जिला के बंजरिया प्रखंड अंतर्गत पचरखा पश्चिमी पंचायत के ग्राम मोकिलसपुर में स्थित मध्य विद्यालय बूढ़ी गंडक नदी के किनारे है तथा इसकी दूरी 13 से 14 मीटर है । इस विद्यालय के पोषक क्षेत्र में दूसरी भूमि स्थानीय ग्रामीण द्वारा दान में दिया गया है जिसका निबंधन किया जा चुका है । भवन निर्माण मद में राशि उपलब्ध होने के उपरांत भवन निर्माण का कार्य शीघ्र कराया जाएगा ।

डॉ0शमीम अहमद: अध्यक्ष महोदय, अभी जहां विद्यालय अवस्थित है, वहां नदी में कटाव होने की वजह से कभी बच्चे वहां जाकर डूब सकते हैं और वहां ग्रामीणों ने फैसला करके जमीन दे दिया है तो मैं मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि उस विद्यालय को वहां कब तक शिफ्ट करा देंगे ?

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा,मंत्री: महोदय, मैंने बताया कि लोगों द्वारा दान में दी गई जमीन उपलब्ध है वहां, राशि की उपलब्धता होते ही वहां भवन निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, जब ग्रामीणों ने जमीन दिया है, ग्रामीण जागरूक हैं, तब तो सरकार की तरफ से शीघ्र निर्माण करा देना चाहिए । वह भवन कट रहा है, तब तक जल संसाधन विभाग को भी लिखिए कि कटाव में कितना दिन तक उसको बचाया जा सकता है ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा,मंत्री: ठीक है महोदय, मैं इसपर शीघ्र कार्रवाई करूंगा ।

टर्न-06/कृष्ण/13.03.2018

तारांकित प्रश्न संख्या : 1052 (श्री विजय प्रकाश)

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : महोदय, 1. उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2. वस्तुस्थिति यह है कि उच्च शिक्षा निदेशालय से प्राप्त सूचनानुसार जमुई जिला में महिला महाविद्यालय की स्थापना की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है जिसके लिये भूमि चयनित हो गयी है ।

3. वस्तुस्थिति यह है कि जिला पदाधिकारी, जमुई के द्वारा राजकीय कन्या मध्य विद्यालय, जो नगर परिषद् में अवस्थित है, को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने का प्रस्ताव निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार,पटना को भेजा गया है । इस विद्यालय से 200 मीटर की दूरी पर प्लस टू राज्य संपोषित बालिका उच्च विद्यालय, जमुई अवस्थित है । विभागीय संकल्प 1021 दिनांक 05.07.2013 में निहित प्रावधान के आलोक में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति से अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की जाती है । अतः उक्त विभागीय संकल्प में निहित निर्देश के मद्दे नजर नगर परिषद् के विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री विजय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, जो कन्या मध्य विद्यालय के बारे में माननीय मंत्री महोदय जो स्वीकार किये हैं, वहां जिला में मात्र एक महिला उच्च विद्यालय है, जहां पूरे गांव से आते हैं, सबों का वहां नामांकन नहीं हो पाता है, इसलिए आपसे निवेदन किया था कि पहले भी पत्रांक 1057 के माध्यम से कि एक महिला उच्च विद्यालय शहर में दिया जाय, जो बड़ी आबादी है । आप कहते हैं कि बेटी बचाओ,बेटी पढ़ाओ का नारा है तो यह नारा कैसे पूरा होगा कैसे सफल होगा, इसपर माननीय मंत्री जी सोचें ।

दूसरा, जो महाविद्यालय का है, माननीय मुख्यमंत्री जी आज से लगभग 5-6 साल पहले वहां गये थे और महाविद्यालय के लिये वहां घोषणा किये थे लेकिन आज माननीय मंत्री जी से पता चल रहा है कि प्रक्रियाधीन है । महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह कबतक प्रक्रियाधीन रहेगा ? महोदय, उसकी एक समयावधि तय कर दिया जाय ।

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : महोदय, महिला माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की कार्रवाई प्रकियाधीन है । यह मैंने बताया । लेकिन सरकार का जो संकल्प है, 1021, उसके अनुसार हमलोग ग्राम पंचायतों में उत्क्रमित करते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी स्पष्ट है कि आपकी उत्क्रमित वाली योजना पंचायतों के लिये है, शहरों के लिये नहीं है । लेकिन आप यह भी कह रहे हैं कि प्रस्ताव वहां महिला माध्यमिक विद्यालय खोलने का विचाराधीन है या प्रक्रियाधीन है । यह भी आप बता रहे हैं । माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि इसको जितना जल्द हो सके, करा दीजिये ।

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : महोदय, यह चयनित जो है उच्च शिक्षा निदेशालय से प्राप्त सूचनानुसार जमुई जिला में महिला महाविद्यालय की स्थापना की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है जिसके लिये भूमि चयनित हो गयी है और आप दूसरी बात कह रहे हैं ।

श्री विजय प्रकाश : महोदय, दोनों दिया हुआ है ।

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : यह जो है संकल्प के अनुरूप नहीं है । यह संकल्प पंचायतों में उत्क्रमण का है ।

अध्यक्ष : आप संकल्प को छोड़ दीजिये । जो प्रक्रियाधीन है, उसी को करा दीजिये ।

श्री विजय प्रकाश : संकल्प आपका नहीं है, विभाग में आपने तय किया है कि पंचायत में ही करना है तो शहरों की बालिकाओं का क्या होगा ? शहरों के बारे में सरकार क्या विचार रखती है ? यह बतायें कि क्या सरकार सिर्फ गांवों में ही उत्क्रमित करने का काम करेगी ? हम यह जानना चाहते हैं कि शहर में उत्क्रमित होगा या नहीं ? इस पर सरकार बताये । क्या पकौड़ा बेचने पर लोग विवश होंगे ?

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य की जो भावना है, मैं उसके अनुरूप मैं इसकी जांच कराकर शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन देता हूं ।

श्री विजय प्रकाश : महाविद्यालय के बारे में बता दीजिये महोदय कि कबतक प्रक्रियाधीन रहेगा?

अध्यक्ष : अब मामला खुला हुआ है, इसलिए रहने दीजिये ।

तारांकित प्रश्न संख्या: 1053 (श्रीमती गुलजार देवी)

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, महथौर खुर्द में वर्ग नवम् में कुल 136 एवं दशम् में कुल 90 छात्र-छात्रायें नामांकित हैं । वर्तमान में छात्र-छात्राओं का पठन-पाठन मध्य विद्यालय के 6 वर्ग कक्ष अन्तर्गत एवं स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा किया जाता है ।

बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि0 के द्वारा भवन निर्माणाधीन है । माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की पदस्थापना नहीं हुई है । उत्क्रमित माध्ययिमक विद्यालय सिझौलिया में वर्ग नवम् में 137 एवं दशम् में 92 छात्र-छात्रायें नामांकित हैं । बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि0 के द्वारा दो मंजिला भवन बनाकर हैंड ओवर कराया गया है, जिसमें कुल 16 कमरे और 10 सीट का शौचालय है । शिक्षक की नियुक्ति नहीं होने के कारण मध्य विद्यालय के स्नातक योग्यताधारी पठन-पाठन का कार्य कराया जा रहा है ।

प्लस टू उच्च विद्यालय बरही फुलपरास में वर्ग नवम् में 1156 एवं दशम् में 1205 तथ उच्चतर माध्यमिक कला संकाय में 120, विज्ञान संकाय में 60 एवं वाणिज्य संकाय में 30 छात्र-छात्रायें नामांकित हैं । नामांकित छात्र-छात्राओं के अनुपात में माध्यमिक में 11 शिक्षक एवं उच्चतर माध्यमिक में 6 शिक्षक कार्यरत हैं । कुल वर्ग कक्ष की संख्या 9 एवं एक सभागार है ।

श्रीमती गुलजार देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि कब तक भवन बन जायेगा और बरही फुलपरास जो स्कूल है उसमें तो 10 प्लस टू भवन बना हुआ है ।

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : भवन तो बना हुआ है और उसको हैंडओवर कर दिया गया है। शिक्षक की नियुक्ति नहीं होने के कारण मध्य विद्यालय में स्नातक योग्यताधारी द्वारा पठन-पाठन का कार्य कराया जा रहा है । महोदय, इनकी समस्या क्या है ? भवन तो वहां हैंडओवर कर दिया गया है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती गुलजार देवी जी, माननीय मंत्री जी ने बड़ी संवेदनशीलता से आपकी समस्या जाननी चाही है । आप इनको समस्या दे दीजियेगा, जिसका माननीय मंत्री समाधान कर देंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या : 1054 (श्री अमित कुमार)</u>

श्री संतोष कुमार निराला, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1. स्वीकारात्मक है ।

2. क्षेत्रीय परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर से निजी बस मालिकों को बैरगेनिया मुख्यालय से सीतामढ़ी जिला मुख्यालय एवं अन्यत्र जाने-आने के लिये बस परिचालन हेतु परमिट निर्गत है । साथ ही उक्त पथ में जीप आदि निजी वाहन का भी परिचालन होता है ।

3. अस्वीकारात्मक है । सीतामढ़ी बैरगनिया मार्ग पर निगम की संप्रति 5 बसों का संचालन किया जा रहा है । सीतामढ़ी से अन्य मार्गों पर लगभग 10 से 15 बसों का संचालन वर्तमान में किया जा रहा है ।

श्री अमित कुमार : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बैरगेनिया के दिहात से जो लोग आते हैं जहां पर बस की परमिट नहीं है जहां पर जीप की उपलब्धता नहीं है, वह एरिया जो सुदूर बोर्डर इलाका पड़ता है, वहां पर भी कम से कम बस जाना चाहिए, जिससे लोगों को जिला मुख्यालय और शहर में जाने की सुविधा हो।

तारांकित प्रश्न संख्या : 1055 (श्री नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह)

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, विभागीय पत्रांक 156 दिनांक 10.03.2018 के द्वारा प्रश्नाधीन विद्यालय के वंचित 12 छात्रों को मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत राशि उपलब्ध कराने का निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी को दे दिया गया है । दोषी पदाधिकारी, कर्मचारी जिनकी लापरवाही के कारण लाभुक वंचित रह गये थे, उन्हें चिन्हित कर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी ।

टर्न-7/सत्येन्द्र/13-3-18

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह: देखिये अध्यक्ष जी, वर्ष 2015-16 का यह पैसा है और मंत्री जी के समक्ष विधान-सभा के फ्लोर पर जब बच्चे की आवाज को हमने उठाया तो इनका आदेश होता है कि बच्चे को पैसा दिया जायेगा । मेरा यह कहना है अध्यक्ष जी कि मंत्री जी वैसे पदाधिकारी जो सरकार की योजना पर उदासीनता बरत रहे हैं ,वैसे पदाधिकारियों को दंडित करने का काम ईमानदारी से ये करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा, मंत्री: महोदय, मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो पदाधिकारी दोषी होंगे, उनके विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी ।

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न संख्या-1056(श्री मो0 नेमातुल्लाह)

अध्यक्ष: 1056 पुट हुआ । यह बाद में लिया जायेगा ।

प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उसे सदन पटल पर रख दिये जायें ।

शून्यकाल

श्री अमित कुमार: अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिलान्तर्गत सुप्पी प्रखंड में थाना की स्वीकृति मिल चुकी है परन्तु जमीन अनुपलब्ध रहने के कारण निजी आवास में चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में लॉ एंड आर्डर की गोपनीयता बनाये रखना संभव नहीं है । जनहित में थाना का जमीन उपलब्ध कराकर भवन निर्माण कराया जाय ।

श्रीमती अमिता भूषण: अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिले के मक्का उत्पादक किसानों की फसल में दाना नहीं आने की वजह से जिले के किसानों में हाहाकार की स्थिति है । अत: जनहित में इन मक्का किसानों की समस्या पर सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करे ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, नालंदा जिला अन्तर्गत करायपरशुराय प्रखंड में अमात गवसपुर आर0ई0ओ0 पथ जर्जर स्थिति में है, जिसके कारण आवागमन बाधित रहता है । अत: उक्त पथ को तत्काल प्रभाव से बनाने हेतु सरकार से मांग करता हूँ ।

श्री राजेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय, हरसिद्धि विधान-सभा अन्तर्गत कन्धेदवा चौक से कन्धेदवा कुशवाहां टोला जाने वाली पथ जर्जर स्थिति में है जो ग्रामीण कार्य विभाग की पथ है और अनुरक्षण समय बहुत पहले समाप्त हो चुका है । अत: जनहित में अविलम्ब उक्त पथ को सरकार बनावे ।

डॉ0 विनोद प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, गया जिलान्तर्गत शेरघाटी प्रखंड के ग्राम पंचायत कचौड़ी की आबादी लगभग 20 हजार है एवं घोड़वाडीह, हनानगंज, गॉवखाप, मोहिद्दीनपुर इत्यादि गांवों को मिलाकर 30 हजार से अधिक आबादी है । जनहित में कचौड़ी स्वास्थ्य उपकेन्द्र को उत्क्रमित कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्री महबूब आलम: अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद स्मार्ट सिटी के नाम पर गरीबों को बिना वैकल्प्कि व्यवस्था किये उजाड़ा जा रहा है, हमारी मांग है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था किये शहरी गरीबों को उजाड़ना बंद किया जाय और पुश्तैनी रूप से बसे शहरी गरीबों को जमीन पर मालिकाना हक दिया जाय ।

श्री सुदामा प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार की सात निश्चय योजना में '' हर घर नल का जल'' एक महत्वपूर्ण योजना है लेकिन जमीनी स्तर पर कहीं भी नल का जल लोगों को नहीं मिल रहा , उल्टे चापाकल भी बंद हो गये । चापाकल की मरम्मति व शुद्ध पानी की व्यवस्था की हम मांग करते हैं ।

श्री सत्यदेव राम: अध्यक्ष महोदय, गर्मी का महीना आरंभ होते ही गरीब बस्तियों में तेजी से अगलगी की घटनाओं की सूचना मिल रही है लेकिन बहुत जगहों पर अनुमंडल

स्तर पर भी अग्निशमन यूनिट नहीं है । थाना स्तर पर अग्निशमन यूनिट का तत्काल गठन किया जाय और लोगों को राहत पहुंचाई जाय ।

श्री ललन पासवानः अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत प्रखंड शिवसागर-चेनारी एस.एच. पथ के जगडिहरा मोड़ से सिकरौर गांव तक का पहुंच पथ कच्ची है, आवागमन बाधित है । सरकार से मांग करते हैं कि उक्त पथ का पक्कीकरण करावें ।

श्री रामप्रीत पासवानः अध्यक्ष महोदय, जिला मधुबनी, प्रखंड अंधराठाढ़ी पलार गांव के सुरगवे नदी पर लघु सिंचाई विभाग से वर्ष 2002 में 6 करोड़ की लागत से स्लुईस गेस का निर्माण कराया गया । विभाग के लापरवाही से अभी तक स्लुईस गेट किसानों की खेती हेतु चालू नहीं किया गया । अतः सरकार से स्लुईस गेट चालू करवाने की मांग करता हूँ ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंहः अध्यक्ष महोदय, मोतिहारी केन्द्रीय विश्वविद्यालय को अपना भवन नहीं होने से पठन पाठ्न बाधित हो रहा है तथा संस्थान का पूरा लाभ विद्यार्थियों को नहीं प्राप्त हो रहा है । सरकार भवन निर्माण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू कराकर और अधिक फैकल्टी में पढ़ाई प्रारम्भ कराये ।

श्री प्रह्लाद यादवः अध्यक्ष महोदय, लखीसराय के सूर्यगढ़ा थानाध्यक्ष दिनांक 1-2-18 को 8 से 11 बजे रात में निस्ता गांव के ग्रामीणों पर फायरिंग किया, घर में घुसकर महिला, वृद्ध एवं बच्चे को बुरी तरह से पीटा, बचाव में सूर्यगढ़ा कांड सं0-12/2018 निर्दोष लोगों पर दर्ज किया गया । अतः दारोगा को निलंबित करने एवं झूठा केस को वापस लिया जाय....

(व्यवधान)

मैं सरकार से मांग करता हूँ कि वैसे थाना प्रभारी को निलंबित किया जाय, इसकी एक उच्चस्तरीय जांच हो और महोदय उस थाना प्रभारी का पटना जोन में ट्रांसफर भी हो गया है...

(व्यवधान)

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकीः महोदय, यह बहुत ही गंभीर मामला है । ठीक है, आसन ने भी इस पर संज्ञान लिया और सदन में सरकार भी ले रही है । मगर यह जो गंभीर मामला है इसकी गंभीरता को देखते हुए सरकार को इस पर बोलना चाहिए कि क्या कार्रवाई की जायेगी या नहीं की जायेगी इसलिए मैं मांग करता हूँ कि सरकार बताये ऐसे गंभीर मामले में भी अगर सरकार कान में तेल डालकर के सोयी रहेगी तो फिर मुश्किल होगा इसलिए सरकार से अनुरोध है कि..

अध्यक्षः ठीक है । माननीय सदस्यों की भावना को देखते हुए सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इस संबंध में जांच करानी चाहिए ।

(व्यवधान)

सरकार को कहा न ?

श्री रामनारायण मंडल,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य एक-एक कर के बोलेंगे तो सुना जायेगा न ? अब सब एक बात को बोलेंगे तो कैसे सुना जायेगा ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: अच्छा, आप सुन रहे हैं तो हम बोलें ? सदन की कमिटी के द्वारा इसकी जांच करा दी जाय ।

अध्यक्ष: श्री सुनील कुमार।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कहा कि सब लोग एक साथ बोल रहे हैं तो हम सुन नहीं रहे हैं इसलिए मैंने कहा कि इसकी गंभीरता को देखते हुए सदन के कमिटी से इसकी जांच करायी जाय ।

अध्यक्ष: ठीक है । श्री सुनील कुमार ।

श्री सुनील कुमार: माननीय अध्यक्ष महोदय..

(व्यवधान)

अध्यक्ष: अरे, आप ही के सदस्य बोल रहे हैं ।

श्री सुनील कुमार: अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिलान्तर्गत सीतामढ़ी शहर स्थित तलखापुर मुहल्ला में दिनांक 10-3-2018 को रात्रि 9.30 बजे व्यवसायी धर्मेन्द्र कुमार का अज्ञात अपराधियों द्वारा हत्या कर दिया गया है । अत: उक्त हत्या के वांछित अपराधियों के गिरफ्तारी एवं पीड़ित परिवार को मुआवजा राशि के भुगतान की मैं मांग करता हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आपलोगों ने कहा आसन ने उसको गंभीरता से लेते हुए सरकार को निर्देश दिया है उस मामले की जांच कराने के लिए, अब क्या चाहते हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष: श्री सुनील कुमार, आप पढ़ चुके ।

श्री सुनील कुमार: जी ।

टर्न-8/मधुप/13.03.2018

श्री सदानन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : जरा पहले शून्यकाल हो जाने दीजिये ।

श्री जितेन्द्र कुमार राय : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 10 मार्च को सारण जिले के गौरा ओ0पी0 के हथिसार निवासी जानकी प्रसाद की पुलिस द्वारा बेरहमी से पिटाई की गई । विरोध किये जाने पर पुलिस द्वारा निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया गया । मैं सरकार से जॉच कराकर दोषी पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई की मॉग करता हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय भाई वीरेन्द्र जी, शून्यकाल में जितनी सूचनाएँ आती हैं, सभी गंभीर होती हैं।

श्री जिवेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्रान्तर्गत दरभंगा जिला के जाले प्रखण्ड अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जाले में दिनांक 10.03.2018 को रात में रहस्यमय तरीके से आग लग जाने से बहुत सारे कागजातों, उपकरण को काफी नुकसान हुआ है । इसकी जॉच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करें ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिला अन्तर्गत बलरामपुर थाना कांड सं0-14/2018 में भाजपा नेता संजीव मिश्रा के बहनोई पंकज झा के हत्यारों की गिरफ्तारी एक महीना से अधिक बीत जाने के बाद भी नहीं हुयी है ।

अतः सरकार अविलम्ब हत्यारों को चिन्हित कर गिरफ्तारी एवं मृतक के आश्रित को दस लाख रूपये मुआवजा तथा सुरक्षा दे ।

श्री विनय बिहारी : अध्यक्ष महोदय, गन्ना किसानों को प्रभेद अनठानबे हजार दो हजार दो सौ चौबीस का मूल्य लौरिया चीनी मिल द्वारा प्रति क्विंटल दो सौ पैंसठ दिया जा रहा है । जबकि अन्य मिलों द्वारा दो सौ नब्बे रूपया दिया जा रहा है ।

सदन के माध्यम से मेरा अनुरोध है कि सरकार किसानों के साथ न्याय करे ।

श्री लक्ष्मेश्वर राय : महोदय, मधुबनी जिला के खुटौना प्रखंड के माधोपुर पंचायत के वघमरिया गॉव के महादलित एवं कमजोर वर्ग (अत्यंत पिछड़ा) को सरकार द्वारा पर्चा निर्गत किया गया । जमीन कब्जा शीघ्र कराया जाय ।

अध्यक्ष : सदानन्द बाबू कुछ कहना चाह रहे थे ।

श्री सदानन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य प्रह्लाद यादव जी ने जो कहा और आपने माननीय सदस्यों के आग्रह पर उसको संज्ञान में लिया लेकिन आपने कह दिया कि जॉच हो । यह जॉच की प्रक्रिया तो निरन्तर होती है, कह देने के बाद उसका कार्यान्वयन नहीं होता है, फिर ये लोग शांत हो जाते हैं । आप सदन के संरक्षक हैं और विधायकों के भी संरक्षक हैं, यह जितनी गम्भीर बात कही गई है, यदि समय-सीमा के अन्दर आप उसमें हस्तक्षेप करते हुये जॉच करवा कर मँगवा लेते हैं प्रतिवेदन तो यह ठीक रहेगा ।

अध्यक्ष : आप मंत्री जी, जॉच कराकर आप बताइयेगा ।

श्री सदानन्द सिंह : नहीं, प्रतिवेदन दें आपको ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

अब ध्यानाकर्षण सूचना ।

श्री जिवेश कुमार : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय विधायक फराज फातमी जी डेली अपना साईन करते हैं उपस्थिति रजिस्टर पर और हमारा हाजिरी डेली काट देते हैं ।

ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री राजीव नन्दन, जिवेश कुमार एवं अन्य बारह सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार [पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग] की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष : श्री राजीव नन्दन जी की सूचना पढ़ी हुई है । माननीय मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग विभाग ।

श्री बृज किशोर बिन्द, मंत्री : महोदय, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के नवीन एवं नवीकृत छात्रवृत्ति हेतु पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए विभागीय पत्रांक-183 दिनांक-23.01.2018 PR No-1250 (Welfare) 2017-18 के तहत ऑनलाईन आवेदन पत्र National Scholarship Portal Version-2.0(NSP-2.0) के वेबसाईट https://scholarship.gov.in के माध्यम से दिनांक-08.02.2018 से दिनांक-28.02.2018 तक आमंत्रित किए गए थे, जिसे विभागीय पत्रांक-440 दिनांक-28.02.2018 के द्वारा दिनांक-20.03.2018 तक विस्तारित किया गया है ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

सर्वश्री अशोक कुमार, वीरेन्द्र कुमार एवं श्री समीर कुमार महासेठ, स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार [सामान्य प्रशासन विभाग] की ओर से वक्तव्य ।

श्री अशोक कुमार(क्षेत्र सं0 208) : महोदय, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-9529, दिनांक- 01.07.15 द्वारा सभी सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी, सचिव, बिहार लोग सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्त्ती), परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, सचिव, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार सहित राज्य के सभी विभागों, निकायों को निर्देश जारी किया गया है कि सेरिब्रल पॉल्सी से प्रभावित अभ्यर्थी, जो लिखने में

सक्षम नहीं हैं, को श्रुतिलेखक की सुविधा उपलब्ध करायी जाय । राज्य के किसी भी विभाग, आयोग, निकाय द्वारा श्रुतिलेखक का कोई पूल नहीं बनाया गया है जिसके कारण किसी भी परीक्षा में सेरिब्रल पॉल्सी से प्रभावित अभ्यर्थियों को श्रुतिलेखक नहीं मिल पा रहा है और वे परीक्षा से वंचित हो जा रहे हैं ।

अतः राज्य के सभी विभागों, आयोग, निकायों में सेरिब्रल पॉल्सी से प्रभावित अभ्यर्थियों के लिये श्रुतिलेखक का पूल बनाये जाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

अध्यक्ष : सरकार का उत्तर ।

श्री रामनारायण मंडल, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, समय चाहिये ।

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, मैं पूछना चाहता हूँ ....

अध्यक्ष : समय चाहिये तो फिर अभी क्या पूछना है ?

श्री समीर कुमार महासेठ : विभाग के मंत्री चले गये, डिप्टी सी0एम0 भी चले गये.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप समीर जी, अब तो पुराने हुये । सरकार, सरकार होती है, वित्त मंत्री ही सरकार नहीं होते हैं ।

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, आपका संरक्षण चाहिये । पूरे देश में बिहार विकलांग और दिव्यांग में नम्बर वन आ रहा है, अगर सरकार समय ले रही है तो इसपर सही ढंग से सोचकर आवे ।

अध्यक्ष : समीर जी, अगर आपको आसन का संरक्षण प्राप्त नहीं होता तो यह ध्यानाकर्षण सूचना स्वीकृत कैसे होती ?

(व्यवधान)

सर्वश्री मनीष कुमार, रामप्रीत पासवान एवं अन्य चार सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार [वित्त विभाग / ग्रामीण विकास विभाग] की ओर से वक्तव्य।

श्री मनीष कुमार : अध्यक्ष महोदय, सरकार के लोक कल्याणकारी एवं विकास योजनाओं की राशि जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार से विभागों या जिलों को प्राप्त होती है, को वित्त विभाग के निर्देश के विपरीत निजी बैंकों में जमा करायी जाती है । वित्त विभागीय पत्रांक-5268, दिनांक-16.06.15 के अनुसार वैसे सभी बैंक खाते जो वित्त विभाग की सहमति के बिना खोले गये हैं, में बिहार कोषागार संहिता के नियम-34 का उल्लंघन हुआ है ।

उदाहरणस्वरूप ग्रामीण विकास विभाग के अधीन संचालित विभिन्न योजनाओं की राशि ऐसे खास निजी बैंकों में जमा करायी जाती है जो दूसरे निजी बैंकों से कम ब्याज दर पर सरकार को देती है । एक ओर तो राष्ट्रीय बैंक में सरकारी राशि जमा नहीं करायी जाती है, वहीं दूसरी ओर कुछ खास निजी बैंक में सरकारी राशि जमा कराकर सरकार को राजस्व की हानि पहुँचायी जा रही है ।

अतएव दोषी के विरूद्ध कार्रवाई करने एवं ज्यादा ब्याज दर देने वाली राष्ट्रीयकृत बैंक में सरकारी राशि जमा करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

अध्यक्ष : सरकार का उत्तर ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, यह मामला कई विभागों से संबंधित है, इसमें समय चाहिये ।

अध्यक्ष : ठीक है । अब सभा की कार्यवाही 2:00 बजे दिन तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(अन्तराल)

टर्न–9/आजाद/13.03.2018

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

वित्तीय कार्य

माननीय सदस्यगण, आज नगर विकास एवं आवास विभाग के अनुदान की मांग पर वाद–विवाद, सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । इसके लिए तीन घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है और इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जाएगा :–

राष्ट्रीय जनता दल	–	59 मिनट
जनता दल (युनाइटेड)	–	52 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	–	39 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	–	20 मिनट
सी0पी0आई0(एम0एल0)	–	02 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी	–	02 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	–	01 मिनट
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी	–	02 मिनट
निर्दलीय	–	03 मिनट

माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, अपनी माँग प्रस्तुत करें ।

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :–

''नगर विकास एवं आवास विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए 44,13,58,67,000/– (चौवालीस अरब तेरह करोड़ अनठावन लाख सड़सठ हजार) रूपए से अनधिक राशि प्रदान की जाए ।''

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : इस मांग पर माननीय सदस्य श्री भोला यादव, श्री रामदेव राय, श्री समीर कुमार महासेठ, डा0 मो0 नवाज आलम एवं श्री ललित कुमार यादव से कटौती प्रस्ताव

प्राप्त हुए हैं, जो व्यापक हैं और जिनपर सभी माननीय सदस्य विचार-विमर्श कर सकते हैं ।

माननीय सदस्य श्री भोला यादव का प्रस्ताव प्रथम है, अतएव माननीय सदस्य श्री भोला यादव अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री भोला यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

''इस शीर्षक की मांग 10/- रूपये से घटाई जाय ।''

अध्यक्ष महोदय, नगर विकास एवं आवास विभाग का जो शीर्ष है, इस शीर्ष की मांग 10 रू0 से घटायी जाय ।

महोदय, राज्य के अन्तर्गत नगर निकाय की स्थिति बद से बदतर है । महोदय, मेरा क्षेत्र शहर के चारों तरफ से घिरा हुआ है । इसीलिए यह प्रस्ताव मैं लाया हूँ । पूरे राज्य के अन्तर्गत जो नगर विकास एवं आवास विभाग की स्थिति है, पिछले वर्ष में 51 प्रतिशत से अधिक खर्च नहीं कर पाया है और इतना बुरा स्थिति है कि कोई भी नगर निगम को ले लीजिए या नगर निकाय को ले लीजिए, जल-जमाव की समस्या चारों तरफ है । बस स्टैंड जितना है, वह बद से बदतर है। किसी भी बस स्टैंड में मूलभूत सुविधा जो होना चाहिए, उसका अभाव है । पटना मेट्रो का वर्षों-वर्ष से जब से एन0डी0ए0 की गवर्नमेंट बनी है, तब से ये लोग ढिढोरा पीट रहे हैं लेकिन धरातल पर कहीं न तो मेट्रो का कोई चर्चा है, हरेक बार कहते हैं कि डी0पी0आर0 बनकर तैयार है। कुल मिलाकर के देखिए तो नगर निगम की स्थिति बद से बदतर है । भारत स्वच्छता मिशन से भारत सरकार ने जो पैसा दिया है, कोई एक नगर का बता दें जो स्वच्छ हुआ हो । ये लोग स्मार्टसिटी की बात करते हैं । स्मार्टसिटी की स्थिति इतनी खराब है कि जो पूरे राज्य में एक भी शहर ये बता दें कि स्मार्ट बन गया हो । जहां पर जल जमाव की समस्या नहीं हो, मूलभूत सुविधायें हों, पेयजल की समस्या नहीं हो । चारों तरफ हाहाकार है । इस विषय पर हमारे दल से कई वक्ता हैं, मैं बहुत समय नहीं लेना चाहता लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि दरभंगा नगर निगम के सराऊडिंग में मेरा भी कई पंचायत है और माननीय नगर विकास मंत्री जी मौजूद हैं, हम यह बताना चाहते हैं कि पिछले 10 वर्षों से दोनार से लेकर किनही पुल के बीच दरभंगा शहर के जल निकासी के लिए ..... (व्यवधान)

महोदय, पास तो बहुत पहले हुआ लेकिन स्थिति इतनी खराब है कि अभी तक टेंडर नहीं हुआ, ढिढोरा पीटने से नहीं होता है, अगर टेंडर हुआ तो एवार्ड हो जाना चाहिए ।

अध्यक्ष : संजय सरावगी जी, बोलने दीजिए माननीय सदस्य को ।

श्री भोला यादव : माननीय नगर विकास मंत्री जी, यदि हो गया है तो समय निर्धारित करें, मैं भी उसमें उपस्थित रहूँगा, उसका शिलान्यास करें और उसमें काम लगावें । चूँकि स्थिति यह है कि दरभंगा शहर के अन्तर्गत अधिकांश इलाका पानी से डूबा रहता है। उससे हमलोगों के इलाका में भी पानी आ जाता है । इसीलिए बहुत नारकीय स्थिति बन गया है ।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी दूसरा एक बात कहना चाहता हूँ कि इसमें पी0एच0ई0डी0 भी समाहित है । जिस समय हम बिहार विधान परिषद् के सदस्य थे, उस समय जो चापाकल योजना दिया गया था, उस चापाकल योजना में से हमलोगों का अनुशंसा उसी समय हुआ, लेकिन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के जो माननीय मंत्री जी हैं, उनका आदेश भी आ चुका है, लेकिन अभी तक चापाकल गाड़ने का काम नहीं हुआ । वहां के एजक्यूटिव इंजीनियर टेंडर ही नहीं निकालते और टेंडर नहीं निकलने के चलते वह चापाकल यथावत पड़ा हुआ है, उसको भी इम्पलीमेंट करावें । बहुत,बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रामसेवक सिंह ।

श्री राम सेवक सिंह : अध्यक्ष महोदय, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा लाये गये बजट के पक्ष में और विपक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री भोला बाबू के द्वारा जो कटौती प्रस्ताव लाया गया है, उसके विरोध में बोलने के लिए मैं खड़ा हूँ । अध्यक्ष महोदय, भोला बाबू के माध्यम से नगर विकास एवं आवास विभाग पर जो कटौती प्रस्ताव लाया गया है, उनका ध्यान हो सकता है कि 2005 के पहले के तरफ नजर हो । 2005 से 2018 के बीच में नगर का सूरत किस तरह बदला है, उसमें क्या स्थिति है । शहर में पटना नगर निगम को लीजिए, नगर निगम में जितने भी पार्क थे, आपके राज-पाट में उस पार्कों की स्थिति क्या बद से बदतर थी कि नहीं थी ? हमलोग जब सत्ता में आये, सैंकड़ो नगर निगम की जितनी भी पार्कें हैं, वह काफी सुन्दर है और उसका सौन्दर्यीकरण किया गया है । उसमें काफी विकास किया गया है । नगर विकास विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के माध्यम से पूरे बिहार के सभी प्रत्येक परिवार में नल से जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ही मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना प्रारंभ की गई है । इस योजना के क्रियान्वयन हेतु इसको चार पार्ट्स में बांटा गया है । एक है 250 की संख्या में, एक है 500 की संख्या में, एक है 1000 की संख्या में और एक है 1500 घरों की संख्या में । इसमें गुणवत्तापूर्वक हम कैसे शुद्ध रूप में सही तरीके से प्रत्येक घर में जल उपलब्ध करा दें, इसके तहत हमारी सरकार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नगर विकास एवं आवास विभाग के माध्यम से

योजनायें चलायी जा रही है । एक योजना है जिस तरह हम सात निश्चय के माध्यम से सुदूर इलाका में अपने सभी पंचायतों के माध्यम से, सभी परिवारों में नल जल योजना के माध्यम से हम जल प्रत्येक परिवार में देना चाहते हैं । उसी तरह मुख्यमंत्री शहरी नली-गली पक्कीकरण योजना निश्चय योजना के माध्यम से सभी शहर के जितने हमारे नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर वार्ड है, नगर पंचायत है, सभी पंचायतों में इस योजना के माध्यम से सभी घरों में जल देने का निश्चय सरकार के माध्यम से किया गया है । ..... क्रमशः .....

टर्न-10/अंजनी/दि0 13.03.18

श्री रामसेवक सिंह : क्रमशः.... इस योजना के तहत नगर निकायों की कुल संख्या लगभग 3377 वार्डों में जो वर्ष 2017-18 में प्रस्तावित था, उसमें 3,040 वार्डों में निविदा निकाली जा चुकी है और कुल 2692 वार्डों में कार्य प्रारंभ है । कुल अबतक 3340 योजना पूर्ण हो चुकी है, जिसमें 1 लाख 28 हजार 577 घर पक्की नाली गली का निर्माण हो चुका है । वित्तीय वर्ष 2017-18 में (व्यवधान) भोला बाबू, थोड़ा-सा सुनिए, आपका हम बहुत ध्यान से सुने हैं । वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित कुल 310 करोड़ रूपये मात्र कुल 140 नगर निकायों में आवंटित किया गया है । वर्ष 2018-19 में इस योजना के लिए 360 करोड़ रूपया का बजट का प्रावधान किया गया है, जिससे योजना में गति लाने में निश्चित रूप से सुविधा प्रदान होगी । अध्यक्ष महोदय, नगर विकास के माध्यम से प्रत्येक शहरी परिवार के लिए घरों में शौचालय के निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत नगर निकाय क्षेत्र में स्थित सभी शौचालय विहीन घरों में जिस तरह पंचायत के सुदूर इलाकों में हमारे ग्राम पंचायत में जिन परिवारों में शौचालय की सुविधा नहीं है, वहां शौचालय बनाने का सरकार का लक्ष्य है । उसी की कड़ी में हमारे नगर पंचायत, नगर निगम में इस योजना को लागू करने का लक्ष्य सरकार द्वारा रखा गया है । अध्यक्ष महोदय, नगर विकास के माध्यम से स्ट्रोम वाटर ड्रेनेज का निर्माण सभी शहरों के अन्दर काफी मात्रा में हुआ है । शहर का पानी बाहर कैसे जाय, उस योजना को लागू करने के लिए और सही तरीके से जल का निकासी कैसे हो, उस योजना के लिए भी सरकार ने अच्छी पहल की है । उसमें अनेक शहरों का चयन किया गया है । शहर में जैसा कि प्रस्ताव है और इसमें सहरसा, सासाराम, सुपौल, फुलवारीशरीफ, दरभंगा शहरों में जल जमाव की समस्या को दूर करने हेतु स्ट्रोन वाटर ड्रेनेज योजना स्वीकृत की गयी है । इसका क्रियान्वयन बुडको द्वारा

किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त 18 नगर निकायों में यथा नवादा, मसौढ़ी, शेखपुरा,रक्सौल,बक्सर,डुमरा,बिहिया,चकिया,सिलाव,जगदीशपुर,अरेराज,हिसुआ,जनकपुर रोड,राजगीर,ढ़ाका,वारसलीगंज,परसा बाजार एवं टेकारी में बड़े आउट फॉल नाला निर्माण की योजना स्वीकृत की गयी है । अध्यक्ष महोदय, नगर विकास एवं आवास विभाग के माध्यम से कई जगह, हमारे माननीय विपक्ष के सदस्य साथी बोल रहे थे कि कई जगहों पर बस पड़ाव नहीं है तो नागरिक सुविधा के लिए 39 नगर निकायों में बस स्टैंड का निर्माण की योजना स्वीकृत है, जिसमें 18 नगर निकायों में 60.33 करोड़ रूपये की लागत से बस स्टेंड का निर्माण हो चुका है । 13 नगर निकायों में कुल 42.31 करोड़ की लागत से बस स्टेंड का निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है । इसके साथ बस स्टेंड निर्माण की प्रक्रिया एवं उसके साथ ही 302.34 करोड़ रूपये की लागत से पटना में अन्तर्राज्यीय बस स्टेंड का निर्माण भी करने का सरकार का लक्ष्य है । सबके लिए आवास योजना शहर में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योजना हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लिया गया है । जैसे देहातों में हमलोग देखते थे कि इंदिरा आवास के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से सभी गरीबों को आवास देने की सुविधा थी लेकिन शहरों में इसकी सुविधा नहीं थी तो इसके लिए भी सरकार द्वारा योजनायें ली गयी है ताकि गरीब परिवारों को निश्चित रूप से आवास मिले और उनके रहने के लिए सुविधा प्रदान हो । अध्यक्ष महोदय, विभाग के माध्यम से पटना में मेट्रो रेल परियोजना का भी शुभारंभ होने की प्रक्रिया में है, इसको एन0आई0टी0 पटना और आर0आई0टी0ई0एस0 के संयुक्त तत्वावधान में केन्द्र सरकार की नयी मेट्रो नीति के दिशा निर्देश के अनुरूप डी0पी0आर0 तैयार किया जा रहा है, अगले वित्तीय वर्ष में संशोधित डी0पी0आर0 तैयार कर भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेज दिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, पूर्व में सरकार ने बिहार के 50 नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, कई जगह कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और उसके बाद गई जगह जमीन के अभाव में कहिए या उसकी जो प्रक्रिया है, वह प्रक्रियाधीन है, निश्चित रूप से वर्ष 2018-19 में जो 50 नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन का निर्माण होना है, वह निश्चित रूप से भवन निर्माण का कार्य पूरा कर लेने का सरकार का लक्ष्य है । अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2017 में हमारे पटना में शुकराना में श्री गुरू गोविंद सिंह जी की जयंती समारोह में, जो 350वॉं प्रकाशोत्सव प्रारंभ हुआ, उसमें देश के लोगों के साथ-साथ पूरे विश्व के लोग आये, जिसका परिणाम यह हुआ कि बिहार जैसे जगह में गुरू गोविन्द सिंह जी की 350वॉं जयंती अच्छी तरीके से जो सरकार द्वारा कराया गया, उसके लिए मैं सरकार

के अपने मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूँ और स्वागत करता हूँ । कई माननीय सदस्यों ने सवाल उठाया कि कब्रिस्तान के लिए राशि है लेकिन श्मशान घाट के लिए सुविधा नहीं है तो नगर पंचायत, नगर निगम और नगर परिषद में सरकार के माध्यम से शवदाह गृह निर्माण हेतु वर्ष 2017-18 में भागलपुर, मुंगेर, मोकामा, सिमरिया घाट एवं पहलेजा घाट में 95.55 करोड़ रूपये की लागत से विद्युत शवदाह गृह की योजना स्वीकृत की गयी है । इसके अतिरिक्त 12 नगर निकायों में शवदाह गृह के निर्माण हेतु 17.06 करोड़ रूपये की योजना स्वीकृत की गयी है । अध्यक्ष महोदय, नगर विकास के माध्यम से अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन योजना भी लागू किया गया है । 21 नगर निकायों के लिए कुल 2184.25 करोड़ रूपये की जलापूर्त्ति योजना तथा 27 नगर निकायों में 64.94 करोड़ रूपये का पार्क निर्माण योजना की स्वीकृति दी गयी है, जिसमें भागलपुर फर्स्ट फेज में 493 करोड़ और गया फर्स्ट फेज में 376 करोड़ एवं गया फेज-2 में 64.91 करोड़ रूपया की जलापूर्त्ति योजना प्रक्रियाधीन है और इसको निश्चित रूप से लागू करने का सरकार का लक्ष्य है । उसे भी हमारी सरकार निश्चित रूप से पूरा करेगी, इसमें दो राय नहीं है । अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के माध्यम से अन्य सारी योजनायें भी चल रही हैं । हम अपने पक्ष के साथ-साथ सभी विपक्ष के साथियों से आग्रह करेंगे कि सभी योजनाओं में आप सबों का भरपूर सहयोग चाहिए, ताकि हमारी सरकार की जो सोच है, हमारे दल के मुखिया और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो सोच है, उसमें निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी । जैसे कि मान लीजिए कि जो शराबबंदी है, बाल विवाह है, दहेज प्रथा है, अभी कई साथियों ने प्रश्न भी उठाया कि बालू की समस्या है तो जो भी नया कानून बनता है, उसमें कठिनाई आती है लेकिन कठिनाई के बाद राज्यहित में लाभ क्या होगा, उसके तह में जाने की जरूरत है । निश्चित रूप से हम समझते हैं कि आप सभी लोगों का सभी योजनाओं के कार्यान्वयन में सहयोग मिलेगा । अध्यक्ष महोदय, मैं अपने मीरगंज नगर पंचायत हथुआ विधान सभा क्षेत्र, मीरगंज नगर पंचायत है, उस नगर पंचायत के संबंध में हम माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करेंगे । वहां बस स्टेंड पड़ाव के लिए योजनायें स्वीकृत है लेकिन अभी तक उस योजना को पूरा नहीं किया गया है, इसलिए हम उनसे आग्रह करेंगे कि निश्चित रूप से उन योजनाओं पर ध्यान देते हुए तत्काल पूरा कराने की कृपा करेंगे । अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहते हैं कि मीरगंज नगर पंचायत में वर्ष 2016-17 में, वहां नगर पंचायत की कमिटी के माध्यम से डस्टबीन की खरीद की

गयी, उस डस्टबीन के प्रस्ताव में डस्टबीन खरीदा गया लेकिन एक साधारण बाल्टी खरीद कर लिया गया । डस्टबीन के प्रस्ताव में है कि 560 रूपया की दर से डस्टबीन खरीद की जायेगी लेकिन जो डस्टबीन खरीद किया गया, उस बाल्टी का वेल्यू 100 रूपया से भी कम है और जो खरीदारी हुई है, वह पांच हजार के तकरीबन है । (व्यवधान) जो खरीदारी हुई है, वह तो नगर पंचायत की कमिटी है, उसमें सरकार कहां इनवोल्व है ? हम सरकार को इस संबंध में ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि निश्चित रूप से इसमें जांच कराते हुए जो भी उसमें दोषी हो, उस पर तत्वरित कार्रवाई की जाय ।

क्रमशः...

टर्न-11/शंभु/13.03.18

श्री रामसेवक सिंह : क्रमशः....अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ हमारे नगर पंचायत मीरगंज के तरफ से 2016-17 में कुछ योजनाएं वहां से स्वीकृत हुई है । जो आपके नगर विकास एवं आवास विभाग में विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग में 06.03.17 को प्रस्तावित करके यहां दिया गया डी0पी0आर0 बनाते हुए हम मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि जो भी सारी योजनाएं दी गयी है उस योजना को निश्चित रूप से ध्यानपूर्वक देखते हुए उसमें जल की निकासी है और जल की निकासी के बिना शहर का सौंदर्यीकरण संभव नहीं है । जो नगर पंचायत की राशि है उस राशि से उस नाला का निर्माण नहीं हो सकता है । इसलिए हम अपने माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि नगर पंचायत में 2005 से 2017 तक काफी योजनाएं एप्रूव हुई है, उससे नगर में विकास की गति काफी बढ़ी है । जो अवशेष बचा हुआ है उन योजनाओं का जिक्र आपके विभाग में दिया गया है इसे निश्चित रूप से सुधार करने की कृपा करेंगे । अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी भी सदन में उपस्थित हैं । एक शहरी विकास के लिए जो मुख्यमंत्री विकास योजना जो शहर के लिए पहले राशि उपलब्ध होता था वह योजना अभी बंद है और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि शहर के विकास के लिए निश्चित रूप से उन योजनाओं को लागू करें ताकि जो हमारा अवशेष योजना बचा हुआ है उसे त्वरित गति देने में हमें सफलता मिले । मैं इन्हीं चन्द शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय आपका आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ । जय हिन्द, जय भारत ।

श्री नितीन नवीन : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज भोला बाबू जो कटौती प्रस्ताव पेश किये मैं उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ और कहीं न कहीं कटौती प्रस्ताव

पेश करते समय ही जो असहज भाव उनके अंदर दिख रहा था कि कटौती प्रस्ताव का कोई तर्क नहीं दे पाये इससे दिखा कि जो विपक्ष है वह कहीं न कहीं विभाग के इस बजट से अनुत्तरित है । मुझे लगता है कि इस विभाग का जो बजट आया है उसके समर्थन में विपक्ष को भी आना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय, आज जिस चीज की चर्चा करने के लिए हमलोग यहां बैठे हैं नगर विकास विभाग ने कई योजनाओं को लिया । जहां एक ओर पूरे बिहार में जल जमाव की स्थिति रहती थी 2005 के पहले आज 2018 में जब हम बैठे हैं तो यह सच्चाई है कि उस समय नाव चलता था, आज कई सड़कें पक्की नजर आ रही है । मुख्यमंत्री शहरी विकास हो यह सरकार की नीतियां हैं जिसके माध्यम से आज कई योजनाएं शहरों में हुई है । अध्यक्ष महोदय, केवल हमलोगों ने योजनाओं को करने का काम नहीं किया- अभी हाल में केन्द्र सरकार की योजना के अन्तर्गत दीन दयाल अन्त्योदय योजना के तहत जहां गरीब क्षेत्र में रह रहे युवक युवतियों को 36 हजार 267 बच्चों को प्रशिक्षित किया गया और उनमें से करीब 3 हजार छात्रों को नौकरी भी लगी तो शहर के गरीब बच्चों पर जहां सरकार का ध्यान रहा वहीं जो शहरी क्षेत्र में सेंटर फोर अर्बन होमलेस के लिए 48 नये जगह चिन्हित किये गये जिसमें 30 का निर्माण कार्य हो चुका है । जहां एक ओर रैन बसेरा में बड़ी संख्या में आबादी रहती थी, लोग रहते थे उसके लिए भी सरकार ने चिंता किया । यह सरकार केवल गरीबों की मसीहा शब्द वाली सरकार नहीं है, गरीबों की चिंता करने वाली सरकार है । उस रैन बसेरे में 6 लाख प्रति रैन बसेरा- 67 रैन बसेरों को स्वीकृत किया गया । यह सरकार की दूरदर्शिता दिखाती है, सरकार के गरीबों के प्रति चिंता दिखाती है । साथ ही साथ इस सरकार ने जहां स्वच्छता मिशन के तहत कई योजनाओं को लिया- स्वच्छता एक मिशन है, एक जागरूकता का अभियान है- मैंने कभी विपक्ष के साथियों को नहीं देखा कि वह स्वच्छता के मिशन में, इस जागरूकता के कार्यक्रम में नजर आये हों क्योंकि वे अपने मन को अभी स्वच्छ नहीं कर पाये हैं । मुझे लगता है कि जब तक वे अपने मन को स्वच्छ नहीं करेंगे तो स्वच्छता मिशन उनको दिखेगा नहीं । जहां तक सरकार की कई योजनाएं हैं अध्यक्ष महोदय, स्मार्ट सिटी के माध्यम से जहां आज चार शहरों का चयन किया गया पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ- 1 हजार करोड़ रूपया अगले पांच वित्तीय वर्षों में इन शहरों के विकास के लिए दिया जायेगा । स्मार्ट सिटी की कल्पना ही इनसे दूर है इसलिए इनको स्मार्ट सिटी दिखेगा नहीं । जहां तक स्मार्ट सिटी की कल्पना की बात है- मैं माननीय मंत्री जी को भी सुझाव दूंगा कि जितना जल्दी हो उसके एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया जाय क्योंकि

बिना एडवाइजरी बोर्ड के पूरी योजनाओं का संकलन नहीं हो सकता है । हम जनप्रतिनिधि उस एडवाइजरी बोर्ड में रहेंगे तो निश्चित रूप से सरकार की योजनाओं को गति प्रदान करने में सहायक होंगे । इसलिए हम माननीय मंत्री जी से इसके त्वरित कार्यक्रम को आगे करने के लिए एडवाइजरी बोर्ड का गठन तत्काल किया जाय, यह आग्रह करता हूँ । साथ ही साथ जिस चीज की चर्चा हमारे कई विधायक करते हैं सत्तापक्ष के विपक्ष के सभी साथी करते हैं । 2008 में बहुत ही दूरदर्शिता के तहत मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना को लागू किया गया था और 2008 से 2013-14 तक उस योजना का लाभ इतना मिला कि आज शहर की कई सड़कें जो बड़ी योजनाएं होती थी, जो विधायक निधि से नहीं हो पाता था, नगर निगम के पंचायत से नहीं हो पाता था उन बड़ी योजनाओं का काम इन शहरी विकास की योजनाओं से हमलोगों ने किया था । मुझे याद है उस समय एक-एक वित्तीय वर्ष में 2-2 सौ करोड़ रूपया उन योजनाओं में स्वीकृत कराकर अपने क्षेत्र में कराने का काम किया । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नगर विकास मंत्री जी आज यहां उपस्थित हैं । मैं सभी विधायकों के तरफ से विनम्र आग्रह करता हूँ कि माननीय मंत्री जी इस योजना को फिर से लागू कीजिए इससे बिहार में रह रहे शहरी क्षेत्र के विधायक को बड़ी ताकत मिलेगी । हम उन योजनाओं को कराने में सफल होंगे जो बड़ी योजनाएं वार्ड के परिधि में, पंचायत के परिधि में रहकर नहीं हो पाती है । इन शहरी योजनाओं को तत्काल हमलोगों को कराने की बड़ी सफलता मिल सकती है । साथ ही साथ वुडको योजना के अन्तर्गत कई योजनाएं माननीय मंत्री जी ने स्वीकृत कराया है, उन योजनाओं की चर्चा हम करना चाहेंगे । चाहे वह सिवरेज योजना हो, रिवर फ्रन्ट योजना हो, लेकिन इन योजनाओं के साथ-साथ मैं माननीय मंत्री जी से यह भी आग्रह करूँगा कि वुडको की जो ये योजनाएं हैं यह जिस जिला में होते हैं उस जिला के विधायकों के साथ बैठकर उन योजनाओं का एक प्रजेन्टेशन जरूर होना चाहिए । जब हमको अपने क्षेत्र की योजनाओं का प्रजेन्टेशन नहीं मिलता है, जब अधिकारी और कंट्रेक्टर काम करते रहते हैं तो वैसी स्थिति में न उनको सुझाव दिया जा सकता है, न उनके काम को रोका जा सकता है । हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि ऐसी योजनाएं चाहे जिस जिले में चल रही हो, बड़ी योजनाओं को कम से कम जनप्रतिनिधियों की सहभागिता से कराया जाय । जहां तक नगर विकास की कई योजनाओं की चर्चा की बात है, अभी हमारे कई प्रतिनिधि बता रहे थे कि चाहे पेय जलापूर्ति की योजना हो- शहर के क्षेत्रों में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो घर-घर नल जल की योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में तो लाभ हो ही रहा है, शहर के क्षेत्रों के लिए बड़ी

योजना स्वीकृत की गयी है । लेकिन हम आग्रह करेंगे माननीय मंत्री जी से कि इन जलापूर्ति योजनाओं को चूंकि पटना और शहर के क्षेत्रों में पानी को बड़े पैमाने पर आप निकाल नहीं सकते हैं । इसलिए उसको रोकने के लिए आनेवाले समय में एक कन्क्रीट प्लान बने नहीं तो बड़े पैमाने पर बोरिंग का काम शहर के क्षेत्रों में हो रहा है, अगर आप बड़ी योजना बनाते हैं तो कहीं न कहीं उन बोरिंग से जो व्यक्तिगत बोरिंग गरते हैं उससे आप बचा सकते हैं और आनेवाले समय में जो रिजर्व वाटर लेवेल होता है उसको हमलोग मेनटेन रख पायेंगे । अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि जिस प्रकार से पानी एक अनमोल चीज हो गया है इस देश और पृथ्वी के लिए हम सभी को इस पानी के संरक्षण के लिए जो भी उपाय हो उसके लिए जरूर करना चाहिए । घर-घर नल जल हम जरूर बोरिंग करके दे सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इन्टीग्रेटेड प्लान जब बनेगा तो उसकी वाटर लेवेल पर भी चेकिंग होगी और सरकार के माध्यम से हर घर जल भी पहुंच पायेगा । अभी हाल में माननीय मंत्री जी ने और विभाग ने बड़ी योजना मेरे क्षेत्र के लिए भी लागू की और पूरे पटना के लिए सिवरेज ड्रेनेज सिस्टम की बात जो हमारे पूर्व के वक्ता कर रहे थे उसी में पटना के लिए भी 44 करोड़ की योजना जक्कनपुर के इलाके का करीब 3 लाख की आबादी के लिए स्वीकृत हुआ है । इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से पिछले पांच साल से लगातार- माननीय मंत्री जी ने इसको स्वीकृत किया, विभाग ने स्वीकृत किया इसके लिए मैं तहेदिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से । साथ ही साथ अभी मेट्रो ट्रेन की चर्चा कर रहे थे, कल्पना से दूर है उनके, वे जरूर इसमें परेशानी देखते होंगे । मेट्रो का सपना हमारी सरकार ने देखा है नीतीश जी और मोदी जी ने देखा है तो निश्चित रूप से पटना मेट्रो ट्रेन बहुत जल्द आपके सामने आयेगा, विपक्ष के साथियों को मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आज अगर दिल्ली में भी मेट्रो आया तो मदन लाल खुराना हमारे नेता थे उनकी कल्पना थी और आज पूरे दिल्ली में मेट्रो दौड़ रही है तो आप निश्चिंत रहिये पटना मेट्रो भी बहुत जल्दी दौड़ेगा । हम माननीय मंत्री जी से भी आग्रह करेंगे कि इसको और स्पीड करके हमलोग आगे बढ़ायें ।

क्रमशः

टर्न-12/अशोक/13.03.2018

श्री नितिन नवीन : क्रमशः साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें हैं अध्यक्ष महोदय जो माननीय मंत्री जी के माध्यम से मैं अपने क्षेत्र के लिए जो कुछ योजनाओं हैं जो जल जमाव की परेशानी की सबब बनती हैं, उसमें एक बड़ी योजना अभी 44 करोड़ की योजना आपने स्वीकृत किया जो बेऊर बाईपास से लेकर सिपारा पुल तक हैं लेकिन उसी

में मीठापुर से लेकर नंदलाल छपरा तक, बाईपास से जब तक नाला स्वीकृत नहीं होगा तब तक उस पूरी योजना का लाभ हमलोगों को नहीं मिल पायेगा। उसी तरह से कंकड़बात–अशोकनगर जीरो प्वायंट पर एक बड़ी योजना पर पिछले दो साल से काम चल रहा है, उसको इस बार बरसात के पहले कराना बहुत जरूरी है नहीं तो कंकड़बाग का थोड़ा सा इलाका फिर से डूबन की स्थिति हो सकती है । साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट नगर के सम्प हाऊस को भी दुरूस्त करने की आवश्यकता है । 2015–16 में अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला में अमृत योजना के तहत 75 करोड़ स्वीकृत हुये थे, उस योजना को शुरू करने की दिशा में मैं मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि मंत्री जी यथाशीघ्र प्रयास करें साथ ही साथ ही अध्यक्ष महोदय,

अध्यक्ष : अब एक मिनट में समाप्त करेंगे ।

श्री नितिन नवीन : एक मिनट में समाप्त कर रहा हूँ । अध्यक्ष महोदय, सरकार ने लगातार पटना को और कई शहरों को पार्को का शहर बनाने का प्रयास किया और पटना को भी कई पार्क मिले और माननीय मुख्यमंत्री के विजन के साथ । लेकिन कई और पार्को की आवश्यकता है और साथ ही साथ माननीय मंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि पार्को के मैन्टेनेन्स के लिए जो पॉलिसी बननी थी उस पर काम यथाशीघ्र हो चूंकि जितनी बड़ी संख्या में सरकार का पैसा उन पार्को में लगा है, उसकी पॉलिसी की बगैर बात करेंगे तो निश्चित रूप से भविष्य में मैन्टेनेन्स का काम अच्छा नहीं हो पायेगा । मैं माननीय मंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि जिस स्वभाव से लगतार अपने विभाग को देंख रहे हैं हम सभी विधायकों को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री शहरी विकास आपके नेतृत्व में फिर से शुरू होगा और हम शहर के विधायकों को इसका लाभ मिलेगा । बहुत बहुत धन्यवाद और अध्यक्ष महोदय को भी धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, नगर विकास एवं आवास विकास की प्रस्तुत मांग पर लाये गये कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूँ । आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ । महोदय, शहर का मतलब ही होता है कि शहर के बारे में जब आप कोई भी शहर में जाते हैं तो एक सोच बनाते हैं कि शहर का सोच क्या है । शायद आप बिहार में कहीं चले जायं और वह जो परिकल्पना है जब आप बिहार से बाहर जाते हैं और अपने यहां आते हैं तो थोड़ा से जो डिफरेंस, जो हमलोग देखते हैं, संयोग है अच्छा है। माननीय मंत्री जी हमारे इंजीयिर है और शहर से भी आते हैं और शहर के प्रति दर्द भी ज्यादा होगा चूंकि बार बार जीतने वाले हमारे संजय जी है आगे जितना कष्ट

दरभंगा जिला को मिल रहा है शायद उसे सही ढंग से सरकार को नहीं बता पा रहे हैं । निर्णय अपना करें, सोच अपना है, और यहीं कारण है, यही कारण है हम नाम नहीं बोलेंगे, दरभंगा(व्यवधान) शहर का मतलब होता है कि ग्रामीण के परिस्थिति में जब कोई ब्लॉक से कोई चाहता है कि अच्छा जीवन जिये तो पंचायत से ब्लॉक में जाता है, ब्लॉक से शहर में जाता है । शहर से पटना आता है और पटना से दिल्ली, मुम्बई जाता है । लेकिन जब हम पुनः एक बात की जब चर्चा करते हैं कटौती प्रस्ताव दस रूपया से जो मांग रखा गया है काटने का इसके पीछे केवल यही है कि हम इसलिये आते हैं कि जितना हम दे पा रहे हैं क्या आप सक्षम होकर काम कर रहे हैं ? क्या आपके बजट का कितना परसेंट खर्चा हुआ और जहां-जहां दिया गया पैसा, पैसा सही ढंग से खर्च हुआ या नहीं ? यह जिम्मेवारी किसकी थी अगर सरकार की जिम्मेवारी थी तो स्टार्ट विथ आपने पंचायतों सम्मानपूर्वक आपने जो मानदेय भत्ता रखा, बार बार उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे कि मानदेय भत्ता देंगे, वो चाहते नहीं थे, लेकिन अपेक्षाकृत कम मानदेया भत्ता दिया गया क्या कहीं न कहीं हम दूसरे तरफ, क्या हम यह नहीं देखते हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त जितने लोग हैं चाहे जो हैं क्यों हैं ? जब आपका कहीं पर मानदेय मान सम्मान नहीं मिलेगा कहीं न कहीं श्रोत दूसरा निकाल लेंगे । हमने कहा था पहले भी, आप जब चेयरमैन का एलेक्शन कराते हैं, आप एक्ट में परिवर्त्तन करइये और एक्ट में परिवर्त्तन इसलिये करना आवश्क है चूंकि आप हौर्स ट्रेडिंग रोक सकें, क्या सरकार यह चाहती है कि नहीं कि हौर्स ट्रेडिंग रोकें । माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि लेकिन उनका शासन और सत्ता उनको अपना विश्वास है गांव पर और दूसरे पक्ष के जो लोग हैं उनका सोच है कि शहर मेरा है, आवश्यकता है, शहर की अभी चर्चा कर रहे हैं शहर पर चर्चा करते वक्त आप देंख लें । आपको मैं कह रहा हूँ कि कहीं आप चले जायं, चाहे नगर निगम हो, चाहे नगर परिषद् हो, चाहे नगर पंचायत हो आप कहीं की भी चर्चा कर लें किसी नगर निगम में तब आप जाकर के देंख लें पटना से शुरू से करें कि दरभंगा से शुरू करे, कि मुजफ्फरपुर से शुरू करें, कि भागलपुर से शुरू करें कि कहां से शुरू करें आप बतायें और उसके बाद हमलोग सोचे और पुनः हम सोच कर चलेंगे कि सोच अच्छा होना चाहिए और इस सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं चाहे वह कोई भी नगर निगम , कोई भी नगर परिषद् हो, कोई भी नगर पंचायत हो आवश्यकता जो वहां की जनता की मूलभूत है वह मिलनी चाहिये क्यों हमलोग आपस इस सोच के साथ चलते हैं कि जो शहर है आबादी दिनानुदिन बढ़ती जा रही है जब उस रूप में बढ़ती जा रहीं है जिसका भविष्य का निर्णय सही ढंग से

नहीं कर पाते हैं इसलिए कहीं न कहीं यह व्यवधान होता है । जब पटना का यह छोटा ब्रीज बना था, पांच साल में छोटा पड़ गया कहीं भी आप चले जाइये जो आपकी प्लानिंग होती है, ढंग से प्लानिंग नहीं होती हैं, कहीं आपको होना चाहिये था पहले ही नगर विकास का यह डिमान्ड होना चाहिये था इस सोच के साथ जितना भी नगर निगम है हम किस स्तर पर ठीक, सोच तो बहुत रखे थे पहली बातर 2006 में नगर विकास संयोग से भारतीय जनता पार्टी के पास ही था, उस समय क्या सोच था,ठीक है उस समय जो था, उसका डेवलपमेंट होता चला गया, एम.एल.ए. बने, मंत्री बने, एम.पी. बने, केन्द्र में मंत्री बने लेकिन हम वहीं हैं, बिहार की जनता वहीं है, बिहार की जनता रो रही है, आपलोग ढकोसला करके आगे बढ़ते चले गये, आगे बढ़ रहे हैं बेस आपका वहीं है, लगता है उसी बेस के आधार पर बढ़ रहे हैं और उस समय पटना को कहा जाता था कि हम इसको सिंगापुर बनायेंगे, क्या आज हम पटना के विधायकों से अपेक्षा कर रहे हैं कि हम सिंगापुर में हैं ? अगर सिंगापुर हैं तो हमे कुछ नहीं कहना है । एक शब्द नहीं बोलना है कि जनता देंख रही हैं, जनता देंख रहीं है कि आपका सोच, आपके मंत्री जी का सोच जिस ढंग से आपलोग पैर में उनको जिस ढंग से बांध देते हैं तो हमको लगता है कि पहले भी वही सरकार थी 2005 के बाद एक्ट में परिवर्त्तन हुआ इस सोच के साथ आप पूर्णतः अधिकार देंगे, त्रिस्तरीय पंचायत को अधिकार देकर के पूर्ण शासन लायेंगे, आपने कौन सा शासन लाया, कौन सा नगर निगम को स्ट्रॉग किया? आप अपना अधिकार अपने तरफ रखना चाहते हैं, सरकार वह अधिकार अपने तरफ रखना चाहती है, जो अधिकार उनका है वह देना नहीं चाहती है । पहला हमारा वही से शुरू होता है, अधिकार उसको नहीं देंगे सफल आप कैसे होंगे । सफल होगे तब ही जब उनको अधिकार देंगे । महोदय किसी भी शहर के लिए उसका टाऊन प्लानिंग आवश्यक है, कहीं भी चले जाइये बिहार छेड़कर कहीं चले जाइये पहले सड़के बनती है, सिवरेज सिस्टम होता है तब मकान बनता है । आपके यहां क्या हो रहा है ? कौन सी प्लानिंग है इसलिऐ आग्रह होगा कि सबसे पहले कोई भी शहर का टाऊन प्लानिंग आवयश्यक है । अगर मधुबनी है तो उसे ग्रेटर मधुबनी बनाया जाय, यह कोई भी शहर है, झंझारपुर है तो ग्रेटर झंझरपर ही क्यों नहीं बने, आवश्यकता इस बात का है कि सोच आपकी पचास साल की है,आप की प्लानिंग होनी चाहिये अब पचास साल के आगे तक का अगर प्लानिंग करते हैं तो सरकार का भी हमारे पास बड़ी बड़ी उपलब्धियों का चिट्ठा है, लेकिन उपलब्धि के नाम पर है क्या ? उपलब्धि के नाम पर है क्या । हमारे यहां माननीय मुख्यमंत्री जी दो बार गये, एक बार 4.5.2016 को प्रमण्डलीय समीक्षा बैठक के

तहत गये थे , दूसरी बार 16.11.2016 को चेतना यात्रा के माध्यम से गये थे और जिन बातों की हमने चर्चा की थी और वहां जाकर के दिखलया गया । आज मधुबनी से दस एम.एल.ए. आपके हैं, दसों एम.एल.ए. बतला दे अपनी छाती पर हाथ रखकर कि मधुबनी में जब घुसते हैं, हम आप क्या घुस पायेंगे, एम्बुलेंस भी रूक जाता हैं, पेशेंट भी मरने की स्थिति में है, कोई सिस्टम उस ढंग का नहीं बन पा रहा है दोष किसका है ? दोष अगर है तो पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों का हैं अगर है तो आप मूल्यांकन कर लें । ... क्रमशः...

टर्न-13/13-03-2018/ज्योति

क्रमशः

श्री समीर कुमार महासेठ : आप मूल्यांकन कर लें कि 2018 के बाद कौन मंत्री किस पार्टी के ज्यादा हुए और कौन बढ़िया से किसने क्या काम किया और आप जहाँ भी कुछ प्लानिंग करते हैं, कोई अगर एक बार चेयरमैन बनता है तो पांच साल के लिए बनता है, पाँच साल तक उसको काम करने का उसको छूट नहीं मिलेगी, तो कैसे कोई काम करेगा । आप एक तरफ जिस तरह से प्रस्ताव लाते हैं, जिस ढंग से बजट भेजते हैं क्या होगा ? कौन सी सड़के बनेंगी, कौन सा सिवरेज सिस्टम बनेगा, कौन सा कैनाल बनेगा, कौन सी बिजली स्ट्रीट लाईट लगेगा । अभी माननीय सदस्य पक्ष के बोल रहे थे कि जब खरीद शुरु हुआ, तो एल.ई.डी. लाईट कितने पैसे में खरीदी गयी डस्टबीन खरीदा गया, तो कितने पैसे लगे, क्या बात सही है कि आप एक तरीका निकालें, उस तरीका के आधार पर सिस्टम बनावें और अब तो सही माने में हरेक चीजों में जो आज की स्थिति है .....

सभापति (डा0 रंजू गीता): माननीय सदस्य समीर बाबू अब आपका समय समाप्त हो रहा है ।

श्री समीर कुमार महासेठः हमारी पार्टी की तरफ से है । आवश्यकता है कि जिस रुप में हम चल रहे हैं हमको कहीं न कहीं अपनी तरफ देखना है और मधुवनी की तरफ हम कुछ चाहेंगे कि नगर में जो पूर्व से बने किंग्स कैनाल, वाटसन कैनाल है, राज कैनाल हैं, बार बार इसके लिए पिछले तीन साल से हम आग्रह कर रहे हैं माननीय मंत्री जी उस तरफ ध्यान दें और जल्द से जल्द उसको कराने की व्यवस्था करें और जहाँ तक पेय जल का है, तीन ईच की पाईप से पेय जल दे रहे हैं । कैसे तीन ईच की पाईप से और जब वह दोनों तरफ का रोड तोड़ती है साईड में फ्लैंक तोड़ती है, वह भरी नहीं जा रही है, उसके लिए निधि की व्यवस्था नहीं है और अगर उस पर ट्रक चल जायेगा तो फिर वह पाईप टूट जायेगी और डायरेक्ट पम्पिंग सिस्टम से एक तो जरुर फायदा है, जहाँ चापाकल से जितनी आवश्यकता है,

उतनी ही पानी लेने का और अगर आप इस ढंग से व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, तो दस गुणा पानी बर्बाद होगा, जिसके बारे में आपकी सोच नहीं है और जिनको यह फायदा होना चाहिए उस परिवार को नहीं मिलेगा । एक साथ सड़क और नाला ऐसे बनेगा .....

सभापति (डा0 रंजू गीता): माननीय सदस्य, अब समाप्त करें । आपकी ही पार्टी के और लोगों को बोलना है ।

श्री समीर कुमार महासेठ : दो मिनट, अब अंतिम कह रहे हैं । हमारे यहॉ मधुवनी में बाई पास चूँकि हमने जो चर्चा की कि एम्बुलेंस में मर जाते हैं इसलिए बाई पास की बहुत आवश्यकता है और उसपर ध्यान जाय और शहरों में चाहे पूरे बिहार में जितना तालाब आपके शहर में है, वह कम से कम उसका अधिकार नगर निगम, चाहे नगर परिषद को मिलना चाहिए, वह कहीं न कहीं अधिकार दूसरे को है, जिसके चलते उसका साफ सफाई नहीं हो पाती है । आगे हमारा अनुरोध होगा कि कहीं न कहीं हमलोग .....

सभापति (डा0 रंजू गीता): माननीय सदस्य अब आप समाप्त करें । माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा ।

श्री अजीत शर्मा : सभापति महोदया, मैं नगर विकास एवं आवास विभाग पर अपनी बात रखना चाहूंगा । आजादी के बाद देश में तीव्र गति से .....

सभापति (डा0 रंजू गीता): माननीय सदस्य अजीत शर्मा जी, आपका समय 8 मिनट है ।

(व्यवधान)

श्री अजीत शर्मा : नहीं, भविष्य तो मेरा ऊपर वाला तय करेगा लेकिन अभी का समय वह तय किए हैं । देश में कई राज्यों में विकसित और सुविधा संपन्न नगरों का निर्माण हुआ लेकिन खेद है कि आजादी के इतने वर्ष के बाद भी बिहार के नगरों का विकास अपेक्षाकृत काफी कम हुआ है । कटु सत्य तो यह है कि नगरों के विकास के क्रम में देश के कई छोटे छोटे राज्य हमसे काफी आगे हैं । कई राज्यों में नये नये शहर विकसित हुए जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान है । बिहार में नये शहरों की विकास दूर की बात है, हमारे राज्य के पुराने शहर आज भी अपने विकास की बाट जोह रहा है, जिसकी वजह से आज भी हमारे राज्य के अधिकांश शहरों की पहचान स्लम सिटी के रुप में है । इसकी वजह नगरीय विकास की समेकित एवं समुचित योजना का अभाव रहा है । अगर विकास कहीं कुछ दिखता है, तो वह मात्र पटना शहर में थोड़ा दिखता है । पटना के अलावे राज्य के अधिकांश शहर आज भी विकास से कोसों दूर है । मेरा निर्वाचन क्षेत्र का संपूर्ण इलाका नगर निगम के अंतर्गत आता है । ऐसे में मेरे निर्वाचन क्षेत्र के विकास का सीधा वास्ता नगर

विकास विभाग से संबंधित है । ज्ञातव्य हो कि बिहार में भागलपुर नगर सबसे पहले केन्द्र सरकार के स्मार्ट सिटी योजना के तहत चयनित कर लिया गया था । जब इसकी खबर भागलपुर की जनता को लगी, तो लोगों की यह जिज्ञासा और विश्वास भी मजबूत हुआ कि भागलपुर में अब नगर विकास रफ्तार पकड़ेगा और यहॉ की जनता को तो तमाम सुविधाा उपलब्ध होगी, जिसकी कमी यहॉ की जनता वर्षो से महसूस कर रही थी लेकिन इस घोषणा के दो वर्ष बाद भी मंत्री जी बैठे हुए हैं, यहॉ की जनता नगरीय सुवधिा से पूरी तरह महरुम है, यहॉ जनता अब भी उन मूलभूत समस्याओं से लगातार जूझ रही है, जिसके प्रति सरकार अपनी प्रतिबद्धता बार बार दुहराती रही है लेकिन परिणाम शून्य रहा है । निगम क्षेत्र में विकास की सारी परियोजनाओं का कार्यान्वयन नगर निगम के माध्यम से होता है, जिसमें सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सात निश्चय भी शामिल है, जबकि नगर निगम की सम्पूर्ण कार्यवाही में स्थानीय विधायक की भूमिका गौण रखी गयी है, जिससे मुझ जैसे विधायकों को विकास की योजनाओं को नगर निगम के भरोसे पूरी तरह रहना पड़ता है, जिससे जन शिकायतों और जन सुविधाओं के निदान हेतु हमारे सामने विवशतापूर्ण स्थिति रहती है । इसका समाधान तभी संभव है जब स्थानीय विधायक की भूमिका पूरे बिहार में नगर निगम के विकास योजनाओं एवं तत्संबंधी निर्णयों हेतु कानूनी रुप से सुनिश्चित किया जाय । भागलपुर, पटना के बाद बिहार का दूसरा सबसे बड़ा नगर है जिसका विस्तार विगत कई दशकों से तेजी के साथ हुआ है । नगर के नव विकसित मुहल्ला में जन सुविधाओं जैसे सड़क, पानी, बिजली, नाला इत्यादि का अभाव है, ऐसे मुहल्लों में बिजली की आपूर्ति जर्जर लकड़ी के खम्भों के माध्यम से होता है, जिससे हमेशा जान माल के नुकसान की संभावना बनी रहती है, अतः मेरी मांग हैं कि पूर्व की तरह नगर निगम में विधायक का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाय और विधायक द्वारा अनुशंसित योजनाओं के क्रियान्वयन को अपरिहार्य बनाया जाय, तब ही जन आकांक्षाओ के अनुरुप अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम कर सकेंगे । जहॉ तक स्मार्ट सिटी जैसे महत्वाकांक्षी योजनाओं का मामला है, इस मामले में भागलपुर की जनता को अब तक निराशा ही हाथ लगी है, क्योंकि विगत दो वर्षो में इसकी योजना सरजमीं पर कहीं दिखायी नहीं दे रहा है, क्योंकि स्मार्ट सिटी बोर्ड का गठन ही पूरी तरह दोषपूर्ण एवं भ्रामक है, जिसमें अधिकारियों के अलावा एक मात्र महापौर को आमंत्रित सदस्य के रुप में रखा गया है । मेरी मांग है कि स्मार्ट सिटी बोर्ड में स्थानीय विधायक की निर्णायक भूमिका सुनिश्चित की जाय, तब ही जन भावना के अनुरुप शहर का विकास संभव हो सकेगा । आज भागलपुर शहर की सबसे बड़ी समस्या प्रति दिन जाम लगने के

कारण है, जिसकी वजह सकरी सड़कें एवं बीच सड़क पर बिजली का पोल है । इस संदर्भ में मेरा सुझाव है मंत्री जी से कि सारे बिजली पोल को हटा कर भूमिगत नाला, कलकत्ते में आप देखें होंगें, ह्यूम पाईप का बड़ा बड़ा चार से पॉच फीट डायमीटर का नाला लगता है, उसके ऊपर क्लैम्प लगकर बिजली का तार जाता है, भूमिगत किया जाय, जिससे सड़कें काफी चौड़ी हो जायेंगी एवं यातायात सुलभ हो जायेगा । साथ ही साथ भागलपुर शहर में जाम से निजात के लिए प्रमुख चौराहों पर फ्लाई ओवर ब्रीज का निर्माण अपेक्षित है । तब ही आप स्मार्ट सिटी की कल्पना कर सकते हैं । आज भी भागलपुर शहर के लोगों को पर्याप्त शुद्ध पेय जल की आपूर्ति नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां शताब्दी पूर्व निर्मित जल संयत्र जर्जर हो चुका है, विशेष कर गर्मी के दिनों में जब गंगा नदी की जल धारा संयत्र से दूर हो जाती है, तो शहर के लोग जल आपूर्ति से वंचित हो जाते हैं । शहर में जल आपूर्ति हेतु नियुक्त आपके संवेदक कंपनी पैन इंडिया की लचर व्यवस्था योजना की धीमी गति के कारण अब तक अपने कार्यों में विफल रहा है । यह कंपनी निर्धारित समय में शहर में अब तक पाईप लाईन नहीं बिछा पायी है, जिससे हमें नहीं लगता है कि यह काम वह पूरा कर पायेगे । सभापति महोदया, जैसा कि आपको ज्ञात है, भागलपुर, पटना के बाद बिहार का दूसरा सबसे बड़ा नगर शहर है, जो पूरी दुनिया में सिल्क सिटी के रुप में विख्यात हैं । यहॉ बिक्रमशीला जैसे प्राचीन विश्वविद्यालय जैन धर्म के दौदहवें तीर्थाकार भगवान वासुपूज्य की जन्मभूमि अवस्थित है । यहॉ से वायुयान सेवा नहीं होने की वजह से शहर का विकास और व्यवसाय दोनों बुरी तरह प्रभावित हैं । जिसकी वजह से सिल्क व्यवसायी, देश भर के पर्यटक, आपात स्थिति में मरीज अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते हैं । अतः आग्रह है मंत्री महोदय से स्मार्ट सिटी कल्पना साकार तब तक नहीं होगा, जब तक हवाई सेवा नहीं होगी । यहॉ यथाशीघ्र हवाई सेवा शुरु की जाय । हवाई सेवा के बिना स्मार्ट सिटी की कल्पना ही बेकार है ।

सभापति (डा0 रंजू गीता) : माननीय सदस्य जहॉ तक मेरी जानकारी है कि हवाई सेवा शुरु हो चुकी है भागलपुर, दरभंगा के लिए ।

श्री अजीत शर्मा : भागलपुर में नहीं शुरु हुई है मैड्म ।

सभापति (डा0 रंजू गीता) : हवाई सेवा शुरु होने जा रही है ।

श्री अजीत शर्मा : नहीं, अभी तक नहीं हुआ है जैसा कि आपको मालूम है ।

(व्यवधान)

मेरा टाईम सरावगीजी क्यों ले रहे हैं आप ।

विधायक की अनुशंसा पर योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा स्पष्ट रुप से निर्देशित किया गया है, जिसकी वजह से नगर निकाय द्वारा विधायक के अनुशंसा को गंभीरता के साथ नहीं लिया जाता है । मंत्री महोदय हमलोगों की अनुशंसा नगर निगम में नहीं ली जाती है, अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करुंगा कि सरकार पूरे नगर निकाय में विधायक की निर्णायक भूमिका सुनिश्चित करने के साथ साथ यह भी निर्देशित करें कि हमारी अनुशंसा को प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वित करें, तब ही हम नगरों का समुचित विकास कर जन आकांक्षाओं को सरजमीं पर उतार सकते हैं ।

क्रमशः

टर्न–14/13.3.2018/बिपिन

श्री अजीत शर्माः क्रमशः ... आपको मंत्री जी, एक बात और, मैं पहली बार विधान सभा में बोले थे, जब तक स्टाफ जो वहां नौकरी में बहाल होता है, वहीं पर रिटायर करता है । जब तक आप एक नगर निकाय से दूसरे नगर निकाय ट्रांसफर नहीं करेंगे, तब तक विकास असंभव है, चूंकि वो कुंडली मार कर बैठा रहता है । इसलिए आप एक नगर निकाय से ट्रांसफर निश्चित करें और जैसाकि नीतीश जी और सबलोग कह रहे थे कि मंत्रीजी, जो मुख्यमंत्री नगर विकास योजना जो बंद कर दिया गया, निश्चित तौर पर हम भी सहमत हैं कि वह निश्चित तौर पर यह फिर से चालू होना चाहिए ताकि नगर का विकास हो, चूंकि नगर के विकास से ही पूरे गांव में मैसेज जाता है कि आप काम क्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं । इसलिए शहर को आपको देखना बहुत जरूरी है और दूसरी बात मंत्री जी, मेयर का चुनाव निश्चित तौर पर जनता के माध्यम से होना चाहिए, तभी आपका शहर पूरे विश्व में जाना जाएगा कि यह शहर हमारा पूरे बिहार का...

(व्यवधान)

दूसरे और बहुत सारी बातें हैं लेकिन समय इतना कम दिए हैं कि मेरा तो आठ मिनट पूरा हो रहा है लेकिन मैं मंत्री जी, आप विशेषकर भागलपुर में आप जाएं और देखें क्या स्थिति है? आपके स्मार्ट सिटी में कोई काम नहीं हुआ है, नगर निगम में डिसिप्लिन की कमी है । कोई काम नहीं हो रहा है । दो वर्षों में आप देखेंगे सड़क, नाला, मुख्यमंत्री शहर विकास योजना बंद होने के बाद कोई विकास नहीं हो रहा है जिससे सरकार की बदनामी और हम प्रतिनिधियों की बिल्कुल बदनामी हो रही है कि हमलोग कोई काम नहीं कर रहे हैं । इसलिए शहर पर निश्चित तौर पर ध्यान दिया जाए । धन्यवाद । जयहिंद ।

सभापति (डॉ0 रंजू गीता): माननीय सदस्य श्री चन्द्रसेन प्रसाद । आपका समय पांच मिनट है ।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद: माननीय सभापति महोदया, आज नगर विकास और आवास विभाग के बजट के पक्ष में बोलने का मौका आपने दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं ।

हम जब नगर विकास और आवास विभाग की चर्चा करते हैं तो हम वह दिन याद करें जब बिहार का विभाजन हुआ था और विभाजन के बाद बिहार सरकार बिहार में जितने शहरें थी और बिहार के बाहर जो शहरें चली गई उसको एक नजर देखने की जरूरत है सभापति महोदया । आज हम नगर विकास की बात करना चाहते हैं, नगर विकास जब 2005 में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब सरकार में उन्होंने सत्ता संभालने का काम किया तो उस समय के पटना को याद कीजिए । उस समय पटना, जब पटना लोग आते थे तो लगता था कि कहीं कोई जंगल में पहुंच गए है । न बढ़िया सड़कें थी, न ही ओवरब्रिज था, न ट्रैफिक के संचालन का कोई व्यवस्था था और न ही कोई व्यवस्था थी । हम कहना चाहते हैं कि उस पटना को जंगल राज कहिएगा तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगा महोदय ।

महोदय, नगर विकास विभाग जब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब बिहार में परिवर्त्तन आया तो परिवर्त्तन देखने लायक है महोदया । परिवर्त्तन, किस तरह का परिवर्त्तन ? हर क्षेत्र में परिवर्त्तन, एक सिस्टम का परिवर्त्तन ...

(व्यवधान)

सभापति(डा0 रंजू गीता): कृपया शांति ।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद: लोग देखते थे कि पटना में जो लोग रहने का काम करते थे, वह चाहते थे कि पटना में नहीं रहकर हम कहीं देहात में रहें । आज जो पटना की हालत है, जो भागलपुर की हालत है, जो मुजफ्फरपुर की हालत है, बिहार शरीफ, मुंगेर आज देखने लायक है महोदया । हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और माननीय उपमुख्यमंत्री श्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि बजट में आपने जो प्राक्कलित राशि का आवंटन किया है, देहात से कम शहरों पर ध्यान नहीं दिया है । यह एक विकसित बिहार, न्याय के साथ विकास, यह दोनों एक दूसरे का, एक कड़ी का सामंजस्य देखने को मिलता है । अब कैसे मिलता है, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जब देहातों में सात निश्चय पूर्ण शराबबंदी और बाल विवाह, दहेज प्रथा पर रोक लगाने की बात कही गई, शहरों में भी, उसी तरह बिहार के सभी शहरों में चाहे मुख्यमंत्री पेयजल का सवाल हो, चाहे

नली–गली का सवाल हो, चाहे शौचालय का सवाल हो, चाहे बस स्टैंड का सवाल हो, चाहे यहां के नागरिकों, चाहे जो भी सवाल हो, नागरिकों को रहने का सवाल हो, सभी सवालों पर एन.डी.ए. की सरकार ने एक नजर से देखने का काम किया। नगर निकाय में, नगर निगम में, नगर पंचायत में यहां के लोगों के लिए पानी की जो व्यवस्था किया, हर घर में नल का पानी, हर घर में नल का पानी, नगर पंचायतों में उसी तरह की व्यवस्था, हर घर में नल जल का पानी, हर घर में नल जल का पानी । पहले लोग चापाकल के भरोसे रहते थे । पटना जैसे शहरों, मुंगेर जैसे शहरों में, भागलपुर जैसे शहरों में चापाकल के भरोसे अपना बर्तन लेकर खड़े रहते थे, लाइन लगाकर खड़े रहते थे । लेकिन एन.डी.ए. के सरकार ने जब माननीय मुख्यमंत्री और मोदी जी की सरकार जब अपना नया बजट 2018–19 का पेश किया तो उन्होंने दिखा दिया कि अब बर्तन लेकर गरीबों को शहरों में भी रहने की जरूरत नहीं है । उनके घर में पानी जाएगा । नल का पानी पिएंगे । आज देखने को मिल रहा है महोदया । महोदया, लोग देखते थे कि बाहर से आ जाते थे तो उनको शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, फिर सात निश्चय में उसी तर्ज पर शहरों में भी शौचालय बनाने का प्रबंध किया गया और उसमें राशि बिहार सरकार और भारत सरकार मिल कर बारह हजार रूपया देकर और उस राशि को जन–जन तक पहुंचाने का काम किया गया ।

सभापति महोदया, आज नगर विकास विभाग, आज पटना में जब हम बिहार से, देश से बाहरी लोग आते हैं तो देखते हैं कि पटना तो वह पटना है ही नहीं । पटना तो लगता है कि दिल्ली और बम्बई के बराबर देखने को मिल रहा है। पहले पटना में एक ओवरब्रीज नहीं था । एक दिन याद कीजिए कि एक भी ओवर ब्रीज नहीं और आप ...

सभापति(डा0 रंजू गीता): शांति । शांति ।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद: आप जहां से चल कर देखिए ओवरब्रीज, ओवरब्रीज, ओवरब्रीज, सिर्फ ओवरब्रीज । यही देखने को मिलता है सभापति महोदया । तो हम कहना चाहते हैं..

सभापति(डॉ0 रंजू गीता): अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद: जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का न्याय के साथ विकास हो रहा है, उसमें ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों में भी न्याय के साथ विकास देखने को मिल रहा है सभापति महोदया ।

सभापति महोदया, जहां तक हमारे क्षेत्र का सवाल है, क्षेत्र के सवाल पर नालंदा जिला, स्मार्ट सिटी के सवाल पर बिहार शरीफ को भी लेने का काम किया गया है । हम बिहार के बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी को और उपमुख्यमंत्री जी

को बधाई देना चाहते हैं कि आपने नालंदा जिला को भी चुनने का काम किया । इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं । जहां तक क्षेत्र का सवाल है, इस्लामपुर विधान सभा क्षेत्र के अंदर, हम पुरानी बातें याद दिलाना चाहते हैं, इस्लामपुर नगर पंचायत को नगर पर्षद बनाने की बात कही गई थी, लेकिन आज जो काम अभी अधूरा है, हम माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करेंगे कि जरा उस काम को पिछला देखकर के, जो पीछे घोषणा किया गया था कि हम नगर पंचायत को नगर पर्षद में बदलने का काम करेंगे, उसे निश्चित तौर पर हम आपसे उम्मीद करते हैं कि उसको इसी सत्र में नगर पंचायत को नगर पर्षद में बदलने का काम किया जाए ....

टर्न-15/कृष्ण/13.03.2018

सभापति (डा0रंजू गीता) : अब आप समाप्त करें । माननीय सदस्य श्री राम विशुन सिंह ।

श्री राम विशुन सिंह : सभापति महोदया, मैं वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान मांग के विरोध में और कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपके प्रति एवं अपने नेता के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं ।

श्री ललित कुमार यादव : सभापति महोदया, माननीय सदस्य ने पटना को एक तरह से गाली देने का काम किया है । इन्होंने कहा है कि पटना पहले जंगल था । महोदया, पटना का अपना एक गौरवशाली इतिहास है । बंगला देश से अफगानिस्तान तक पाटलीपुत्र का राज्य होता था । यह पाटलीपुत्र की धरती है । माननीय सदस्य पाटलीपुत्र की धरती को गाली देने का काम करेंगे ? इसको प्रोसिडिंग्स से निकाला जाय ।

सभापति (डा0 रंजू गीता) : माननीय सदस्य आप बैठ जाईये । जो बातें प्रोसिडिंग्स के लायक नहीं होगी, उन्हें प्रोसिडिंग्स से निकाल दिया जायेगा ।

श्री संजय सरावगी : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि 2005 के पहले पटना की जो नारकीय स्थिति थी, उसके बारे में कहा है ।

(व्यवधान)

श्री राम विशुन सिंह : महोदया, शहरी क्षेत्रों में जल-जमाव की गंभीर समस्या है ।

(व्यवधान)

और शहरों को छोड़ दिया जाय, पटना में वर्षा के दिनों में क्या हाल होता है यह बात किसी से छिपी नहीं है। सरकार स्मार्ट सिटी बनाने की बात करती है, किसी भी शहर में वर्षा का पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है ।

सभापति (डा0 रंजू गीता) : माननीय सदस्यगण, आपलोग बैठ जायं । शांति शांति ।

श्री राम विशुन सिंह : क्योंकि नालियों की सफाई नहीं होती है, जिसके कारण सभी शहरों में पानी का जमाव रहता है, यहां तक कि विधायक आवास में भी पानी जमा रहता है, वहां से भी पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है ।

सभापति (डा0 रंजू गीता) : माननीय सदस्यगण, प्लीज आपलोग बैठ जाईये । आपके दल के माननीय सदस्य का समय जाया हो रहा है । आपके दल के माननीय सदस्य को बोलना है । बोलने दीजिये । आप बोलिये ।

श्री राम विशुन सिंह : अभी तक नगर निगम एवं नगर निकायों में बस स्टैंड नहीं है और यदि है तो उसकी हालत बहुत ही खराब है ।

(व्यवधान)

महोदया, वर्षों से कहा जा रहा है कि मीठापुर बस स्टैंड को शिफ्ट किया जायेगा । यह भी कहा जाता है कि पटना में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बस स्टैंड बनाया जायेगा । लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड की तो बात छोड़ियें, फिलहाल मीठापुर बस स्टैंड की स्थिति बिल्कुल नारकीय है । महोदया, पटना में मेट्रो रेल योजना के संबंध में कहना है कि सराकर द्वारा सिर्फ घोषणा ही घोषणा की गयी है। डी0पी0आर0 बन रहा है, यह हो रहा है, वह हो रहा है । महोदया, 2022 तक पटना में मेट्रो रेल का कोई चीज दिखाई नहीं देगा ।

महोदया, जलवायु और वातावरण को बचाने के लिये सरकार बड़ी-बड़ी बातें करती है । जलवायु स्वच्छ की दिशा में विद्युत शवदाह गृह का होना अतिआवश्यक है जो नदियों और जलवायु को प्रदूषण से बचाती है । सभापति महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इन्होंने 08.03.2018 को इसी सदन में कहा था कि जहां 5 लाख की आबादी होगी, वहीं विद्युत शहदाह गृह का निर्माण होगा तो और बिहार के अन्य शहरों की क्या स्थिति होगी, इसका अनुमान लगाया जा सकता है ।

महोदया, किसी भी शहर के किसी भी परिवार के सदस्यों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है । उसकी गति ठप्प पड़ी हुई है । महोदया, सरकार सिर्फ टैक्स और सेस लगाना जानती है । स्वच्छ भरत मिशन के नाम पर सेस तो लगाया गया लेकिन पटना जैसा शहर स्वच्छ नहीं हुआ तो दूसरे शहर की क्या बात करना है । कचरे का अम्बार लगा हुआ है, स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर सिर्फ अवैध निकासी हो रही है, घोटाले हो रहे हैं । जहां तक स्मार्ट सिटी की बात है, कहीं स्ट्रीट लाईट तक नहीं है । चारो तरफ अंधेरा ही अंधेरा है । जहां रात और दिन-दहाड़े मर्डर और चोरी होती रहती है ।

महोदया, शहरी क्षेत्रों में अपना आवास बनाने हेतु आमजनों को नक्शा पास करवाने में जो परेशानी है, वह सारे लोग जानते हैं । सरकार शहरी आम जनों को धोखा से बचने के लिये सरकार इस दिशा में क्या कार्रवाई कर रही है ? फ्लैट को खरीदने में 12 परसेंट जी0एस0टी0 टैक्स लिया जा रहा है । इसके लिये सरकार क्या कर रही है ?

सभापति (डा0 रंजू गीता) : अब आपके पास मात्र दो मिनट का समय शेष है ।

श्री राम विशुन सिंह : भोजपुर के आरा नगर निगम में बरसात के दिनों में गली की बात छोड़ दीजिये, हमारे यहां जो अस्पताल है, उसमें पानी भर जाता है, जिसके कारण मरीजों को आने-जाने में दिक्कत हो रही है । पंचायत नगर की स्थिति क्या है, विगत 5 वर्षों से जगदीशपुर नगर पंचायत की स्थिति यह है कार्यपालक पदाधिकारी श्री अनुभूति श्रीवास्तव, श्री अनिल कुमार शर्मा, श्री हरिनिस गौतम, श्री प्रभाकर कुमार, कार्यपालक अधिकारी एवं वर्तमान कार्यपालक अधिकारी द्वारा करोड़ों रूपये का गबन किया गया है । मेरे द्वारा वित्तीय अनियमितताओं को उठाने के बाद प्रधान सचिव के द्वारा पांच सदस्सीय कमिटी द्वारा जांच कराया गया । डी0एम0 का पत्र आया लेकिन प्रधान सचिव के द्वारा उस पदाधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है । मैं प्रधान सचिव से जानना चाहता हूं कि वे भी कभी किसी जिला के डी0एम0 होंगे । जब डी0 एम0 का रिपोर्ट आता है तो प्रपत्र 'क' गठित होता है तो उस पदाधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है ? नगर विकास विभाग का पत्रांक 588 दिनांक 04.08.2016 में स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी नगर निगम में विभागीय कार्य नहीं होगा । री-टेंडरिंग से काम होगा । तो इसका अनुपालन हमारे जगदीशपुर में क्यों नहीं हो रहा है और शहरों में क्या हो रहा है, वह तो हम नहीं बता सकते हैं । जहां तक मुझे जानकरी है, कहीं भी विभागीय कार्य नहीं हो रहा है । जबकि नगर परिषद् के कार्यपालक पदाधिकारी श्री बी0एन0पाठक,मुख्य पार्षद श्री रौशन कुमार और संविदा पर नियुक्त इन्जीनियर से 200 योजनाओं में काम करवा रहे हैं जबकि संविदा पर काम करनेवाले को विभागीय काम करने का सरकार की यह चिट्ठी है कि सारे काम री-टेंडिरिंग से होंगे । लेकिन इसके बावजूद जगदीशपुर में नगर पंचायत में सारे काम विभागीय और संविदा पर जो इन्जीनियर बहाल हैं, उसके द्वारा दो सौ योजनाओं पर कार्य कराया जा रहा है ।

सभापति (डा0 रंजू गीता) : अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री राम विशुन सिंह : महोदया, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के बारें में कहना चाहता हूं । जल ही जीवन है । लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की यह स्थिति है कि चापाकल कहीं भी चालू हालत में नहीं है । जो भी चापाकल लगाये गये, वह मार्च

महीने में ही पानी देना बंद कर दिया है । इसका मतलब कि ठीकेदार को चापाकल का पाईप जितना नीचे ले जाना चाहिए था, उतना नहीं ले जाया गया, पाईप पानी के लेवल तक नहीं गया ।

(व्यवधान)

मैडम, दिहात में हमलोगों का चापाकल सुख गया । अभी की बात हम बताते हैं । यह किसका दोष है ? यह संवेदक का दोष है । किसी भी विभागीय मंत्री को माननीय विधायक शिकायत करते हैं तो कोई मंत्री ठीक से सुनते नहीं हैं। अगर पदाधिकारियों पर कार्रवाई होती तो यह स्थिति नहीं होती ।

सभापति (डा0 रंजू गीता) : अब आपका समय समाप्त हुआ । आप बैठ जाईये । माननीय सदस्य श्री विजय कुमार खेमका ।

श्री विजय कुमार खेमका : माननीय सभापति महोदया जी, नगर विकास एवं आवास विभाग के अनुदान मांग के पक्ष में मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं और माननीय सदस्य भोला बाबू ने जो कटौती का प्रस्ताव लाया है मैं उसके विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । इसके लिये मैं माननीय मुख्यमंत्री और आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी के साथ-साथ पूर्णियां की जनता का आभार व्यक्त करता हूं ।

सभापति महोदया, हम जानते हैं कि देश में शहरीकरण बहुत तेजी से हो रहा है । इसकी तुलना में बिहार अभी थोड़ा पीछे है । लेकिन एन0डी0ए0 की जो सरकार है, यह डबल इंजन की जो सरकार है, इसकी सकारात्मक सोच एवं नेक इरादे के बल पर हम शहरीकरण के राष्ट्रीय औसत पाने में कामयाब होंगे । माननीय सदस्य ललित भाई देख रहे हैं । सभापति महोदया, जब हम कहते हैं डबल इंजन की सरकार की बात तो बराबर ये डबल इंजन डबल इंजन कहते हैं । टी0वी0 पर एक प्रचार आता है मन में लड्डू फूटा, ललित भाई हम जानते हैं, उधर भी लड्डू फूट रहा है । इस डबल इंजन के लिये एन0डी0ए0 की सरकार द्वारा ये जो बजट बनाया गया है, बहुत ही सराहनीय बजट है और शहर के विकास के लिये एनडीए सरकार सतत् प्रयत्नशील है और नगर के विकास के लिये केन्द्र की सरकार नरेन्द्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उस सरकार ने अनेक महत्वकांझी योजनायें देने का काम किया हैं ।

क्रमश :

टर्न-16/सत्येन्द्र/13-3-18

श्री विजय कुमार खेमका(क्रमशः) जिसमें कि स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत, हृदय और स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, आश्रय, नामामि गंगे जैसी योजना बिहार में

भी लागू की गयी है । ये हमारे यहां राज्य सरकार की भी अनेक योजनाएं ,चाहे वह हर घर को जो हमें पक्की सड़क से जोड़ना है, हर घर को नल से जल देना है, नली गली की योजना के लिए सरकार संकल्पित है । महोदया, राज्य सरकार की हर घर, हर आमजन को पक्की नली गली की सुविधा मिले इसके तहत 2590 बार्डों में पक्की नली गली से जोड़ने का कार्य प्रारंभ है, शेष बार्डों के लिए भी कार्य योजना की गयी है । महोदया, शहर में जम जमाव की जो समस्या है, ये बड़ी भारी समस्या है, इसके प्रति हमारे नगर विकास मंत्री सतत प्रयासरत है और उसके लिए आउटफॉल ड्रेन का निर्माण भी किया जा रहा है । मैं जानता हूँ नगर विकास मंत्री यहां बैठे हैं, पूर्णियां, कस्वा और बनमनखी को भी इससे जोड़ने का काम निश्चितरूपेण करेंगे और सभापति महोदया, ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी चर्चा करनी जरूरी है जो देश के प्रधानमंत्री रहे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने देश और बिहार के विकास की भी चिन्ता की, उनकी एक योजना उनके नाम से अटल नवीकरण शहरी परिवर्त्तन मिशन योजना के अन्तर्गत 21 नगर निकायों के लिए जलापूर्त्ति योजना बिहार में भी लागू की गयी है । बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए 27 नगर निकायों के लिए नगर निकायों में पार्क की भी योजना बनायी है लेकिन हमारे विपक्षी बन्धु को शहर में विकास नजर नहीं आता है । सभापति महोदया, गांधी के सपने को साकार करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी ने देश की जनता के साथ संकल्प लिया है और इस संकल्प में हमारे बिहार के चर्चित मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी ने भी संकल्प लेकर घर घर पहुंचाने का काम किया है । स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर बिहार सरकार के द्वारा 6 लाख 10 हजार 462 शौचालय बनाया जाना है जिसमें सभापति महोदया 1 लाख 7 हजार 191 व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण पूरा हो गया है तथा 1 लाख 59 हजार 878 इकाई निर्माणाधीन है । सभापति महोदया, विपक्ष को नजर नहीं आता है सरकार का विकास, विपक्ष को सिर्फ नकारात्मक सोच के साथ देखने का इनका नजरिया बन गया है। सभापति महोदया, सिर्फ शौचालय ही नहीं, सामुदायिक शौचालय और सार्वजनिक शौचालय को भी बनाने में सरकार तत्पर है । सभापति महोदया, मैं कहना चाहूंगा कि शहर एवं प्रदेश की प्रगति एवं समृद्धि का आईना होता है और हमारा शहर चाहे पटना हो, भागलपुर हो, गया हो, दरभंगा हो, पूर्णियां हो, कटिहार हो इन सारे शहरों में जो सुविधा होनी चाहिए इस बजट के माध्यम से पहुंचायी जा रही है । सभापति महोदया, मैं मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहूंगा देश में जिस तरह की और प्रदेश में जिस तरह से शहरों का विकास हुआ है, हमारे यहां

पूर्णियां में भी स्मार्ट सिटी के लिए जिस तरह पटना और भागलपुर और अन्य शहरों की चर्चा चल रही है, कुछ बने है, पूर्णिया 1770 का पुराना जिला है, यह प्रमंडल मुख्यालय है इसी लेकर के मैं नगर मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि स्मार्ट सिटी के लिए जो नियमावली है उसको सरल बनाते हुए उसमें जितने भी हमारे उस क्षेत्र के विधायक है, जहां जहां के जो विधायक है, उसको निश्चितरूपेण उसमें जोड़ा जाय और शहर विकास की जो योजना है उसमें भी विधायक का प्रतिनिधित्व होना चाहिए । खासकर नये बसावट जो हैं शहर में उसके प्रति भी मैं मंत्री जी का विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूँ, हमारा पूर्णियां पुराना शहर है जिसमें कचरा निस्तारण के लिए भी उसमें कोई योजना बने और महोदय, फ्लाई ओवर के बगैर जाम जो है वह नहीं छूट पाता है इसलिए पूर्णियां में फ्लाई ओवर की भी व्यवस्था होनी चाहिए और मंत्री जी इसलिए भी कि पूर्णियां नेपाल से, बंगाल से, आसाम से जुड़ा हुआ है इसलिए मैं आपसे सदन में आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि वहां राज्यस्तरीय एक बस स्टैंड का निर्माण हो, इस ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ । सभापति महोदया, आपने मुझे समय दिया बोलने के लिए सरकार के बजट के पक्ष में और इस लेकर के मैं पूर्णियां की जनता की ओर से आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ और ये बजट जो सबका साथ सब का विकास का पूरे देश में नारा है उसके साथ शहर का भी विकास द्रूत गति से हो रहा है । इसी के साथ इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए जो हमारा बजट है इसका समर्थन करते है और कटौती प्रस्ताव का विरोध करते हुए और विपक्ष को यह सोचते हुए, यह कहते हुए आग्रह करते हुए कि साकारात्मक सोच के साथ हम बढ़े सबका साथ और सबके विकास में ही बिहार का भी कल्याण है । बहुत बहुत धन्यवाद, जय पूर्णियां, जय बिहार, जय हिन्द ।

सभापति(डॉ0 रंजू गीता)आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय का ख्याल रखा । माननीय सदस्या श्रीमती अमिता भूषण । आपका समय 8 मिनट है ।

श्रीमती अमिता भूषण: माननीय सभापति महोदया, मैं कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हूँ । सभापति महोदया, आजकल फ्रांस के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर है और इस दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनका भ्रमण काशी नगरी का कराया है । इस दौरान प्रधानमंत्री जी ने गर्व से घोषणा की है कि हमलोग कचरा महोत्सव मना रहे हैं परन्तु हमारे राज्य में विशेषकर राज्य के राजधानी पटना में हमलोग प्रतिदिन कचरा महोत्सव मनाते हैं क्योंकि आप जिधर भी नजर दौड़ाये, आपको कचरा का ढेर मिल जायेगा । हमें लगता है कि कचरा महोत्सव के रूप में हम माननीय प्रधानमंत्री जी का योगदान कर रहे हैं । इसमें अतिश्योक्ति नहीं होगी कि नगर

विकास के लिए बिजली, सड़क और पानी की उपलब्धता अत्यंत ही आवश्यक है। इस संदर्भ में आप सबों का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाहती हूॅ कि बिजली तो लगभग प्रतिदिन उपलब्ध है लेकिन बिजली के झटके बिजली के बिल के रूप में लगते रहते हैं और हमारे प्रदेश के कई नागरिकों को इस झटके के कारण प्राणों की आहूति भी देनी पड़ रही है । हमें यह सोचना होगा क्या बिजली की इस उपलब्धता के बदले में हमें इस तरह की कुर्बानी देनी होगी । हमारे प्रदेश में बिजली का उत्पादन कितना हो रहा है, यह एक निर्विवाद विषय है, इस पर विशेष रूप से टिप्पणी की आवश्यकता नहीं हैं । जहां तक सड़कों की स्थिति का संबंध है तो राज्य की गलियां, जिन्हें सड़क के रूप में संबोधित किया जाता है, वाहनों के दवाब से कड़ाह रही है । प्रत्येक दिन सरकार को माननीय उच्च न्यायालय में यह जवाब देना पड़ता है कि जाम से निजात पाने की सरकार की क्या योजना है और इस संदर्भ में सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाती है और आम नागरिक केवल ठंढ़ी आह भर कर रह जाते हैं । कुछ दिन पहले मैडम आप भी यही सच बोल रही थी । यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि सड़कों पर वाहन के जाम से उत्पन्न समस्या का कई मरीजों को भी झेलना पड़ता है, कई मरीज तो एम्बुलेंस में ही अपने प्राण त्याग देते हैं, छात्र छात्राएं इंटरभ्यू देने से बंचित रह जाते हैं, ये और व्यापारी वर्ग के लोग भी अपने काम समय पर नहीं निष्पादित कर पाते हैं जिससे उनके व्यापार में भी घाटा उठाना पड़ता है । चूंकि सरकार को सड़क पर आवागमन के दौरान विशेष सुविधा मिलती है इसलिए इन समस्याओं से उन्हें नहीं जुझना पड़ता है । महोदया, आपके माध्यम माननीय मंत्री जी से हमारा आग्रह है कि यातायात की व्यवस्था को ठीक करने पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है । साथ ही मैं आग्रह करना चाहती हूॅ कि सार्वजनिक जगह पर शुद्ध पेयजल और शौचालय की विशेष व्यवस्था पूरे प्रदेश में की जाय । अतिक्रमण की मुक्ति के नाम पर जिस तरह से कमजोर वर्ग के लोगों का शोषण हो रहा है उनका भी स्थायी निदान किया जाय । हमारा बिहार प्रदेश भागौलिक दृष्टि से विशेष क्षेत्र है, जहां पानी की प्रचुरता है लेकिन जहां पीने के पानी की गुणवत्ता का सवाल है , मैं इतना ही कहना चाहती हूॅ, मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूॅ, वह बेगुसराय में पानी में आर्सेनिक की मात्रा बहुत ही है । (क्रमशः)

टर्न-17/मधुप/13.03.2018

...क्रमशः...

श्रीमती अमिता भूषण : जिसके कारण वहाँ के लोगों को बहुत परेशानी होती है, खासकर किडनी की बीमारी से लगातार कई सालों का अगर सर्वे किया जाय तो किडनी के बीमारी के मरीजों की संख्या वहाँ लगातार बढ़ती जा रही है । सरकार ने पूर्व में घोषणा भी की थी किडनी के मरीजों के लिये विशेष रूप से वहाँ के सदर अस्पताल में डायलिसिस की व्यवस्था की जायेगी लेकिन अभी तक उस योजना की क्या रूपरेखा है, उसका पता नहीं चल पा रहा है ।

महोदया, हमें यह सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा- कैसा नगर और कैसा विकास? आज बात चलती है स्मार्ट सिटी की, मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि किसी सिटी को स्मार्ट बनाने की बजाय अगर हम उस शहर के किसी वार्ड, मुहल्ले को या जिले के किसी प्रखंड के गाँव को अगर स्मार्ट बना लें तो यह अपने-आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी ।

महोदया, मैं अंत में यह कहना चाहती हूँ - I would submit that there should not be smartness of words but smartness in action. सदन के सभी लोगों के प्रति बहुत-बहुत आभार एवं धन्यवाद ।

सभापति (डॉ0 रंजु गीता) : आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद । समय-सीमा के अन्दर अपने वक्तव्य को समाप्त करने के लिये आपको धन्यवाद ।

माननीय सदस्य श्री मो0 नवाज आलम । आपका समय 8 मिनट है ।

श्री मो0 नवाज आलम : सभापति महोदया, नगर विकास एवं आवास विभाग के 2018-19 के वार्षिक बजट के अनुदान माँग के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में और बजट के विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ ।

महोदया, हमने जो बजट का आकलन किया है, उस आकलन के मुताबिक मुझे लगता है कि जब महागठबंधन की सरकार थी, जन-जन के नेता आदरणीय लालू यादव के साथ मिलकर जो सरकार बनी थी उस सरकार में नगर के विकास मंत्री ने नगर के बजट को बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ाने के लिये ताकि नगर की मूलभूत समस्याएँ जो हैं, उन मूलभूत समस्याओं में सात निश्चय को लाने का काम किया गया था जिसमें जलापूर्त्ति, हर घर को नल पहुँचाना, हर घर को शौचालय देना, हर घर की जो मूलभूत समस्याएँ होती हैं, जो मलीन बस्तियों में लोग जूझते थे और बड़े-बड़े आलीशन महलों में रहने वाले लोग, कहीं न कहीं उन महलों में रहने वाले लोग, गरीबों के बीच में पानी जो सप्लाई का होता, वह देखने को मयस्सर नहीं होता था लेकिन आदरणीय जन-जन के नेता लालू यादव की एक

सोच थी, एक संकल्प था और वह संकल्प था कि कहीं उन तमाम जगहों पर ये तमाम सुविधा को पहुँचाया जायेगा । लेकिन महागठबंधन की सरकार के आने के बाद कहीं न कहीं महागठबंधन के जनादेश को अपमानित करने का काम किया, वैसे अपमान करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो पलटनिया मारने का काम किया है, हमारे नेता ने उनपर विश्वास किया था और उस विश्वास के तहत उनको छोटे भाई के रूप में चन्दन लगाने का काम किया था लेकिन ठीक किसी ने कहा है कि

खुदगर्जियों की बस्ती में मदद भी एक गुनाह है,
जिसे तैरना सिखाओ वही डुबाने को तैयार है ।

महोदया, कहीं न कहीं छल किया गया हमारे नेता के साथ, कहीं न कहीं उनको धोखा देने का काम किया गया । जो जमीन पर हमलोगों ने लम्बा बजट देने का प्रावधान किया था, हमारे वित्त विभाग के मंत्री ने उसमें काफी हद तक जाने का काम किया था लेकिन आज के माननीय वित्त मंत्री ने कहीं नगर विकास को छोटा करने का काम किया है, उसके कारण हैं महोदया, कि जो मंत्री थे, तमाम लोगों की जो सोच थी, उस विभाग का जो पैसा था, 50 परसेंट से उपर खर्च नहीं हो पाया । खर्च नहीं होने के कारण आज हर घर को पानी पहुँचाने की योजना जो है, बोरिंग लगाने की योजना है, शौचालय योजना, आज कहीं घोटाले का अंबार बना हुआ है । नगर विकास विभाग को हम यों कहीं कि नगर विकास नगर विनाश के नाम से जाना जा रहा है । आज के वक्त में चाहे इंजीनियर की बहाली का मामला हो, संवेदक का मामला हो, आपका कोई टाइम प्लानिंग नहीं है । प्लान के मामले में कोई मास्टर प्लान नहीं है । शहर तो दूर की बात, हम आरा के इलाके से आते हैं, आप पटना को ही उठा लें, नितिन जी बोल रहे थे, बैठे हुये थे श्याम रजक भाई, उनके मुहल्ले की जो मलीन बस्तियाँ हैं, जहाँ गरीब लोग बसते हैं फुलवारी में, वहाँ की दुर्दशा देखने के लायक है । कौन-सा मास्टर प्लान आपका है, कौन-सा नमूना है ? आप कहते हैं स्मार्ट सिटी की बात, स्मार्ट सिटी की बात वह करता है जहाँ कोई उसकी सोच होती । कोई सोच आपके सामने नहीं है, महोदया। आप शहरी बस्ती के कई वार्डों के बस्तियों को, परिवारों को पक्की नाली से जोड़ने का 2590 वार्ड का कार्य प्रारंभ करने की बात कही है । मैं जहाँ से आता हूँ, 45 वार्ड है, माननीय प्रभारी मंत्री जी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके सामने भी तमाम मामले, मुख्यमंत्री जी की समीक्षा यात्रा हुई थी, बैठक हुई थी 30.01.2017 को, उसके बाद लगातार बैठक हुई और उस बैठक में हमलोगों ने मजबूती से अपनी तमाम समस्याओं को रखने का काम किया । महोदया, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम के मामले

में, जल जमाव के मामले में भी, आउट-फॉल ड्रेनेज के मामले में आप कहते हैं कि उसको पानी पहुँचाने का काम करते हैं, हम सदन के माध्यम से, माननीय महोदया, आपके माध्यम से जानना चाहते हैं, हमलोगों ने 30.01.2017 की समीक्षा बैठक में अपने आउट-फॉल नाला ड्रेनेज की समस्याओं को उठाने का काम किया था, वह ड्रेनेज का मामला था बिहार होटल से मिल्की मुहल्ला होते हुये अमरपुर का नाला, गांगी तट निकालने का मामला, बड़ी मठिया से सदर अस्पताल मोड़ से सपना सिनेमा तक, आज तक महोदया, चार-चार डी0पी0आर0 बनकर आया लेकिन उसपर कोई अमली-जामा नहीं पहनाया गया। विभाग से कभी कहीं डूडा में भेजा जाता, अभी आपने सुना होगा कि वहाँ के नगर आयुक्त शराब पीते हुये कहीं न कहीं पकड़े गये । आज बताइये, जिस जगह का नगर आयुक्त शराब पीते हुये पकड़ा जाय, वहाँ के डी0एम0 ने उसपर बजाप्ता कमिटी बनाने का काम किया था।

महोदया, जो एक विधायक ने दो वर्षों से लगातार उन सवालों को, ड्रेनेज के सवालों को हमेशा आपके सदन में रखने का काम किया लेकिन वह मामला डी0पी0आर0 और कागजी कार्रवाई के बिनाह पर घूमता रहा । आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है । महोदया, आपको बताना चाहते हैं कि मिलकिया नाईट, बगल में एक महल्ला है, जहाँ पानी से लोग डूब रहे हैं । आप स्वच्छ भारत की बात कहते हैं, कौन-सा स्वच्छ भारत ? स्वच्छ भारत के नाम पर यह नारकीय स्थिति बनी हुई है । इसी तरह से रमगढ़िया से दूधकटोरा, वलीगंज धरहरा चौकी से होते हुये धरहरा पुल तक नाले के निर्माण का काम आज तक पूर्ण नहीं हो सका । इसी तरह से पकड़ी मोड़, जो सर्किट हाउस है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी गये थे, उप मुख्यमंत्री जी गये थे, पकड़ी मुहल्ला जो शहर के बीचोबीच है, आज नाला से डूब रहा है । उन समस्याओं को हमलोगों ने दनियांवा में इस मामले को मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में मंच से उठाने का काम किया था लेकिन उसपर कोई अमली-जामा नहीं पहनाया गया । जब इस सूबे का मुख्यमंत्री हाथ पसार ले, जिस सूबे का मुख्यमंत्री प्रधान सचिव के पास, हमें लगता है कि यहाँ का लाल-फीताशाही पूरी तरह हावी है । नगर विकास विभाग पर लाल-फीताशाही का कब्जा है और उसी का परिणाम है कि विभाग के मंत्री से लेकर तमाम लोग उनके इशारे पर बदले जाते हैं । इसमें भी हमें संदेह है ।

....क्रमशः ....

टर्न–18/आजाद/13.03.2018

..... क्रमशः .....

श्री मो0 नवाज आलम : जहां का चीफ सेक्रेटरी तमाम मामले में इनवोल्व हो महोदया, वो जो है चारा के घोटाले में लिप्त हो, वो आज कैसे मुख्य सचिव से लेकर तमाम चीजों में निगरानी रख सकता है, सोचने का विषय है महोदया । यह बात मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूँ, मैंने प्रमाण के साथ सदन में उठाने का काम किया है, उसको रखने का काम किया हूँ । हम आपको बताना चाहते हैं लेकिन हम विपक्ष में हैं, विपक्ष की भी भूमिका होती है । मेरी कोशिश है कि हम विपक्ष में होते हुए भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलन्द करते रहे । ये जो भ्रष्टाचार का सुनामी चला हुआ है, इनके भ्रष्टाचार का सुनामी है शौचालय घोटाला, सृजन घोटाला इन तमाम घोटालों का जो अम्बार बना हुआ है । 10–12 घोटाले हैं, ऐसे घोटाले में भी हमलोग चाहते हैं कि आप विकास के रास्ते पर अग्रसर होईए । इसलिए मेरी कोशिश है .....

सभापति(डॉ0 रंजू गीता) : अब आप समाप्त करें ।

श्री मो0 नवाज आलम : महोदया,

''मेरी कोशिश है, सहारों में मेरे साथ चलो,
मैंने एक शमां जलायी है, हवा के खिलाफ चलो ।''

महोदया, हमेशा हमलोग चाहते हैं, हमारी कोशिश है कि विकास के रास्ते पर कदम से कदम मिलाकर चलें, चूँकि विपक्ष की भी एक अलग भूमिका होती है । लेकिन आपकी राह अलग–अलग है । इसलिए महोदया, आपके सामने बहुत सारे सवाल हैं, जैसे आप होल्डिंग टैक्स लेते हैं, होल्डिंग टैक्स के नाम पर आप पूरे शहर के लोगों को दोहन करने का काम करते, आप के पास इंजीनियर नहीं हैं । आरा नगर निगम में हमारे यहां इंजीनियर की कमी है .....

सभापति(डॉ0 रंजू गीता) : आपके पास मात्र एक मिनट है ।

श्री मो0 नवाज आलम : आप होल्डिंग टैक्स के नाम पर शहर के लोगों का दोहन करते हैं, ड्रेनेज नहीं है, अन्डरग्राऊन्ड ड्रेनेज का प्लान आपका पूरी तरह विफल है । आपके यहां कर्मचारी का अभाव है । हमारे माननीय जन–जन के नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी कहीं न कहीं जो बहाली, नियुक्ति की, परमानेन्ट की, आप भी उदाहरण देते हैं चाहे वह शिक्षा के मामले में हो, चाहे इंजीनियर के मामले में हो । आपने नियुक्ति नहीं किया, पूरा विभाग खाली है, नगर–निगम खाली है, कंट्रेक्ट पर चल रहा है । कहीं न कहीं हमको लगता है कि इसमें मिलीभगत है और इसी का कारण है कि एन0जी0ओ0 के माध्यम से तमाम जो कार्य हैं, वे कराते हैं, चाहे

सफाई का कार्य हो, तमाम जगह कर्मचारी से काम कराते हैं । आप तमाम जगह घोटाले में ही लिप्त हैं । इसलिए हमारा मानना है कि यह सरकार पूरी तरह घोटाले में लिप्त है और इनका कोई मिशन नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है । इसलिए हम माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहते हैं कि .....

सभापति(डॉ0 रंजू गीता) : अब आप समाप्त करें ।

श्री मो0 नवाज आलम : महोदया, मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में, प्रधान सचिव के सामने और तमाम डी0एम0 के सामने आरा के आऊट फॉल ड्रेनेज का मामला को उठाते रहे हैं। जब आप एक आऊट फॉल ड्रेनेज को नहीं बना पायेंगे तो कैसे हम विकास के मामले में आगे बढ़ सकेंगे । इसलिए तमाम जगहों पर एम0एल0ए0 को रिप्रजेन्ट करने के लिए, प्रतिनिधित्व करने के लिए आपका संरक्षण चाहिए । तमाम जगहों पर जो अनियमिततायें हैं, उसकी उच्चस्तरीय जाँच की जाय । इसलिए महोदया, इसी आरा नगर निगम में के0पी0 सिंह जैसा इंजीनियर करोड़ो रू0 के मामले में लिप्त था और वह लिप्त ही नहीं था, बल्कि उसके यहां सोना का ईटा पकड़ा गया है । इसलिए मैं आपका संरक्षण लेते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ । जयहिन्द ।

सभापति(डॉ0 रंजू गीता) : माननीय सदस्य डॉ0 मो0 जावेद । आपका समय 4 मिनट है ।

डॉ0 मो0 जावेद : मैडम, हमारे माननीय सदस्य ने कम बोला है, इसलिए एक मिनट और ।

सभापति(डॉ0 रंजू गीता) : वह माईनर था, समय ज्यादा कम नहीं था ।

डॉ0 मो0 जावेद : माननीय सभापति महोदया, बहुत,बहुत शुक्रिया । मैं नगर विकास एवं आवास विभाग के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूँ । मैडम, आज कल नये-नये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रहे हैं और खासकर के इंडिया में और देखा-देखी हम बिहार में भी शुरू कर दिये हैं स्मार्ट सिटी । अब लोग पूछते हैं स्मार्ट सिटी क्या है, जहां तक मेरी समक्ष है स्मार्ट सिटी वह सिटी है, जहां जो भी लोग उस सिटी में रहते हैं, उस सिटी में सुविधायें अच्छी रहती है । वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होता है, हाईजीन मेनटेन होता है, सफाई मेनटेन होती है । पार्क होते हैं, प्ले ग्राऊन्ड होते हैं, पार्किंग स्पेश होते हैं, मार्केट लगाने के लिए अलग जगह होती है लेकिन हमारे पटना या पटना के अलावे किसी भी सिटी में या टाऊन में इस तरह का कहीं नहीं देखा जा रहा है । जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात है, हमारे माननीय सदस्य श्री नितीन जी ने कहा कि सी0एम0 और डिप्टी सी0एम0 सपना देख रहे हैं कि यहां पर मेट्रो स्टेशन लाया जायेगा, मेट्रो स्टेशन चलाया जायेगा । पिछले 5-7 सालों से हमलोग सुन रहे हैं लेकिन यह सपना ही रह गया मैडम । एक तरफ बुलेट ट्रेन आ रहा है जापान से और दूसरा मेट्रो स्टेशन आ रहा है

दिल्ली से और वह आता ही रह जायेगा । महोदया, आज जो स्थिति है बिहार में स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं या नहीं, इसपर बहुत बड़ा सवाल है । अगर आप पिछले साल का बजटरी एलोकेशन देखेंगे तो 2734 करोड़ रू0 था और उसको बढ़ायेंगे क्या, उसको घटा दिया गया 2635 करोड़ । अब बताईए स्मार्ट सिटी कहां बनेगा ? जो स्थिति है, उसकी देखभाल ठीक से नहीं हो पाती है ।

मैडम, मैं किशनगंज के बारे में बताना चाहता हूँ, जहां से मैं विधायक हूँ। कई सालों से मैं परेशान हूँ कि वहां पर सिवरेज सिस्टम किया जाय । एक हमारे माननीय मिनिस्टर थे, आज नहीं है हमारे साथ लेकिन उन्होंने वादा किया था लेकिन उसपर कोई पहल नहीं हुई । रमजान नदी बीच से बह रही है पिछले 7 साल से, हर वर्ष में यह मुद्दा उठाता हूँ इनक्रोचमेंट के वजह से वह नदी नाला बन गया है । नाला ही नहीं 8 महीना उससे बदबू आती है, उससे बीमारियां फैलती है और उसके वजह से पिछले साल फ्लड आये थे, उससे लाखों लोगों का नुकसान हुआ । इससे सड़कें तबाह हो गई । यहां पर दो-चार गांवों का नाम लेना चाहता हूँ । खगड़ा से मझिहा रोड, महिस भतना रोड, सिमलबाड़ी खिरदा रोड यह सब रोड में बीच-बीच में कटाव है । नाव से आज भी लोग उसको पार कर रहे हैं। मेरा आपसे गुजारिश है कि इसको जल्द से जल्द बनवाने की कोशिश करें और इनक्रोचमेंट को इमेडियेट हटाने के तरफ इसका पहल करें । चूँकि इस इनक्रोचमेंट के वजह से जैसा मैंने बताया कि प्रदूषण हो रहा है, इनक्रोचमेंट जो किया गया है, उसमें कई ऐसे लोग लैंडलेस हैं, उनको घर नहीं है, इसलिए उनको अन्य जगह सेटल्ड करके शीघ्र अतिशीघ्र हटाना चाहिए ।

सभापति(डॉ0 रंजू गीता) : अब आप समाप्त करें ।

डॉ0 मो0 जावेद : मैडम, एक मिनट । डूडा स्कीम होता था, उसको हम चालू कराने का आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं । आखिर में सिर्फ एक प्वायंट, हमारे बिहार में सबसे कम तादाद में शहरों में बसते हैं और इसकी रफ्तार बढ़ती जा रही है । हमने पिछले साल के पिछले साल उठाया था, यह अच्छा ऑपरचुनिटी है कि बाकी शहरों से हमलोग सबक लेते हुए सैटेलाईट टाऊन्स का इन्तजाम करें, जमीनों को लेकर वहां पर पहले से ही सिवरेज सिस्टम रखें, रोड रखें, पार्क, स्कूल और अस्पताल का अलग-अलग आईडेन्टीफाई करके एरिया रखें और जब उस तरह का शहर फैलेगा तभी स्मार्ट सिटी होगा वरना पटना की तरह या अन्य टाऊनों की तरह आज जो गांवों में फैल रहा है । वहां पर आज सड़क नहीं है, कहीं खेलने के लिए मैदान नहीं है । स्कूल भी है तो चार मंजिला, पाँच मजिला, यहां तक कि एक कैरमबोर्ड रखने की जगह नहीं है । मेरा सुझाव होगा

मैडम कि इन चीजों पर भी माननीय मंत्री जी ध्यान दें । आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत,बहुत शुक्रिया ।

सभापति(डॉ0 रंजू गीता) : माननीय सदस्य श्री कुमार सर्वजीत । आपका समय 7 मिनट है ।

श्री कुमार सर्वजीत : सभापति महोदया, नगर विकास एवं आवास विभाग के अनुदान मांग के विरोध में और कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदया, हम माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करेंगे कि जो आपने बजट लाया है सदन में, पूरे बिहार में और पूरे बिहार के जितने जिले हैं, कितने मे0टन शहर से कचड़ा निकलता है और आपने इस बजट में कितना प्रावधान रखा है, उस कचड़े को डिसपोजल करने के लिए । अभी हाल में हमारे मुख्यमंत्री जी, नन्दकिशोर जी, अभी नहीं बैठे हैं, नहीं तो उनसे भी पूछता । बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी जापान गये और जापान जैसे शहर में जो समुद्र के बीच में बसा है और हमलोगों ने देखा है, एकाध सौ बार उस शहर को देखा है पूरे जापान देश को । वहां के जो कचड़े निकलते हैं, उस कचड़ा से पूरे जापान ऐसा देश अपनी सड़क को बनाता है । आपके पास जितने मे0टन कचड़े निकलते हैं, क्या आपके पास कोई ऐसा प्रावधान है कि उस कचड़े से आप बिहार के विकास में उसका कोई उपयोग करेंगे कि नहीं करेंगे, यह हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं ? ..... क्रमशः .....

टर्न-19/अंजनी/दि0-13.03.18/

श्री कुमार सर्वजीत :...क्रमशः... महोदया, पूरे बिहार का जो कचरा निकलता है, अगर आप शहर में नगर पंचायत के माध्यम से, घर में जो हमारी मां-बहनें खाना बनाती हैं, उसका सब्जी अगर ले लेते हैं और जानवरों को, गोशाला में अगर उसकी आपूर्त्ति करते हैं तो उसका जो गोबर है, उससे हमारे गांव के जो किसान हैं, उसका बड़े पैमाने पर उपयोग कर सकते हैं । महोदया, इस तरह कचरा का उपयोग हो सकता है । महोदया, हमने पूरे बिहार के नगर निगम और नगर पर्षद को देखा है....

(व्यवधान)

सभापति(डॉ0 रंजू गीता) : माननीय सदस्य टोका-टोकी बंद कीजिए ।

श्री कुमार सर्वजीत : हमने देखा है कि पूरे बिहार में नगर परिषद और नगर पंचायत में करोड़ों-अरबों रूपयों का (व्यवधान) सुन लीजिए, अगर काम नहीं करना है, आप मंत्री हैं, कोई अच्छी बात सदन में पूछता है तो बोलना चाहिए ।

सभापति(डॉ0 रंजू गीता) : माननीय सदस्य टोका-टोकी न करें । माननीय सदस्य, आप बोलिए ।

श्री कुमार सर्वजीत : तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि करोड़ों-अरबों रूपया का नगर परिषद और नगर पंचायत मशीन खरीदती है, वह जनता का पैसा है तो आप सदन को बतायें कि पूरे बिहार के नगर पंचायत और नगर निगम में उस मशीन को चलाने वाले आपके पास कितने स्टाफ हैं ? महोदय, इसका अगर मापदंड करेंगे और जानकारी लेंगे तो पूरे बिहार में मुझे लगता है कि नगर निगम और नगर पंचायत के पास एक सौ से ज्यादे ड्राइवर नहीं है गाड़ी चलाने के लिए और खर्च कितना है ?

सभापति(डॉ0 रंजू गीता) : इन सारी बातों का जवाब सरकार के उत्तर के समय दिया जायेगा।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदया, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि बिहार के मुखिया जापान गये और हम जिस शहर के वासी हैं, जिस शहर से हमलोग जीतकर आते हैं, यह बोध गया विश्वविख्यात पर्यटक स्थल है और इस पर्यटक स्थल में जब माननीय मुख्यमंत्री जी जब जापान से घूमकर आये तो हमलोग के पास कितने मेल वहां से आये, जो आस्था रखते हैं भगवान बुद्ध की धरती से । मुझे बहुत दुख हुआ कि नंद किशोर जी ने कहा कि मैं सीता मईया और भगवान राम का बिहार से उस सड़क को जोड़ रहा हूँ और आप वैसे जगह से घूमकर आये, आप वैसे देश का खाना खाकर आये, जिनकी आस्था बोध गया से है और आपने यह नहीं कहा कि मैं जापान घूमकर आया हूँ । बोध गया के जो भगवान बुद्ध को माननेवाले लोग हैं, उसके लिए मैं क्या करना चाहता हूँ ? वहां फुटपाथी हैं, मेल आया हमलोगों के पास और वहां के लोगों ने पूछा कि आपके बिहार के मुखिया बोध गया आये तो क्या नगर पंचायत के पास कोई ऐसा विजन नहीं है कि फुटपाथ पर सामान बेचनेवाले पुलिस के डंडे रोज खाते । कई देश के प्रधानमंत्री बोध गया आते और फुटपाथियों को लाठी-डंडा भांजकर उसकी झोपड़ियों को उजाड़ देते हैं तो क्या बिहार में नगर निगम, नगर पंचायत या आपके विभाग के पास क्या कोई ऐसा विजन नहीं कि हम फुटपाथियों को रोजगार मुहैया करा सकें । हमने कई बार आग्रह किया कि वे भी ऐसे पर्यटक स्थल, आप जापान गये और आपने क्या देखा, अगर मुझे मालूम होता कि बिहार के मुखिया जापान के दौरे पर जा रहे हैं तो निश्चित तौर से मैं पीछे से टिकट कटाकर जाता और मैं वहां बताता कि यहां के नगर पंचायत और नगर निगम कैसे देश का विकास करती है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि आप जिस तरह से बंगाल के मंदिरों में अपनी आस्था रखते हैं, उसी तरह से बिहार...(व्यवधान).

सभापति(डॉ0 रंजू गीता) : माननीय सदस्य, बैठे-बैठे टोका-टोकी न करें ।

श्री कुमार सर्वजीत : उसी तरह से बिहार विश्वविख्यात भगवान बुद्ध की धरती है, आप वहां पर आयें, अपने सर को झुकाये, मंदिर है । बोध गया का विकास नगर पंचायत के माध्यम से कैसे होगा, उसको करें ।

सभापति(डॉ0 रंजू गीता) : माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें ।

श्री कुमार सर्वजीत : फुटपाथी आपकी सहायता से बिहार का नाम कैसे रौशन करेंगे नगर पंचायत की सहायता से और फुटपाथी लोग अपना जीवन-यापन कैसे करेंगे, उसको आप देखें । माननीय मुख्यमंत्री जब जापान से वापस आये तो वहां के अखबार में एक आर्टिकल आया, आर्टिकल यह था माननीय मंत्री महोदय कि बिहार का कचरा, पटना शहर का कचरा और पूरे बिहार का कचरा जहां पर फेंका जाता है, वहां पर गरीब और दलित के बेटे और गो-हत्या के नाम पर सड़क पर आम आदमी को मारने वाली पार्टी की सरकार उसके जानवर वह कचरा खाते और गरीब और दलित का बेटा वह कचरा खाकर अपने पेट को भरता, क्या आपके पास ऐसा कोई विजन नहीं है ?

सभापति(डॉ0 रंजू गीता): अब आप समाप्त करें, माननीय सदस्य श्री ललन पासवान, आपका समय चार मिनट है ।

श्री ललन पासवान : जैसी आपकी मर्जी । सभापति महोदया,

(व्यवधान)

सभापति(डॉ0 रंजू गीता) : माननीय सदस्य को बोलने दीजिए, इनके पास चार ही मिनट है । आप बोलिए ।

श्री ललन पासवान : सभापति महोदया, मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ, इधर के लोग उधर भी थे और उधर के लोग इधर थे । महोदय, हम उस समय भी सदन के माध्यम से मैं अपनी समस्या को रखते आया हूँ । कैमूर और रोहतास के लोगों को, वनवासी और आदिवासियों को जो सदियों से आजादी के बाद तक जिसको पीने का पानी तक नहीं मिला, चुआरी का पानी आज तक पीता है । पहली बार मैं विनोद नारायण झा जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि रेहन में चार पानी टंकी बना है लेकिन सत्तर गांव, मेरे यहां नोहट्टा, रोहतास का दो पंचायत और कैमूर का 109 गांव, आज भी चुआरियों का पानी पीता है, गंदी चुआरियों का, 40 साल, 50 साल कांग्रेस और 15 साल इधर भी और आज भी वही हालत है महोदया, आज पहली बार आप जब इधर थे, तब भी मैं बोल रहा था, पहली बार, मैं सरकार से बड़ी अदब के साथ आग्रह करना चाहता हूँ कि पी0एच0ई0डी0 मिनिस्टर, कमिश्नर सब

यहां बैठे हुए हैं, मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि विशेष पैकेज देकर कैमूर को जहां आदिवासी, वनवासी, खिलवाड़ और ग्वाला भी है, उस समय भी हमने बताया था कि 56 हजार की आबादी कैमूर की और करीब-करीब 25 से 30 हजार मेरी आबादी, सासाराम अशोक जी का भी करीब दस गांव है तो करीब-करीब 225 गांव(व्यवधान)

सभापति(डॉ0 रंजू गीता) : माननीय सदस्य, बैठे-बैठे टोका-टोकी न करें ।

श्री ललन पासवान : इनकी आदत है, वे करेंगे भी नहीं और सुनेंगे भी नहीं । 225 गांव पीने के पानी के लिए विशेष पैकेज चलाने की मांग करता हूँ और दूसरा यह कि मेरे यहां पांच-सात बड़े पर्यटक स्थल हैं- गुप्ताधाम, मां मुंडेश्वरी, शेरगढ़ किला, रोहतासगढ़ किला, पचौरा घाट, चनारी घाट, गीता घाट आश्रम, झरनवां में एक बाबा का आश्रम है, वे वहां तपस्या कर रहे हैं, उनके यहां बड़ी मेहनत के बाद एक चापाकल लगा है लेकिन उससे काम नहीं चलेगा, बखौरी मांई, कैमूर डैम और तुतला भवानी, माननीय अशोक जी का क्षेत्र है, महादेव कोट, झरना दर्जनों पर्यटक स्थल हैं, जहां पीने का पानी नहीं है । हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि वहां सोलर डबल पंप जिससे पानी वहां पर्यटकों को मिले । गुप्ता धाम लाखों पर्यटक जाते हैं लेकिन पीने का पानी नहीं है । पनारी घाट से चढ़कर पचौड़ा घाट से चढ़ते हैं चारों तरफ से तारा चंडी घाट से.....

(क्रमशः)

टर्न-20/शंभु/13.03.18

श्री ललन पासवान : क्रमशः....महोदया, दो सवाल मेरा है ।

सभापति(डा0 रंजु गीता) : आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री ललन पासवान : बस-बस दो सवाल है महोदया । नगर विकास मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि चेनारी में बस स्टैंड नहीं है, पूरा नगर पंचायत आप कर लीजिए हम आपसे आग्रह करेंगे, उसकी जो दुर्दशा है, ठेहुना भर नहीं जांघ भर पानी लग जाता है, नाला नहीं है । आप वहां बस स्टैंड बना दीजिए । वहां सितौरा में एक जगह है, काफी जगह है, तीन-चार एकड़ जमीन है । दूसरा आग्रह है कैमूर और रोहतास में महोदया 40 करोड़ का रोहतास में और 20 करोड़ का कैमूर में फ्लोराइड मुक्त पानी की निविदा निकाली गयी थी- सूरत की एक कंपनी ली है, सरकार ने अगले बार जवाब में कहा है सेक्रेटरी से जॉच कराने का और उसमें अभियंता प्रमुख.....

सभापति(डा0 रंजु गीता) : अब आप समाप्त करें ।

श्री ललन पासवान : बस एक मिनट । महोदय, उसमें पूरी तरह पी0एच0इ0डी0 के कई इंजीनियर इन्वोल्व हैं और बिना कागज के निविदा दे दी गयी है उसकी जॉच कराने के लिए सरकार से हम मांग करते हैं । उस समय भी हम मांग किये थे । पी0एच0इ0डी0 मिनिस्टर हैं और हम तो कहेंगे कि प्रत्यय अमृत जी को मिल जाय या ईमानदार अफसर को मिले जिससे जॉच हो कि दूध का दूध और पानी का पानी फैसला हो । उसमें पूरी तरह से इंजीनियर इन्वोल्व हैं घोटाले का मामला है इसलिए मैं कहूँगा कि सरकार उसकी जॉच करावे । तीसरा एक सवाल और है महोदया आपदा से एक सवाल है कि एक फिल्मी कलाकार शूटिंग के समय मर गया था प्रमोद कुमार कुशवाहा उसको आज तक मुआवजा नहीं मिला ।

सभापति(डा0 रंजु गीता) : माननीय सदस्य सत्यदेव राम जी, आपका समय दो मिनट है ।

श्री सत्यदेव राम : सभापति महोदया, नगर विकास एवं आवास विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग और विधि विभाग द्वारा मांग के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर मिला है । हम जितनी महत्वपूर्ण बात करेंगे- मंत्री जी अपनी ही बात कहेंगे और अपने ही हाथ, अपने ही पीठ थपथपाऐंगे । महोदया, इस सरकार की जितनी उपलब्धियां हैं उतना ही, उससे अधिक नाकामियां है । इसके उदाहरण हैं मेरे पास कि अभी स्मार्ट सिटी बनाने की बात हो रही है तो साथ ही साथ गरीबों को उजाड़ने की भी बात हो रही है । गरीबों को उजाड़कर के वहां से हटाने की बात हो रही है । महोदया, इससे आगे मैं आपको ले चलना चाहता हूँ कि चार शहरों में स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला हुआ है तो गरीबों को उजाड़ने का भी फैसला हो गया है । इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि जो गरीब जिस शहर में और जहां बस गये हैं, वर्षों से उनका पुस्तैनी अधिकार दो, उनको जमीन का मालिक बनाओ- वास, आवास हर नागरिक का मौलिक अधिकार है । उनको यह अधिकार सरकार को देना होगा । यह मैं सदन से मांग करता हूँ कि यह अधिकार उन भूमिहीनों को पहले देना चाहिए । आप प्रधानमंत्री आवास योजना चला रहे हैं, संख्या जरूर आपने दिया है, लेकिन वह आंकड़ा सही नहीं है । इसलिए कि शहरों में जो गरीबों की जमीन है उस जमीन का वह मालिक नहीं है और मालिक नहीं है इसलिए आप प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति नहीं देते हैं । इसलिए उस जमीन की स्वीकृति दिया जाय । गरीबों को भी शहर में रहने दिया जाय । माननीय मुख्यमंत्री जी जापान गये थे और उन्होंने बिहार के विकास के मॉडल को भी रखा है, क्या रखा है बतायेंगे, उन्होंने मॉडल रखा है कि कृषि के क्षेत्र में बड़ी संभावनाएं हैं आप आइये पूँजी लगाइये, हम आपको सस्ता मजदूर दे देंगे ।

सभापति(डा0 रंजु गीता) : आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री सत्यदेव राम : महोदया, आज थोड़ा सा हमको बोलने दीजिए- कि सस्ता मजदूर देंगे, आपने उनको भूमिहीन बनाकर रख दिया है । आपने लाचार बनाकर रख दिया है और सस्ता मजदूर की चर्चा विदेशों में कर रहे हैं आपको शर्म आनी चाहिए कि हमारे राज्य के अंदर इतने मजदूर बेकार हैं, बेरोजगार हैं, बुद्धिहीन हैं, गरीब हैं कोई रोजगार नहीं है इसलिए आपको वह सस्ता मजदूर देने की बात है ।

सभापति(डा0 रंजु गीता) : अब आप समाप्त करें ।

श्री सत्यदेव राम : महोदया, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने नल जल के नाम पर अचानक चापाकल को बंद कर दिया, इसपर विचार करने की बात है । नल जल आपका वार्ड में और टोले में चलेगा, लेकिन विद्यालयों में नहीं चलेगा । वह कॉलेज हो, उच्च विद्यालय हो, मध्य विद्यालय हो, प्राथमिक विद्यालय हो जिसमें सारे लोगों के बच्चे बड़ी संख्या में पढ़ते हैं, अगर वह चापाकल नहीं रहेगा तो उस विद्यालय में कैसे नल का जल पहुंचेगा इसका जवाब सरकार को देना चाहिए और मैं मांग करता हूँ कि सरकार अभी चापाकल को जारी रखे तब तक जब तक नल का जल पूर्ण नहीं हो जाता है ।

सभापति(डा0 रंजु गीता) : अब आप समाप्त करें । माननीय सदस्य श्री केदार प्रसाद गुप्ता प्रारंभ करें । आपका समय 5 मिनट है ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : सभापति महोदय, मैं 2018-19 के लिए पेश नगर विकास एवं आवास विभाग के कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हूँ इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ ।

(व्यवधान)

सभापति(डा0 रंजु गीता) : अब आप बैठ जाइये ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : माननीय उप मुख्यमंत्री जी-सह-वित्त मंत्री जी के कुशल प्रबंधन से 2018-19 का जो बजट आया है वह बहुत ही सराहनीय है । इस बजट में भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र भाई मोदी ने जो न्यू इंडिया बनाना चाहते हैं और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी जो भारत और बिहार बनाना चाहते हैं जिसमें सबका साथ सबका विकास के तहत हर व्यक्ति को रहने के लिए अपना घर हो, हर व्यक्ति को घर तक आने और जाने के लिए सड़क हो, नाला हो, हर व्यक्ति को घर में बिजली हो, हर व्यक्ति के घर में शौचालय हो इस तरह का भारत और बिहार बनाना चाहते हैं । महोदया, हर किसान के खेतों में पानी पटाने के लिए अलग से बिजली की व्यवस्था हो ऐसा हमारे नरेन्द्र भाई मोदी और नीतीश

कुमार जी और सुशील कुमार मोदी जी की जोड़ी चाहते हैं । हर बेरोजगार नौजवानों के हाथ में काम हो । हर महिला को अपना खाना बनाने के लिए गैस कनेक्शन । महोदया, मजदूरों, किसानों को गरीबों को उसके लिए कम पैसे पर प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा का व्यवस्था किया गया है ताकि जो मजदूर किसी कारणवश किसी घटना में उसकी मृत्यु हो जाती थी और उसका परिवार बर्बाद हो जाता था । अब दो लाख रूपया जब उनको मिलेगा तो उनका परिवार गति से आगे चलता रहेगा । महोदया, इसी के तहत जिस तरह के हमारे प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी जिस तरह का बिहार बनाना चाहते हैं उस बिहार में हमारे माननीय नगर विकास मंत्री जी ने अपना हम धन्यवाद देते हैं कि जिस तरह से राज्य के नगर के विकास के लिए कई कार्य कर रही है- नगर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, स्वच्छता प्रदान कराना, शौचालय बनवाना सरकार की प्राथमिकता है । महोदया, राज्य के शहरी क्षेत्र में बसे हुए प्रत्येक परिवार को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 1422 वार्डों में कार्य प्रारंभ हो चुका है और अब तक कुल 1 लाख 1 हजार 578 घरों में नल जल उपलब्ध कराया जा चुका है ।

क्रमशः

टर्न-21/अशोक/13.03.2018

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : क्रमशः महोदया, स्वच्छ भारत मीशन के तहत शहर के आगामी चार वर्षो में सरकार द्वारा 6 लाख 10 हजार 462 शौचालय बनाये जाने हैं जिसमें अभीतक एक लाख 60 हजार 191 व्यक्ति का शौचालय का निर्माण पूरा कर लिया गया है । और एक लाख 59 हजार 878 .. .

सभापति(डॉ0 रंजू गीता) : माननीय सदस्य अब आप समाप्त करेंगे ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : महोदया, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि कुढ़नी विधान सभा क्षेत्र के चार पंचायत, कुढ़नी, तुर्की और मनिहारी केरमा जो पूरा पूरी शहरनुमा है मैं नगर विकास मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि नगर पंचायत का दर्जा दिलावें साथ ही साथ मैं मुजफ्फपुर नगर निगम के तहत मझोली खैतल पंचायत, खबड़ा पंचायत और नगमानपुर पंचायत जो आता है, उनको नगर निगम के अन्दर रखा जाय । हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नगर विकास योजना फिर से चालू किया जाय चूंकि पिछली बार प्रभारी मंत्री जी के अध्यक्षता में जो नगर विकास की कमिटी बनी हुई थी उसमें जो उनका घोषणा हुई थी कि जो-जो योजना स्वीकृत हुई है उसका क्रियान्वयन किया जाय मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ और मैं मांग करता हूँ कि मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के दो करोड़ से बढ़ाकर चार करोड़ रूपया कर

दिया जाय और मैं मांग करता हूॅ कि सीतामढ़ी जिला के बैरगनिया नगर परिषद् में महान स्वतंत्रता सेनानी बंशी चाचा के नाम एक पार्क बनाकर उसमें उनका आदम कद प्रतिमा लगाया जाय ।

सभापति(डॉ0 रंजू गीता) : माननीय सदस्य, श्री गुलाब यादव ।

श्री गुलाब यादव : सभापति महोदया, आज मैं नगर विकास, नगर आवास योजना का कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोल रहा हूॅ नगर विकास, नगर आवास योजना का विरोध में बात कर रहा हूॅ । विभाग के विरोध में बात कर रहा हूॅ । आज सरकार इतनी ताली थपथपा रही है, सिर्फ तालियों की सरकार है या जमीन पर भी काम को देखेंगे । नगर विकास मंत्री कहते हैं कि इतने विकास करते हैं हम शहर बसायेंगे, हमलोग बहुत सारे बड़े शहर में रहते आये हैं बचपन से, बड़े शहर में रहना जानता हूॅ और यहां कहते है कि स्मार्ट सिटी बनायेंगे, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए नगर विकास और सरकार के पास ऐसे कोई इंजीनियर हैं ? कितने इंजीनियर सरकार में बहाल हैं? कि बतायें कि हमने स्मार्ट सिटी बनायेंगे, हम लोग भी पूणे में रहते हैं, महाराष्ट्र में बड़े-बड़े नगरपालिका हैं, महानरगर पालिका है एक एक व्यवस्था हैं, हमारे मधुबनी जिला में झंझारपुर नगर पंचायत है, वहीं हमारा घर भी है । जब बरसात आता है तो गाड़ी नहीं पार हो पाता है, आदमी कहां से जा पायेंगे, कभी बच्चे बीमार हो जाते हैं तो हॉस्पीटल नहीं जा पाते हैं । न नाली है वहां पर और न नल की व्यवस्था है और हमारा यही कहना है कि झंझारपुर नगर पंचायत को नगर परिषद् में तबदील करें । हमेशा कहता है कि सरकार जो है न घोटालों की सरकार है, कहते हैं कि पैसा सब गरीब का पैसा पूरे देश भर का पैसा जो मोदी है, ललित मोदी और नीरव मोदी पूरे देश के गरीब का पैसा लेकर विदेश में चले गये हैं यह सरकार गरीबों की सरकार नहीं है, यह सरकार अमीरों की सरकार है । अदानी और अम्बानी का सरकार मोदी जी कहते हैं बिजय माल्या जी इतने पैसे लेकर भाग गये उनका क्या हुआ ? सब पैसा गरीब जनत, सब गरीब जनता का पैसा लेकर चला गया । ये कहते हैं मंत्री जी आप सरकार का पीठ मत थपथपाइये, काम देखिये कहते है कि नगर विकास मंत्री है, विकास कैसे होते हैं थोड़ा हमलोंगो से पूछ लेंगे,सलाह जरूर देंगे आपको, हम भी शहर में रहे हैं शहर मैन्टेन कैसे होते हैं यह भी बतायेंगे आपको जरूर, परसनली आप हम से पूछ लेंगे । यहां शोचालय घोटाला है, सृजन घोटाला है, कितना घोटाला है, आज तक सरकार में एक भी काम बिना घोटाला के नहीं हुआ है, अभी एक सो दस में कहे थे कि कचरा का बाल्टी खरीदने के लिए,...

सभापति(डॉ0 रंजू गीता) : माननीय सदस्य श्री संजीव चौरसिया ।

श्री संजीव चौरसिया : सभापति महोदया, 2018-19 के लिए पेश नगर विकास एवं आवास विभाग के कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । मैं तो सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि वास्तव में जो परिलक्षित हो रहा है पूरा बिहार के दृष्टि से शहर का पूरा अवलोकन यानी कि विपक्ष के जब योजना में कुछ दृष्टिकोण नहीं होता तो परियोजना परिलक्षित नहीं होता है । आज अनेकों प्रकार की योजनायें जो चल रही है पूरे बिहार की दृष्टि से (व्यवधान) आवास विभाग की दृष्टि से ? सभापति महोदया, मैं बतलाना चाहूंगा कि अलग-अलग प्रकार की योजनायें दिखलाई दे रही है, आज पहले की योजना दृष्टि में और अभी के बिहार की योजना के परिप्रेक्ष्य में पूरे देश या विश्व में जाने के पश्चात् यह दिखता है कि बदलता हुआ बिहार किधर जा रहा है । जो पूरा परिदृश्य पटना के दृष्टि से जानते हैं कि विपक्ष के हमारे मित्रों ने भी इस चीज को अवलोकन किया और अवलोकन करने का काम किया है, इंगित करने का काम किया है, पटना में परिवर्त्तन की दृश्य दिखलाई देती है, आप ध्यान में होगा, अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी सदन में थे, वास्तव में जब उस समय आंदोलन करते थे कंकड़बाग मे जिस प्रकार से जल जमाव की जो स्थिति हुआ करती थी आज की स्थिति क्या है ? किस प्रकार से पूरा जल जमाव दूर हो गया है । विकास का पूरा पैमाना दिख रहा है । मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री बनने के बाद आवास विभाग के शहरी विकास की दृष्टि से जल जमाव पटना में जब जब हुये हैं, लगातार इन्होंने बैठक करने का काम किया, उसका परिणाम यह हुआ कि पटना में जल जमाव दूर हुआ है, वह निश्चित दिखलाई दिया है । यह भी आह्वान करन चाहूंगा कि स्मार्ट सिटी की दृष्टि से मित्रगण, विधायकगण ने जिस प्रकार से बातों को रखा है, इस बात का अवलोकन एवं इस बात को सोचना भी चाहिये कि स्मार्टसिटी में जहां जहां बनने की बात है वहां विधायक सम्मिलित हुये होंगे उससे पूरी योजना की दृष्टि से दिखलाया गया होगा तो उनको देख कर लगना चाहिये कि कार्य किस तरह से आगे बढ़ रहा है । केन्द्र का प्रतिनिधित्व उसमें दिया जा रहा है और यह भी मांग करते हैं कि स्मार्ट सिटी की दृष्टि से माननीय विधायकों को सम्मलित भी किया जाय, पर स्मार्ट सिटी की जहां-जहां योजना दी गई है, उस योजना को भी आप अगर देंखें होंगे तो उस योजना के बारे परिकल्पना दिखाया गया होगा शायद उस परिकल्पना को भी आप वृहत में देंखने का प्रयास करें । जो विकास दिख रहा हैं, उस विकास मे जीने का प्रयास करें तो विकास चारो ओर दिखलाई देगा । मैं यह बतलाना चाहूंगा आज, माननीय सभापति महोदया, कि सबसे बड़ा विषय है कि

गरीबों की बात करने वाली पार्टी किस प्रकार से गरीब के बारे में सोचती है, इसके बारे में सबसे बड़ा एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जब अपनी सरकार थी उस समय मलिन बस्ती नीति, 2012 बनी, उस समय प्रेम कुमार जी नगर विकास मंत्री थे तो वास्तव में उस समय गरीबों का बचाव किया कि गरीब को अगर पुरस्थापना की बात करते हैं, हटाने की बात करते हैं तो उसकी योजना सरकार के माध्यम से बननी चाहिये, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि वास्तव में बिहार राज्य फुटपाथ बिक्रेता नियमावली, 2017 और बिहार राज्य फुटपाथ बिक्रेता स्कीम, 2017 के अन्तर्गत 81 हजार 461 स्ट्रीट वेंडर को अवलोकित करते हुये 8 हजार 480 स्ट्रीट वेंडर को पहचान पत्र निर्गत किया गया है और 482 स्ट्रीट वेंडर जोन बनाने की योजना सरकार की है यानी सरकार यह विचार करती है कि गरीबों को हटाने की बात करेंगे तो उसकी योजना, एक नीति बना कर देने का काम करेंगे । यह सरकार की गरीबों की नीति है जो परिलक्षित करती है अपने स्कीम के माध्यम से, उन स्लम बस्तियों के बारे में सरकार कही है कि अगर योजना देनी है सरकार को तो उनको बसाने की भी बात करनी है उनके बारे मे आवास की योजना करके बसाने की बात करेगी । मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि स्मार्ट सिटी बात करने पर, अदालतगंज जो मेरे नेहरू नगर, कमला नेहरू नगर जो मेरे विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है, 8 से 9 हजार से ज्यादा मतदाता केवल हैं के बारे में भी सरकार विचार किया है कि मल्टी स्टोरेज बनाकर बसाने की बात करेंगे ? इस बात को अवलोकन करनी चाहिए ....

सभापति(डॉ0 रंजू गीता) : अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री संजीव चौरसिया : विषय को समाप्त करने दीजिये, इस बात को अवलोकन करनी चाहिये कि उस दृष्टि से गरीबों के लिय विचार वर्त्तमान सरकार ने किया है । आज उस मास्टर प्लान की बात सरकार ने की है, इस बात पर ध्यान देनी चाहिये, मास्टर प्लान में सरकार यह चाहती है कि सेटेलाईट सिटी है, सेटेलाईट सिटी के बारे में विचार करेगी, सेटेलाईट सिटी के बारे में विकास की बात करेगी, यह वर्त्तमान सरकार ही यह बात कर सकती है कि जितने प्रकार की योजनायें हैं उसको हरएक लेवल पर बात करेगी आप जहां भी देखेंगे तो सेटेलाईट सिटी का विकास हो, यह सरकार की परियोजना की दृष्टि से हैं, सरकार ने यह माना है कि राजनीतिक एवं सांस्कृति धरोहर की दृष्टि से नगर का विकास करते हैं तो सांस्कृतिक धरोहर को जोड़ने कीबात करते हैं । क्रमशः

टर्न-22/ज्योति/13-03-2018

क्रमशः

श्री संजीव चौरसियाः सरकार ने इस चीज को माना है कि हम राजनीतिक, सांस्कृतिक धरोहर की दृष्टि से भी नगर का विकास करते हैं, तो सांस्कृतिक धरोहर को भी जोड़ने की बात करेंगे और बुद्ध का बुद्ध पार्क की बात को भी अवलोकित करने का काम किया है । बस एक बात, मैं कहना चाहूँगा कि क्षेत्र की दृष्टि से जो सबसे बड़ा विषय अभी चल रहा है, माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि अगर विकास की परियोजना पटना में परिलक्षित करना चाहते हैं, तो दीघा-राजीव नगर के विकास का वह निराकरण करें और उसका सौल्यूशन निकले ताकि वहां की जनता को राहत अपने प्रकार से मिले । जलापूर्ति योजना की दृष्टि से भी और क्षेत्र की दृष्टि से बताना चाहेंगे कि पानी की समस्या जो है सी.डी.ए. कॉलोनी, पाटलिपुत्र, दीघा अलग अलग क्षेत्रों में, नेहरुनगर में इसको भी दूर करने का काम करे । बहुत बहुत धन्यवाद ।

सभापति (डा0 रंजू गीता): श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन, आपका समय 5 मिनट है और आप 5 मिनट में आप अपना वक्तव्य पूरा करेंगे क्योंकि आपके वक्तव्य के बाद सरकार का उत्तर होना है ।

श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीनः आज नगर विकास एवं आवास विभाग के भोला यादव जी के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । नगर विकास का पैमाना होता है और नगर मानक होता है किसी भी देश के विकास का मानक, अगर उस देश की राजधानी में घूम लिया जाय, तो अनुमान लगाया जा सकता है, किसी राज्य के विकास का पैमाना । अगर राज्य की राजधानी में घूम लिया जाय, तो पैमाना हो सकता है । जिला का पैमाना- जिला मुख्यालय में अगर घूम लिया जाय, शहर में घूम लिया जाय, तो उसका मानक और पैमाना तय किया जा सकता है और अब बिहार की बात करें कि बिहार किस स्थिति में है, तो देश के और विदेश के विभिन्न सर्वेक्षण संस्थानों ने यह बताया है कि भारत में 10 सबसे गंदे शहरों में कोई शहर है, तो बिहार की राजधानी पटना का नाम दिया गया है । जबकि उसमें चार सौ शहरों को लिया गया है, उसमें एक से दस में यह पटना शहर आता है । कभी तीन में आता है, कभी चार में आता है और यह स्थिति है । दूसरा हाईकोर्ट के जस्टिस एक नहीं कई बार बताते हैं कि इस देश में पटना जैसी गंदी राजधानी मुझे नजर नहीं आती है । यह हाई कोर्ट के कई जस्टिस ने कई बार कह दिया है । तीसरी बात कि जब भारत सरकार स्मार्ट सिटी बनाने की बात करती है और 100 शहरों का चयन किया जाता है, जब उसके मानकों को देखा जाता है, तो भारत

सरकार कहती है कि बिहार का एक भी शहर मानक में खरा नहीं उतरता है, इसको स्मार्ट सिटी नहीं बनाया जा सकता है, यह तो दुर्दशा है । आखिर इस दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है ? हम यह गौर करते हैं कि पिछले 15 सालों से शासन किसका है इस राज्य मे, 15 सालों से शासन किसका है जो विकास की बात करते हैं । इस विभाग की जिम्मेदारी किन लोगों के पास थी, जो विकास की बात करते हैं, जो मानको पर खरा नहीं उतरता है, तो हम उस सूची में देखते हैं कि इस विभाग की जिम्मेदारी पूर्व उप मुख्यमंत्री तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के पास कई बार थी, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि विभाग की जिम्मेदारी किसके पास थी, फिर हम देखते हैं अश्विनी कुमार चौबे उनके पास थी, फिर हम देखते हैं उसके बाद किसकी जिम्मेदारी थी, तो फिर हम देखते हैं, जो अभी कृषि मंत्री बने हुए हैं प्रेम कुमार जी, उनके पास थी, फिर अभी देख रहे हैं कि अभी किसके पास यह जिम्मेदारी है, तो अभी फिर देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास है, 15 साल से शासन कर रहे हैं और आज भी सबसे गंदे शहरों में जब राजधानी है, तो बाकी शहरों की चर्चा बेकार है करना, इसीलिए क्या उम्मीद की जाय कि 15 साल, 20 साल में, कब सही होगा ।

सभापति (डा0 रंजू गीता): अब आप कनक्लुड करें ।

श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन: दूसरी बात मैड्म यहाँ यातायात की व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं किया गया । यहाँ 10 प्रतिशत लोग यहाँ के शहरों में ट्रैफिक में फंसे होते हैं । यहाँ मुक्ति धाम का काम नहीं हुआ । किसी तरह का विकास नहीं हुआ है । समय आपने कम दिया है, इसलिए मैं अपने क्षेत्र से ही शुरु करुंगा, जो मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना थी, इसको सरकार ने बंद कर दिया है । ये एम.एल.एल. को पंगु बना दिया है । एक रोड, एक सड़क, एक नाली, शहर में एम.एल.ए. नहीं बना सकता है, इसलिए इसको पुनः चालू किया जाना चाहिए । दूसरी बात 2014 में योजना स्वीकृत राज्य योजना से किया था, चार साल में यह विभाग उस योजना का टेण्डर नहीं कर सका । चार योजना 2014 में मैंने सैंक्शन कराके दिया था, उसको चार साल में इसका टेण्डर नहीं किया जा सका समस्तीपुर नगर परिषद में । दूसरा बिहार राज्य जल पर्षद के द्वारा एक साल से अधिक हो गया है, जो पूरे शहर में समस्तीपुर में शुद्ध पेय जल देना है, आज एक साल होने को है, अभी तक उसकी गति 10 प्रतिशत भी उपलब्धि नहीं है, दूसरी तरफ सम्राट अशोक भवन जो कहते हैं, पूरे बिहार में बनाना है समस्तीपुर में जमीन देने के बाद प्रस्ताव दिया हुआ है कई वर्षों से आज तक सम्राट अशोक भवन नहीं बन सका । आपलोग पार्क की बात कर रहे हैं । समस्तीपुर में कई बार प्रस्ताव पार्क के लिए दिया गया, तीन

एकड़ जमीन जिला मुख्यालय में है, आज तक पार्क नहीं बना सके, आपलोग विकास की बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि वहाँ इनका एक आवास बोर्ड है, आवास बोर्ड की जमीन जिला मुख्यालय में है और मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग ने मांगा । आवास बोर्ड चार गुणा पैसा मांगता है, जो कहाँ से उचित है । जनता की संस्था है आवास बोर्ड, जनता की संस्था है मेडिकल कॉलेज, फिर चार गुणा पैसा किस लिए मांगा जा रहा है । इसपर विचार किया जाना चाहिए और समस्तीपुर के तमाम ड्रेनेज, सिवरेज सिस्टम बिल्कुल ध्वस्त हो चुके हैं । वहां जल निकासी की व्यवस्था नहीं है । इसीलिए उस व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाय । समस्तीपुर में चारों तरफ जो ताजपुर रोड है, तिरहुत एकेडमी है, गोला रोड तमाम तरफ जल जमाव बना रहता है, इसलिए वहाँ पर उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए । अभी पी.एच.ई.डी. डिपार्टमेंट से मैड्म जुड़ा हुआ मामला है । पूरे शहर में जो पेय जल की व्यवस्था की जा रही है, जो पाईप दिया जा रहा है, वह एकदम घटिया सामग्री दी जा रही है, जो स्पेसिफिकेशन पी.एच.डी. डिपार्टमेंट ने दिया था, उस स्पेसिफिकेशन पर काम नहीं हो रहा है, इन्होंने पेंटेड पाईप की बात की थी । कहीं छः लग रहा है, कहीं चार लग रहा है, एकदम घटिया निर्माण हो रहा है । इसकी जॉच अगर करनी है तो मैं, समस्तीपुर जिला के समस्तीपुर प्रखंड का उदाहरण देता हूँ कि विभाग जॉच कर लें । बाद में, दो चार वर्षों के बाद एक बड़ा घोटाला पी.एच.ई.डी. विभाग में आयेगा और दूसरी तरफ आपदा विभाग की भी मांग की गयी है । आपदा विभाग कहता है कि हम तुरत सुविधा उपलब्ध करायेंगे और राशि देंगे, एक साल हो गया, हमारे यहाँ दस लोग मरे हैं, आज एक साल में इनलोगों ने पैसा तक नहीं दिया है, इसलिए अध्यक्ष महोदय यह विभाग सिर्फ विकास की बात कर रहा है.....

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

और काम कुछ नहीं कर रहा है । नगर विकास पिछले 15 वर्षों में बद से बदतर स्थिति में चला गया है, इसीलिए हम कहना चाहेंगे कि ठीक से काम करे और किसी तरह जुमलेवाजी नहीं करे, बिहार की सरकार की तरह जुमलेवाजी नहीं करे और जिम्मदार लोगों को इस पद पर दिया जाय । विभाग में पदाधिकारी जिम्मेदार लोगों को दिया जाय । मैं पुनः आसन के प्रति आभार प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : अब सरकार का उत्तर होगा ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक सेकेंड आपसे कहना चाहते हैं ।

अध्यक्ष : आपका नाम पार्टी ने भेजा नहीं है ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, नाम से मतलब नहीं है । सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि गया में चूँकि नगर विकास विभाग बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है और पी.एच.ई.डी. और एक मिनट .....

अध्यक्ष: बात कहिये न ?

श्री अवधेश कुमार सिंह: पूरी कॉलोनी में बुडको से जॉच करायी गयी नाली बनाने का, पी. एच.ई.डी.- इसी सदन में सेलवे गांव में गंदा पानी है, काला पानी आता है, उसकी जॉच करायी गयी । सदन में सरकार ने स्वीकार किया ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री,लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ।

श्री विनोद नारायण झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जल कितना महत्वपूर्ण है किसी को बताने की जरुरत नहीं है । जल ही जीवन है । यह हम वर्षों से जानते रहे हैं लेकिन पहले तो लोग जल पीने में इन सब बातों का ध्यान नहीं रखते थे । नदी-नाले, नदी-पोखरे, तालाब कहीं से भी जल पीने का रिवाज था । बाद के दिनों में यह परम्परा बनी कि चापाकल का जल शुद्ध है कि जल जो धरती के नीचे है, वह एक शुद्ध जल है लेकिन समय बीतता गया, जानकारियॉ आती गयीं, अब यह जानकारी आयी कि धरती के अंदर भी जो जल है, वह शुद्ध नहीं है । वह जल भी अशुद्ध है, अनेक तरह की अशुद्धियां हैं । सतह का जो जल है, उसमें तो कम अशुद्धियॉ हैं लेकिन हम जो बाहर से उसे गंदा कर देते हैं, बाहर से उसमें जो कचरा डालते हैं या और तरह से गंदा करते हैं, इससे भले ही सतह का जल अशुद्ध हो रहा हो लेकिन मूल रुप से धरती का जो जल है, ग्राउन्ड वाटर जो है, वह धीरे धीरे उसकी शुद्धता पर प्रश्नचिन्ह लगने लगा, तो दुनिया में इस बात के लिए चर्चा होने लगी कि क्या चाहिए लोगों के स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के मानक में क्या आवश्यक है, तो स्वास्थ्य खास कर डेवलपिंग कंट्रीज में जो शुद्ध जल की आवश्यकता ज्यादा है क्योंकि उनकी बीमारियों पर अधिक बीमारी गंदे माहौल में रहने के कारण और शुद्ध जल नहीं पीने के कारण अनेक बीमारियॉ आती हैं । अभी कुछ दिन पहले एक यूनिसेफ की रिपोर्ट आयी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : मंत्री जी आप अपनी बात कहिये समय कम है ।

श्री विनोद नारायण झा, मंत्री : समय कम है । इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, यह रिपोर्ट आयी कि हालत यह है कि 50 हजार रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष बीमारियों में खर्च करता है, वह बचाया जा सकता है यदि लोग स्वच्छ वातावरण में रहें और शुद्ध शुद्ध पानी पियें, तो एक परिवार को 50 हजार की बचत हो सकती है बिहार जैसे राज्य में और भारत के गरीब राज्यों में तो हम समझ सकते हैं कि यह हमारी

जी.डी.पी. को बढ़ाने वाला है और कई तरह से लोगों की गरीबी को दूर करने वाला है और अमीरी की ओर ले जाने वाला है । बड़ी भारी मजबूती हो जायेगी, यदि स्वच्छ जल उन्हें मिल जाता है । तरह तरह से शुद्ध जल देने का प्रयास हुआ। 40 लीटर पहले शुद्ध जल का मानक माना जाता था कि एक परिवार के लिए, एक व्यक्ति के लिए दिन में 40 लीटर जल की आवश्यकता होती है ।

क्रमशः

टर्न–23/13.3.2018/बिपिन

श्री विनोद नारायण झा,मंत्रीः क्रमशः .. 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो विकास की उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ उसे 55 लीटर कर दिया गया लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब सात निश्चय की घोषणा की तो उन्होंने कहा कि बदलती हुई परिस्थिति में विकास के नए मानकों में अब 70लीटर प्रति व्यक्ति जल की आवश्यकता है और इसीलिए हर घर में उन्होंने जल पहुंचाने का निश्चय किया । कुछ दिन पहले मैं दिल्ली गया था और कई पेयजल मंत्री वहां थे । सभी लोग इसे वाह–वाह कर रहे थे, आश्चर्यचकित थे कि बिहार जिसकी आय बहुत नहीं है, बहुत अमीर राज्यों में नहीं किया जाता है, उसने निश्चय किया कि हर परिवार को हम आने वाले 2020 से पहले हर घर नल देंगे और जो अमीर राज्य हैं वो निर्णय नहीं कर सके । यह बहुत आश्चर्य की बात है और उनलोगों से कहा गया कि आपलोग भी तय करिए । आपके पास यदि बजट है तो निर्णय करिए और सबसे बड़ी आवश्यकता है लोगों को शुद्ध जल देने की, शुद्ध जल पहुंचाने की । यदि बिहार कर सकता है तो बाकी राज्य क्यों नहीं कर सकते । बाकी राज्यों को नसीहत दी जा रही है और बिहार का नकल और अनुसरण किया जा रहा है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कई विभागों में बांट कर हमें हर घर नल का जल देना है । हमारा विभाग जो पी.एच.इ.डी. विभाग है, वह 3378 ग्राम पंचायतों में जल देने की जिम्मेवारी है । इसमें 6 हजार, 4 हजार, 46,365 वार्ड हैं जिसको विभाग की ओर से हर घर नल से जल दिया जाएगा । इसमें 62 लाख परिवार हैं जिसे शुद्ध जल विभाग की ओर से दिया जाएगा । इसमें अभी तक तीन लाख एक्तालीस हजार जल देने में हम सफल हो चुके हैं ।

अध्यक्ष महोदय, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे राज्य में तीन तरह के गंभीर संकट है पानी के मामले में – एक तो फ्लोराइड है, आर्सेनिक है और लौह अव्यव है बड़ी मात्रा में । जो बिहार के जिले हैं, उसमें 13 जिले आर्सेनिक प्रभावित हैं, 11 जिले फ्लोराइड प्रभावित हैं और 9 जिले एक्सेस लौह से प्रभावित

हैं और लौह से प्रभावित वाला जिला तो नौ जिला में तो आर्सेनिक और फ्लोराइड तो जिलों के कुछ इलाकों में है लेकिन लौह प्रभावित तो पूरा-का-पूरा जिला है नौ जिला, इसीलिए बिहार के 20,117 वार्ड अत्यधिक लौह प्रभावित हैं । इसी तरह, 4510 वार्ड फ्लोराइड प्रभावित हैं । 2038 वार्ड आर्सेनिक प्रभावित हैं । विभाग ने एक संपूर्ण कार्य योजना बनाई है कि हम आने वाले दो वर्षों में 2020 से पहले हर घर जो विभाग की जिम्मेवारी है उसको हम शुद्ध जल दे दें । इसके लिए हमारे विभाग ने व्यापक तरीके से कार्य योजना बनाने का काम किया । सबसे बड़ी आवश्यकता थी अपने इंजीनियरों की क्षमतावर्द्धन की, अपने अधिकारियों के उनके जो मैनेजमेंट स्कील थे उनको बढ़ाने की क्योंकि बड़ा महत्वाकांक्षी निर्णय सरकार ने लिया था और इस आधार पर विभाग ने सबसे पहले आई.आई.टी., खड़गपुर में जलापूर्त्ति योजनाओं के डिजाइन और उसके मोनिटरिंग के लिए 102 अभियंताओं को वहां भेजा । इसी तरह, आई.आई.एम. जो भारत की प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान हैं, वहां प्रोजेक्ट और कंटेंट मैनेजमेंट के लिए भेजा और अब हमने उसकी संपूर्ण कार्य योजना बनाने का काम किया । बिहार की जितने भी आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित वार्ड हैं वह 4510 हैं, उसमें से 2979 योजनाओं की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, 2305 के टेंडर निकल गए हैं, 735 निविदा का निष्पादन हो गया है और 191 का कार्य पूर्ण होते हुए दीख रहा है । इसी तरह, आर्सेनिक में 2038 वार्ड जो हैं उसमें 1178 वार्ड की योजनाएं हमने स्वीकृत कर ली है और 1145 की निविदा हमने आमंत्रित कर ली है और 367 जगहों पर हमारा कार्य प्रारंभ हो गया है । हम आज आपको घोषणा करना चाहते हैं कि 2018-19 के वित्तीय वर्ष के अंत होते-होते हम बिहार से आर्सेनिक फ्लोराइड मुक्त जल हर घर को दे देंगे । जितने भी घरों में आर्सेनिक और फ्लोराइड हैं उनको हम इसी 2018-19 के वित्तीय वर्ष के अंत होते-होते हम हर घर नल का जल पहुंचा देंगे । लौह का इलाका थोड़ा बड़ा है । इसीलिए एक वर्ष ज्यादा समय हमें दीजिए । यह 2719 है। उसमें 3192 पर हमने उसकी योजना स्वीकृत कर ली है ।

(व्यवधान)

1152, सुनिये, विकास की बात भी सुनिए । 1152 निविदा आमंत्रित हो चुकी है और आपको भरोसा देते हैं, पूरे सदन को भरोसा देते हैं कि चुनाव से पहले 2020 तक हम इस राज्य से सारे लौह को भी हम मुक्त कर देंगे और सारा लौहमुक्त कर बिहार को देने का काम करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी चुनौती है । यह नीतीश कुमार जी ने और सुशील मोदी के नेतृत्व में इस चुनौती को अवसर में बदलने का निर्णय लिया है ।

भारत के लोग इसका नकल करेंगे । इसका नकल करेंगे कि किस तरह इस राज्य ने, इस सरकार ने, जिसके वित्तीय संसाधन कम थे, उसने निर्णय लिया और दो साल, तीन साल के अंदर लौह, आर्सेनिक और फ्लोराइड मुक्त जल अपने बिहार की जनता को दे दिया । माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त ....

(व्यवधान)

आप घबराएं नहीं, आपके इलाके की बात है, आपके इलाके के हर घर में गफूर साहब, विभाग जल देगा । पंचायत की जरूरत नहीं है । हर घर में विभाग जल देगा, आप परेशान न हों । इसके लिए बड़ी-बड़ी योजनाएं चल रही हैं । यह तो हमारी योजनाएं हैं जिसे हम दे रहे हैं । इसके अतिरिक्त, हमारी मल्टी विलेज योजनाएं हैं । आज सदानन्द बाबू नहीं हैं, उनको बताते हुए, उनको खुशी होती कि उनके 141 बसावट है, 141 गांव में हम इस वर्ष 2018 में, 2019 भी नहीं जाने देंगे, 2018 में उनके कहलगांव और पीरपैती इलाके में 71हजार परिवार को शुद्ध जल दे देंगे । इसीलिए आप धैर्य रखिए । विकास को देखते रहिए और इसको समझने का प्रयास करिए कि विकास के कैसे मानक चल रहे हैं और इतना ही नहीं ....

(व्यवधान)

इसके अतिरिक्त गोगाघाट, सिलाव और नवादा के रजौली में हमारा काम चल रहा है और हम आपको जानकारी देते हैं, सब लोग परेशान रहते हैं अध्यक्ष महोदय कि बिहार में जो टावर दीख रहा है, वह सफेद हाथी बना हुआ है । हम फिर घोषणा करते हैं, इस वर्ष बिहार में 1007 टावर हैं, 2018 के अंत तक हम हर का टेंडर कर देंगे इसी वित्तीय वर्ष में । डी.पी.आर. का काम शुरू कर देंगे और उसके आसपास जो बसावट हैं, उन सारे बसावटों को हम नल से जल देंगे, यह गैरगुणवत्ता प्रभावित इलाके की बात है । उनकी गुणवत्ता प्रभावित हो या न हो, विभाग बीस हजार वार्ड जो पहले से हमारे परंपरागत रूप से योजनाएं चल रही हैं, वह या तो जलमीनार के रूप में हैं या सीधी जलापूर्त्ति योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं में हम इसी वित्तीय वर्ष में हर घर नल का जल देने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, जो योजनाएं बनी हैं, उन योजनाओं में वृद्धि हम काम करने का काम करेंगे । आप परेशान न हों ....

(व्यवधान)

आप परेशान न हों । एक बात कहना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय । बिहार के वर्ल्ड, विश्व बैंक के सहयोग से हम बिहार के दस जिलों को एक-एक करके उनको शुद्ध जल देने का काम कर रहे हैं । ये जिले हैं- पटना, नालंदा,

नवादा, बेगुसराय, बाढ़, सारण, मुंगेर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर और पश्चिम चंपारण । दो जिले हम और शामिल करने के लिए मधुबनी और जहानाबाद को शामिल करने की प्रक्रियाधीन है । उसको हम विश्व बैंक के सहयोग से देंगे । अध्यक्ष महोदय, एक जानकारी, विरेन्द्र बाबू, एक जानकारी और देते हैं । आप घबराएं नहीं, धैर्य न खोएं। आपके लिए जानकारी देता हूं । जानकारी यह है कि पूरे, गफूर साहब, आप धैर्य रखिए, पूरे बिहार में इन योजनाओं के अतिरिक्त हमारे 38 प्रयोगशाला चल रहे हैं विरेन्द्र भाई, 38 प्रयोगशाला हैं, और हर जिला मुख्यालय में जल जांच की प्रयोगशाला है जो प्रति महीने 300 सैंपुल जमा कर जांच करती है और आपसे हम आग्रह करते हैं, आपको भी निवेदन करते हैं, आप लोगों को जागरूक करिए और उनको कहिए कि हमारे प्रयोगशाला में जाएं और जांच कराएं कि वह जो जल पीते हैं, वह शुद्ध है कि नहीं । उसमें आर्सेनिक की क्या मात्रा है, उसमें स्वास्थ्य के लिए क्या मात्राएं हैं लेकिन आप जनता के काम की बात तो करेंगे नहीं ...

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: महोदय, मेरी व्यवस्था है ।

अध्यक्ष : मंत्री जी, सिद्दिकी साहब, कुछ व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: माननीय मंत्रीजी पता नहीं क्यों गुस्से में हैं कि मुक्का भी दिखा रहे हैं और थप्पड़ भी दिखा रहे हैं और विपक्ष की तरफ ही नहीं दिखा रहे हैं बल्कि आसन की तरफ भी थप्पड़ दिखा रहे हैं, यह तो कहिए उनसे ।

टर्न-24/कृष्ण/13.03.2018

अध्यक्ष : माननीय सिद्दिकी साहब, आप सबों के और इतने माननीय सदस्यों के रहते हुये आसन इतना मजबूत है कि इसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है ।

श्री विनोद नारायण झा, मंत्री : महोदय, सिद्दिकी साहब तो वरिष्ठतम सदस्यों में से एक हैं लेकिन बोलने के तरीके अपने-अपने हैं, किसी से लिया नहीं जा सकता है । ये जब बोलते रहते हैं तो कई बात मुझे पसंद नहीं आती रहती है । लेकिन यह बात अलग है । इसके अतिरिक्त एक बात और मैं कहता हूं कि जिलों के अतिरिक्त हमने सब-डिविजनों में भी प्रयोगशाला खोलने का निर्णय लिया है । माननीय सदस्य भाई वीरेन्द्र बाबू, आप इसको जानियें, आप जनता के बीच में रहते हैं । हमने जिला के अतिरिक्त 76 सब-डिविजनों में प्रयोगशाला खोलने का निर्णय लिया है । सात प्रयोगशाला हमने खोल भी लिया है । पूरी बात सुनिये । महोदय मुझे दुख होता है, कल मैं सोनपुर गया था, वहां प्रयोगशाला वालों ने बताया कि लोगों को अभी जानकारी नहीं है । जब पूरे लोग आते नहीं हैं जल जांच कराने के लिये, जरा आपलोग इसको प्रचारित कीजिये, कौन-सा जल पीते हैं, आप परिवार की 50 हजार

रूपये की सलाना इनकम आप बढ़ा सकते हैं, यदि वह स्वच्छ जल पियें और स्वच्छ वातावरण में रहें । यह आपकी भी जिम्मेवारी है । आप उन्हें प्रेरित कीजिये कि वे हमारे प्रयोगशाला में आयें, जो जल वे पीते हैं उस जल में कितनी गंदगी है, कितनी गड़बड़ियां हैं, यदि आप यह करने में सफल होंगे तो आप जनता का बहुत बड़ा काम करेंगे । इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर होगा । माननीय मंत्री,नगर विकास एवं आवास विभाग ।

सरकार का उत्तर

श्री सुरेश कुमार शर्मा,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा कई कार्य किये जा रहे हैं । कार्यरत नगर निकायों की संख्या 141 है, 12 नगर निगम, 43 नगर परिषद् है और 86 नगर पंचायत कार्यरत है । सभी नगर निकायों के कुल वार्डों की संख्या 3,377 है ।

महोदय, नगर परिषद् छपरा को नगर निगम में उत्क्रमित किया गया है । 08 नगर पंचायत - बख्तियारपुर, बरबीघा, दाउदनगर, महनार, बिक्रमगंज, बांका, ढाका और फतुहां को नगर परिषद् में उत्क्रमित किया गया है । 03 नगर पंचायत- बारसोई, सुरसंड एवं हरनौत का गठन किया गया है । सिंघिया, त्रिवेणीगंज, बौंसी, गिरियक, बिरौल, बहेड़ी, बरौनी और रहुई कुल 08 नगर निकायों का गठन की प्रक्रिया चल रही है । वर्ष 2017 में नगर निकायों की आम निर्वाचन के पश्चात् सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को राज्यस्तरीय उन्मुखीकरण सह कार्यशाला 5-6 दिसंसबर,2017 को पटना में आयोजित की गयी थी तथा उन्हें विभाग की योजनायें एवं उनके कार्यान्वयन हेतु प्रशिक्षित किया गया है ।

महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के सात निश्चय में से 3 निश्चय इस विभाग से संबंधित है । मुख्यमंत्री शहरी पेय जल निश्चय योजना : राज्य के शहरी क्षेत्रों में वासित प्रत्येक परिवार को शुद्ध नल का जल उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना लागू है । इस कार्य योजना के अन्तर्गत स्थानीय नगर निकाय, बिहार राज्य जल पर्षद्, बुडको और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा नगर निकायों में प्रत्येक परिवार को नि:शुल्क नल जल संयोजन उपलब्ध कराया जा रहा है । इस योजना के इस योजना के कार्यान्वयन हेतु 250, 500, 1000 एवं 1500 घरों के लिये गुणवत्ता प्रभावित और गुणवत्ता अप्रभावित क्षेत्रों के लिये अलग-अलग मॉडल प्राक्कलन तैयार किया गया है । साथ ही इस योजनान्तर्गत निर्बाध जलापूर्त्ति हेतु ओवरहेड वाटर टैंक का भी प्रावधान किया गया है ।

महोदय, इसमें हमलोग एक अल्पकालीन योजना लिये है जिससे त्वरित पानी दिया जायेंगे और दूसरा, लौंग टर्म में वाटर टावर बना करके पाईप लाईन विस्तारीकरण करके उसको पानी दिया जायेगा ।

महोदय, भू-जल के अतिरिक्त दोहन से बचाव हेतु निजी बोरिंग पाईप से जलापूर्त्ति प्राप्त करनेवाले घरों को इस योजना के तहत हाउस कनेक्शन नहीं देने का निर्देश दिया गया है । महोदय, जो लोग अपना बोरिंग समरसेबुल किये हुये हैं, उनको अभी हम रोक रहे हैं और यह ज्यादातर स्लम एरिया में हम जिस भी तरह से होगा, हम जल्द से जल्द पानी मुहैया कराने की व्यवस्था कर चुके हैं । इस योजना के तहत सभी नगर निकायों को कुल 3,377 वार्डों में लक्षित 3,360 वार्डों में भी अबतक 2,080 वार्डों के लिये निविदा निकाली जा चुकी है कुल 1523 वार्डों में काम प्रारंभ हो चुका है । अबतक कुल 1 लाख 5 हजार 542 घरों को नल जल संयोजन उपलब्ध कराया जा चुका है ।

मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना के तहत राज्य के शहरी क्षेत्रों वासित परिवारों को पक्की नाली-गली के जोड़ने हेतु मुख्यमंत्री शहरी नाली -गली पक्कीकरण निश्चय योजना लागू है । नगर निकायों द्वारा वार्डों में वार्ड सभा की अनुशंसा के आधार पर दीर्घकालीन योजना तैयार की गयी है । प्राथमिकता सूची के अनुसार योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जा रहा है ।

योजना के प्रथम चरण में कच्ची नाली-गलियों की पक्कीकरण की योजनायें ली जा रही हैं तथा द्वितीय चरण में पूर्व से निर्मित नाली-गली के जिर्णोद्धार की योजनायें लिये जाने का निर्णय लिया गया है ।

इस योजना के तहत सभी नगर निकायों के कुल 3,377 वार्डों में से 3,340 वार्डों में निविदा निकाली जा चुकी है । कुल 2,692 वार्डों में काम प्रारंभ हो चुका है । इस योजना के तहत अबतक कुल 3,340 योजनायें पूर्ण हो चुकी है जिससे 1 लाख 28 हजार 577 घरों की पक्की नाली-गली आच्छादित हो चुकी है।

महोदय, शौचालय निर्माण घर का सम्मान निश्चय ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

अध्यक्ष : सभी माननीय सदस्य, कृपया शांति तो बनाये रखिये ।

श्री सुरेश कुमार शर्मा,मंत्री : नगर निकायों की स्थिति ..

श्री ललित कुमार यादव, : महोदय, क्यों सदन का सदन जाया किया जा रहा है ।

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार शर्मा,मंत्री : नगर निकाय क्षेत्र में स्थित शौचालय विहीन घरों में शौचालय की व्यवस्था के लिये योजना की मंजूरी प्रदान की गयी है । इसके अंतर्गत 2019-20

तक कुल 6 लाख 10 हजार 462 शौचालय बनाया जाना है । भारत सरकार द्वारा व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिये प्रति शौचालय 4 हजार रूपया एवं राज्य सरकार द्वारा 8 हजार रूपया सहायता अनुदान दिय जा रहा है ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर सी0पी0आई0-माले द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया)

महोदय, अब तक 1 लाख 68 हजार 953 व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है एवं 1 लाख 59 हजार 467 ईकाई निर्माणाधीन है ।

(व्यवधान)

1240 सामुदायिक शौचालय का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है एवं 2972 निर्माणाधीन है । 77 सार्वजनिक शौचालय का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है जबकि 23 निर्माणाधीन है ।

महोदय, मुख्यमंत्री आदर्श निकाय प्रोत्साहन योजना के तहत नगर निगम, मुंगेर को निगमों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार दिया गया है । नरगर परिषद,हाजीपुर एवं लखीसराय को नगर परिषदों की श्रेणी में क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार दिया गया है । नगर पंचायत, चकिया एवं बोधगया को नगर पंचायत की श्रेणी में क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार दिया गया है । नगर निगम को 5 करोड़, नगर परिषद् को 3 करोड़ एवं नगर पंचायत को 1 करोड़ की पुरस्कार राशि दी जा रही है ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के सभी माननीय सदस्यगण ने सदन से बहिर्गमन किया)

महोदय, नाला निर्माण में राज्य के शहरी क्षेत्रों में बड़े आउट फॉल ड्रेनेज का निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है । इस क्रम में सहरसा, सासाराम, फुलवारी शरीफ फेज-2 एवं 3, सुपौल एवं दरभंगा शहरों में जल-जमाव की समस्या को दूर करने हेतु स्ट्रौम वाटर ड्रेनेज योजना स्वीकृत की गयी है जिसका कार्यान्वयन बुडको द्वारा किया जा रहा है ।

इसके अतिरिक्त 18 नगर निकायों यथा- नवादा, मसौढ़ी, शेखपुरा, रक्सौल, बक्सर, डुमरा, बिहिया, चकिया, सिलाव, जगदीशपुर

क्रमशः

टर्न-25/सत्येन्द्र/13-03-18

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री (क्रमशः) अरेराज, हिसुआ, जनकपुर रोड, राजगीर, ढाका, वारसलीगंज, परसा बाजार एवं टेकारी में बड़े आऊट फॉल नाला निर्माण योजना

स्वीकृत की गयी है । मधुबनी एवं मधेपुरा में स्टौर्म वाटर ड्रेनेज योजना स्वीकृति की प्रक्रिया में है । अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल, आई0एस0बी0टी0 की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसका निर्माण 302.34 करोड़ की लागत से बुडको द्वारा किया जा रहा है । सम्पूर्ण राशि राज्य योजना से व्यय की जा रही है । राज्य के 39 शहरों में बस स्टैंड निर्माण की योजना स्वीकृत है । 18 शहरों में निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा 13 शहरों में निर्माण कार्य प्रगति पर है । छठ पर्व, 2017 में आयोजन सफलतापूर्वक किया गया । दीदारगंज से दीघा तक विभिन्न छठ घाटों पर साफ-सफाई, घाटों का निर्माण, गंगा नदी में बैरिकेटिंग, चेंजिंग रूप, अस्थायी शौचालय, अस्थायी पेयजल व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, पहुंच पथ एवं वाच टावर की व्यवस्था की गयी थी । पूर्व से 50 शहरों में सम्राट अशोक भवन की योजना स्वीकृत थी । चालू वित्तीय वर्ष में 22 शहरों में इस योजना की स्वीकृति दी गयी है । शेष शहरों में अगले वित्तीय वर्ष में योजना स्वीकृत की जायेगी । इसके अतिरिक्त मॉडल प्राक्कलन तैयार किया गया है, जो उत्तर बिहार के शहरों के लिए 139.33 लाख तथा दक्षिण बिहार के शहरों के लिए 135.26 लाख का है । महोदय, राज्य के नगर निकायों में परम्परागत स्ट्रीट लाईट के स्थान पर एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट लगाने हेतु ई0ई0एस0एल0 के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया गया है । ई0ई0एस0एल0 द्वारा नगर निगमों एवं नगर परिषदों के साथ सर्विस लेवल एग्रीमेंट हस्ताक्षरित किया गया है । इसके आधार पर आरा में 17 तारीख को 7 हजार स्ट्रीट लाईट लगाकर के उसको हमलोग स्वीच ऑन करने जा रहे हैं । इस योजना में पहले परम्परागत लाईट को एल0ई0डी0 लाईट से बदला जायेगा । इसके बाद जहां पोल है परंतु लाईट नहीं है, वहां एल0ई0डी0 लाईट लगायी जायेगी । अंतिम चरण में जहां लाईट की आवश्यकता है परन्तु पोल भी नहीं है, वहां पोल सहित एल0ई0डी0 लाईट लगायी जायेगी । महोदय, शवदाह गृह । राज्य के नगर निकाय में शवदाह गृह निर्माण हेतु नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत के लिए अलग अलग मॉडल प्राक्कलन तैयार कराया गया है, जिसमें नगर निगमों के लिए 02 फर्नेस का विद्युत शवदाह गृह तथा 06 pyre वाला परम्परागत शवदाह गृह, नगर परिषदों के लिए 01 फर्नेस का विद्युत शवदाह गृह तथा 04 pyre वाला परम्परागत शवदाह गृह तथा नगर पंचायतों के लिए 02 pyre वाला परम्परागत शवदाह गृह का प्रावधान किया गया है । महोदय, परम्परागत शवदाह गृह निर्माण हेतु गोरखपुर में कम प्रदूषण वाले संयत्र का अध्ययन करने के लिए विभागीय अभियंताओं का दल भेजा जा रहा है । तत्काल 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में विद्युत शवदाह गृह निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है,

जिस पर अगले वित्तीय वर्ष में कार्रवाई की जायेगी और भी बड़े शहर जो होंगे उसमें भी विद्युत शवदाह गृह बनाने की योजना हमलोग बना रहे हैं । जो इससे बड़े शहर हैं, उसमें भी हम विद्युत शवदाह गृह देंगे । महोदय, पटना शहर में परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ करने के क्रम में कुल 26 करोड़ 6 लाख 74 हजार रू0 की योजना पूर्व से स्वीकृत एवं कार्यरत है । सासाराम शहर में ट्रैफिक लाईट की स्वीकृति गृह विभाग के माध्यम से दी गयी है । राज्य के अन्य नगर निगमों में ट्रैफिक लाईट के योजना की स्वीकृति गृह विभाग द्वारा दी जायेगी तथा इसका कार्यान्वयन बुडको द्वारा कराया जायेगा । पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार, पटना मास्टर प्लान, 2031 के क्रियान्वयन हेतु पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार का गठन किया गया है जो कार्यरत है। भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा भू-सम्पदा अधिनियम, 2016 के तहत बिहार भू-सम्पदा नियमावली, 2017 अधिसूचित किया गया है । इस अधिनियम एवं नियमावली का उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा, राज्य में रियल इस्टेट के क्षेत्र में लेन देन में निष्पक्षता लाना एवं ससमय परियोजनाओं के कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त करना है । बिहार राज्य आवास बोर्ड, गत वित्तीय वर्ष में बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा बेहतर वित्तीय अनुशासन ,बेहतर प्रबंधन, आय के नए श्रोत का सृजन, राजस्व संग्रहण में वृद्धि आदि अनेक उपायों के माध्यम से अपनी आय में उल्लेखनीय वृद्धि किया गया है । लीज-होल्ड से फ्री-होल्ड में सम्परिवर्त्तन, आवास बोर्ड की सम्पदाओं के आवंटियों को सम्पदाओं के लीज-होल्ड से फ्री-होल्ड में सम्परिवर्त्तन का विकल्प दिया गया है जिसमें आवंटी एक निश्चित राशि निबंधन विभाग द्वारा निर्धारित एम0भी0आर0 का 10 प्रतिशत राशि जमा कर संपदा को लीज होल्ड से फ्री होल्ड में सम्परिवर्त्तन करा सकते हैं । आवासीय सह व्यावसायिक सम्पदाओं का ई-ऑक्शन के माध्यम से आवंटन, पटना स्थित बहादुरपुर एवं लोहियानगर, 25 व्यावसायिक एवं आवासीय सह व्यावसायिक सम्पदाओं का आवंटन ई-ऑक्शन के द्वारा किया जा रहा है । गंगा घाट, पटना में 20 घाटों का सौंदर्यीकरण, 12 गंगा घाटों का सौंदर्यीकरण हो चुका है, 04 घाट का कार्य अंतिम चरण में है । पटना शहर अन्तर्गत बेऊर, करमलीचक एवं सैदपुर एस0टी0पी0 योजना का स्वीकृति एवं कार्य प्रारम्भ है । पटना शहर अन्तर्गत बेऊर, करमलीचक एवं सैदपुर सीवरेज नेटवर्क योजना स्वीकृत है । पूरे राज्य में 20 सीवरेज एवं एस0टी0पी0 की योजना में कुल 4166.97 करोड़ रू0 स्वीकृत है । सीवरेज एवं नालों से निकलने वाले जल को शोधित कर कृषि/सिंचाई में उपयोग की कार्य योजना तैयार की जा रही है । विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा कार्य योजना पर विचार किया गया है । महोदय, ये जितना भी हम आउट फॉल

ड्रेनेज जो बना रहे हैं , इसको हम किसी न किसी नहर से जोड़ने की प्रक्रिया कर रहे हैं क्योंकि यह जो है उसमें एस0टी0पी0 लगाकर उसमें साफ पानी देंगे जिससे कि वह किसानों के लिए उपयुक्त होगा और उससे सिंचाई का काम होगा । स्मार्ट सिटी योजना, नगर निगम भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर एवं बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी के रूप में स्वीकृति प्राप्त है, इसके लिए एस0पी0भी0 का गठन हो चुका है । महोदय, इसमें माननीय विपक्ष के सदस्य लोग बोल रहे थे तो अभी तो केवल भागलपुर का एस0पी0भी0 बना है और उसका कार्यान्वयन के लिए हम काम किये हैं तीन तो अभी प्रक्रिया में है तो अभी स्मार्ट सिटी का काम जो प्रक्रिया में है, ये सब बन जाने के बाद में हम उसको त्वरित ढंग से उस काम कराने जा रहे हैं । पटना मेट्रो के बारे में लोगों का कहना था पटना मेट्रो का जो पुराना हमारा डी0पी0आर0 था वह केन्द्र सरकार ने उसको पास नहीं किया । मेट्रो का हम नया उसको बनाने का हमने तैयारी किया है और अप्रैल में हमें उम्मीद है कि हमारा राईटस के द्वारा और एन0आई0टी0 के द्वारा हमारा डी0पी0आर0 जो तैयार हो रहा है और अप्रैल में हमें मिल जायेगा, उसके बाद हम उसकी प्रक्रिया जो उसका फायनेंस का व्यवस्था कर के हम उसका जल्द से जल्द वह काम आरम्भ करेंगे और उसको हम चाहते हैं कि इस फायनेंसियल ईयर में मैं सदन को बतलाना चाहता हूँ कि मेट्रो का काम मुख्यमंत्री के निर्देश में और उनके उपस्थिति में शिलान्यास भी इस साल करवायेंगे। (क्रमशः)

टर्न-26/मधुप/13.03.2018

...क्रमशः ....

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : आवास निर्माण - महोदय, शहरी क्षेत्र में आवास-विहीन परिवारों को कम से कम 30 वर्गमीटर का पक्का आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। अब तक 1,24,856 घरों में निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है । इसमें 45,658 घरों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा चुका है । 2022 तक इस नीति के आलोक में 5 लाख आवास का निर्माण प्रस्तावित है । शहरी गरीब आवास उपलब्ध कराने हेतु सरकार निरंतर प्रयत्नशील है ।

अभी माननीय सदस्य लोग बोल रहे थे, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हम रोड पर इनक्रोचमेंट को हटा रहे हैं लेकिन उसको बसाने के लिये भी वेंडिंग जोन बनाने का जगह आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उसमें हम उनको बसायेंगे । कोई गरीब जो ठेला चलाता है, उसको हम वेंडर्स का आइडेंटिफिकेशन करके उनको आइडेंटिटी कार्ड भी निर्गत कर रहे हैं और उनको हम बसायेंगे भी ।

इनक्रोचमेंट को हटाना सरकार का यह धर्म बनता है लेकिन हम पूरा प्रयत्न करके उनको बसाने का भी काम करेंगे ।

इतना ही नहीं सर, हम आश्रय भी बना रहे हैं । आश्रय इसलिये बना रहे हैं कि जो गरीब बाहर से काम करने आते हैं शहर में, उनके लिये 50 बेड का हमारा मुजफ्फरपुर में और यहाँ भी हमने पटना में भी वैसा आश्रय बनाया है, जिसमें बेड वगैरह सब उनका लगा दिया गया है और वह 3-4-5 दिन रहकर वहाँ काम करेंगे। महिला के लिये भी और पुरूष के लिये भी ऐसे आश्रय बनाने का निर्णय ही नहीं लिया गया है बल्कि कई एक शहरों में काम हमने शुरू कर दिया है जिसमें गरीब या मजदूर आकर जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, वह कुछ दिन वहाँ 2-4-5 दिन रह सकेंगे और उनके खाने के लिये भी सब्सिडाइज्ड रेट पर हमलोग इंतजाम कर रहे हैं, कैंटीन रहेगा जिसमें वे लोग खाना भी खा लेगा । उनकी पूरी व्यवस्था सरकार करने जा रही है । इस तरह से महोदय, हमलोगों का कई एक तरह का काम हो रहा है ।

महोदय, सबसे बड़ी समस्या जो बिहार में थी प्रशिक्षण देने का, लोग पढ़-लिख तो जाते थे, बी0ए0-एम0ए0 कर जाते थे लेकिन स्किल्ड नहीं होते थे । स्किल्ड नहीं होने से उनको जॉब अपोर्चुनिटी प्राइवेट या गवर्नमेंट में नहीं मिलता था। सरकार इसके लिये काफी प्रयत्नशील है और कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कृपया सब आदमी शांति से मंत्री जी का वक्तव्य सुनिये । इसमें सबके लिये कुछ न कुछ आयेगा ।

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : महोदय, इसमें हमलोग ट्रेनिंग की व्यवस्था काफी जगहों पर किये हैं, और भी इसको बढ़ा रहे हैं । मेसन ट्रेनिंग भी हम दे रहे हैं क्योंकि भूकम्पग्रस्त एरिया में मेसन को किस तरह से बिल्डिंग बनाना चाहिये, इसके भी ट्रेनिंग की व्यवस्था हमलोग कर रहे हैं । हमारे पास पैरा-मेडिकल स्टाफ नहीं हैं, हमारे बिहार में नर्सेज नहीं हैं, हमारे बिहार में सिलाई-कढ़ाई के काम करने वालों की कमी है, इस तरह का जो ट्रेनिंग हम दे रहे हैं तो उनको वहाँ से जॉब भी मिल रहा है, जॉब अगर नहीं मिल रहा है तो अपना भी कारोबार शुरू करके परिवार का भरण-पोषण कर सकते हैं । इस योजना के तहत सरकार काफी प्रयत्नशील है और इसमें हमलोग जो यह काम कर रहे हैं, इसमें कई एक तरह का और काम है । जैसे हमलोगों ने महिलाओं के लिये भी, कल ही मुजफ्फरपुर में महिला समूह, दीन दयाल प्रशिक्षण के माध्यम से उनको भी हम ट्रेंड कर रहे हैं और उनको 50 हजार रूपया बैंक से लोन दिलवा रहे हैं, कल भी हमने 10 आदमी को लोन दिलवाया है

कि वह महिला अपना कुछ कारोबार कर सकें । अन्य शहरों में भी हम यह काम करने जा रहे हैं कि वे प्रशिक्षित होकर अपना काम करेंगी ।

श्री अरूण कुमार सिन्हा : महोदय, हम सभी माननीय विधायकों की ओर से गुजारिश करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के बारे में भी माननीय मंत्री जी कुछ कहें ।

अध्यक्ष : सभी माननीय विधायकों की तरफ से या सभी शहरी क्षेत्र से आने वाले विधायकों की ओर से !

श्री संजय सरावगी : नहीं सर, सभी विधायकों की तरफ से । ग्रामीण क्षेत्र वाले माननीय विधायक भी तो शहर में रहते हैं ।

अध्यक्ष : बोलिये मंत्री जी । आप अपना वक्तव्य पूरा करिये । अब समय नहीं है, दो-तीन मिनट है, आप अपनी बात कह डालिये ।

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : महोदय, शहरी योजना की जो बात कर रहे हैं, यह तो विभाग का मामला है, मुख्यमंत्री जी का मामला है और माननीय सदस्यों की ओर से सदन में जो रखा गया है, उससे हम इनकार नहीं करते हैं लेकिन यह विषय मुख्यमंत्री जी का है और अलग से है ।

(व्यवधान)

महोदय, आवास के लिये हम और कुछ नहीं बोल सकते हैं, हम इतना ही कहेंगे कि हम आवास बोर्ड के द्वारा बहुत सारा मकान बनवाने जा रहे हैं पी0पी0पी0 मोड पर, जो आम लोगों को मिलेगा उसमें ये लोग भी एप्लाई करके और उनको बैंक लोन भी मिलेगा, वे लोग भी ले सकते हैं । इसमें क्या दिक्कत है, हमलोग इसको करायेंगे । आवास बोर्ड की तरफ से कई एक जगह मकान पी0पी0पी0 मोड पर बनाने जा रहे हैं। उसमें ये लोग एप्लाई करेंगे ।

महोदय, हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो निर्देशित किया गया, जो मार्गदर्शन दिया उसके आधार पर हम तेजी से काम कर रहे हैं, हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि 2018 में बिहार के सभी नगर निकाय का, जो पंचायत है, परिषद है, नगर निगम है, उसमें स्टाफ की जो कमी है, वह भी हम पूरा करेंगे और इसका टेक्निकल सेल भी हम बनाने जा रहे हैं । उसमें एक से एक अनुभवी इंजीनियर आ रहे हैं । हर विभाग से हम ई0ओ0 भी ले रहे हैं । जे0ई0 के लिये भी हम विज्ञापन करने जा रहे हैं। हम समझते हैं कि इस साल के अन्दर नगर विकास एवं आवास विभाग पूरे बिहार के अन्दर चमकते हुये दिखेगा ।

विपक्ष के माननीय सदस्य लोग तो अभी नहीं हैं लेकिन मैं उनसे विनम्र आग्रह करूंगा कि कटौती प्रस्ताव वापस करें, हमें सहयोग दें । जो हमारा बजट

है नगर विकास एवं आवास विभाग के लिये 2018-19 के व्यय वहन हेतु कुल रू044,13,58,67,000/- (चौवालीस अरब तेरह करोड़ अंठावन लाख सड़सठ हजार रू0)का उपबंध मॉग संख्या-48 के अन्तर्गत प्रस्तुत है । इसमें स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अलावे राज्य योजना एवं केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना शामिल है । इसमें स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के लिए रू017,78,58,67,000/-(सत्रह अरब अठहत्तर करोड़ अंठावन लाख सड़सठ हजार रूपये) तथा स्कीम व्यय के लिए रू026,35,00,00,000/- (छब्बीस अरब पैंतीस करोड़ रू0) का प्रस्ताव है ।

मैं सदन से अनुरोध करता हूँ कि नगर विकास एवं आवास विभाग के बजट प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की जाय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सरकार का उत्तर समाप्त हुआ । क्या माननीय सदस्य श्री भोला यादव अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''इस शीर्षक की मॉग 10 रूपये से घटाई जाय ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं ।

टर्न-27/आजाद/13.03.2018

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''नगर विकास एवं आवास विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए 44,13,58,67,000/- (चौवालीस अरब तेरह करोड़ अनठावन लाख सड़सठ हजार) रूपए से अनधिक राशि प्रदान की जाए ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 13 मार्च, 2018 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या-19 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 14 मार्च, 2018 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।